वैश्विक संवाद

12.1

अनेक भाषाओं में एक वर्ष में 3 अंक

पत्रिका

International Sociological Association

समाजशास्त्र पर बातचीत जिल ब्लैकमोर के साथ

जोहाना ग्रुबनेर

नए श्रम आंदोलन

डारियो एजेलिनी
सारा रेमुंडो
हिरोकी रिचर्ड वतनबे
वर्ना दिनाह क्यू. वियाजार

लैंगिक व्यवस्था की किस्में

सिल्विया वाल्बी, करेन शायर, मिके वेरलू, हेइडी गॉटफ्राइड, वैलेंटाइन एम.मोघदम, एसे कोकाबिकैक, अल्बा अलोंसो, इमानुएला लोम्बार्डो, रॉसेला सिसिया, रॉबर्टा गुएरिना, हीथर मैकरे, एनिक मैसेलॉट

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

रॉविन कॉनेल

स्मृति में मोना अबाजा

माइकल बुरावॉय
विनीता सिन्हा
ब्रायन टर्नर
सुआद जोसेफ
पॉल अमर
सैयद फरीद अलतास
सामी जुबैदा

भारत से समाजशास्त्र

सुजाता पटेल
राकेश एम. कृष्णन
स्नेहा गोले
सोइबम हरिप्रिया
शिरीन मिर्जा

खुला अनुभाग

> स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर स्त्रैण हिंसा की पहचान
> अमेरिकी राजनीति में नस्लवाद और पर्यावरण–विरोधीवाद

GD
अंक 12 / क्रमांक 1 / अप्रैल 2022
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

> सम्पादकीय

नवउदारवादी शासन के तहत उनके बाजारीकरण या अर्ध–विपणन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों और विज्ञान में दूरगामी परिवर्तन हो रहे हैं। *ग्लोबल डायलॉग* के इस अंक में हम इस विषय को अपने खंड 'टॉकिंग सोशियोलॉजी' में उठाते हैं। जिल ब्लैकमोर पिछले दशकों में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों द्वारा अनुभव किए गए गहन पुनर्गठन का अध्ययन कर रही हैं । इस साक्षात्कार में वह इन पुनर्रचनाओं, उन्हें प्रेरित करने वाली ताकतों के बारे में, और अकादमिक ज्ञान उत्पादन और ज्ञान–मीमांसा न्याय पर पड़ने वाले उनके प्रभावों के बारे में विस्तार से बताती हैं ।

पहली संगोष्ठी विविध श्रमिक आंदोलनों पर वैश्विक शोध सहयोग के कुछ हिस्सों को प्रस्तुत करती है। जबकि डारियो एजेलिनी दुनिया भर में श्रमिकों के आंदोलनों पर वर्तमान महामारी के प्रभाव की जांच करती है, जिसमें लिंग और नस्ल के पहलू शामिल हैं, सारा रेमुंडो फिलीपींस में उपनिवेशवाद के निशान और ट्रेड यूनियन संघर्षों पर इसके निरंतर प्रभाव की पड़ताल करती है। हिरोकी रिचर्ड वतनबे ने दिखाया कि जापानी अर्थव्यवस्था के विनियमन और उदारीकरण ने कैसे संघ के आयोजन और आज श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को आकार दिया है। वर्ना दिनाह क्यू वियाजर राजनीतिक और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया में ट्रेड यूनियनों के विकास और सुहार्तो शासन को उखाड़ फेंकने में उनकी भूमिका की जांच करती हैं ।

एक ओर, पाँच दशकों से अधिक समय से चल रहे पूंजीवाद के परिवर्तन ने कई देशों में लिंग व्यवस्था को प्रभावित किया है। दूसरी ओर, लिंग संबंधों, जीवन जीने के तरीकों और कल्याणकारी राज्य में चल रहे गहरे बदलावों ने सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित श्रम विभाजन, देखभाल की जिम्मेदारियों और मानदंडों और मूल्यों को चुनौती दी है। सिल्विया वाल्बी और करेन शायर, दोनों पूंजीवाद, संकट और लिंग के बीच संबंधों पर सैद्धांतिक और अनुभवजन्य अनुसंधान के विशेषज्ञ हैं, ने लिंग व्यवस्था की किस्मों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। यह विभिन्न देशों में लिंग संबंधों, व्यवस्थाओं और व्यवस्थाओं में अंतर और समानताओं का मानचित्रण करता है और हमारे समय की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। यह यह भी दर्शाता है कि कैसे पूंजीवाद की किस्में और कल्याणकारी राज्य लैंगिक व्यवस्थाओं को पुनर्गठित करने और पुर्नव्यवस्थित करने के विभिन्न तरीकों के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य' के खंड में लिंग और समाज पर इस प्रतिबिंब को एक अलग दृष्टिकोण से देखना जारी रखते हैं। पुरुषों के अध्ययन के अग्रणी और सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि रॉविन कॉनेल ने इस शोध स्ट्रैंड को फिर से देखा और विश्लेषण किया कि सामाजिक और वैज्ञानिक विकास ने कैसे मर्दानगी पर नए दृष्टिकोण को जन्म दिया।

बड़े दुख के साथ हमें मोना अबाजा के निधन के बारे में पता चला, जिनका 5 जुलाई, 2021 को निधन हो गया। इस अंक में, दुनिया भर के सहयोगियों और दोस्तों ने इस असाधारण समाजशास्त्री को विदाई दी।

इस अंक का देश फोकस, जो प्रमुख समाजशास्त्री और सामाजिक सिद्धांतकार सुजाता पटेल द्वारा आयोजित किया गया, भारत में आज के समाजशास्त्र में प्रभावशाली अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। स्थापित और युवा विद्वानों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचारों को साझा करके इस खंड में सहयोग किया है, जिसमें हिंसा, असमानता या भेदभाव जैसे मुद्दों से उनके समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य को कैसे चुनौती दी जाती है।

अपने 'खुले अनुभाग' में हमने आईएसए की पत्रिका *करेंट सोशियोलॉजी* के साथ सहयोग शुरू किया है । इयान कैरिलो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लवाद और पर्यावरण–विरोधीवाद पर काम करते हैं और मर्ना डॉसन, जो नारी हत्या की जांच करते हैं, ने *ग्लोबल डायलॉग* के व्यापक शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक दर्शकों के साथ अपने वैज्ञानिक कार्यों को साझा करने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया । ■

ब्रिगिट औलेनबैकर और **क्लॉस डोर्रे**,
वैश्विक सवांद के संपादक

> वैश्विक संवाद जी.डी. वेबसाइट पर अनेक भाषाओं में देखा जा सकता है।
> प्रस्तुतियाँ <globaldialogue.isa@gmail.com> पर भेजी जा सकती हैं।

> संपादक मण्डल

संपादक : ब्रिजिट ऑलनबॉकर, क्लॉस डोरे

सह–सम्पादक : राफेल डींडल, जोहाना ग्रबनर, वालिद इब्राहिम

सहयोगी सम्पादक : अर्पणा सुन्दर

प्रबंधन संपादक : लोला बुसुतिल, अगस्त बागा

सलाहकार : माइकल बुरावे

मीडिया सलाहकार : जुआन लेजाररगा

परामर्श संपादक :
साडी हनाफी, ज्योफी प्लीयर्स, फिलोमिन गुतिरेज, एलोइजा मार्टिन, सावाको शिराहेस, इजाबेला बरलिंस्का, तोबा बेन्सकी, चिह–जुए जेचेन, जेन फ्रित्ज, कोइची हासेगावा, हिरोशी इशिदा, ग्रेस खुनो, एलिसन लोकोन्तो, सुसन मेकडेनियल, एलिना ओइनास, लोरा ओसो कैसास, बंडाना पुर्कायस्था, रोहडा रेडॉक, मौनीर सैदानी, आयसे सकतांबर, सेली स्कालोन, नाजानीन शाहरोकनी।

क्षेत्रीय संपादक

अरब दुनिया : *(ट्यूनिशिया)* मौनीर सैदानी, फातिमा रधौनी, हबीब हज सलेम; *(लेबनान)* साड़ी हनाफी।

अर्जेन्टीना : मैगडालेना लेमस, जुआन परसिआ, दांते मार्चिसिओ।

बांग्लादेश: हबीबुल खोंड़कर, खैरुल चौधरी, फातेमा रेजिना इकबाल, हेलाल मोहिउद्दीन, मुमिता तंजीला, बिजॉय कृष्णा बनिक, सबीना शर्मीन, अब्दुर रशीद, एम. ओमर फारुक, मोहम्मद जहीरुल इस्लाम, सरकर सोहेल राणा, मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम, ए.बी.एम. नजमुस साकिब, ईशरत जहान ऑयमून, हेलल उद्दीन, मसुदुर रहमान, शमसुल आरेफिन, यास्मीन सुल्ताना, सैका परवीन, रुमा परवीन, सालेह अल ममून, एकरामुल कबीर राणा, शर्मिन अख्तर शप्ला, मोहम्मद शाहीन अख्तर।

ब्राजील : गुस्तावो तानिगुती, एंजेलो मार्टिन्स जूनियर, एंड्रेजा गली, दिमित्रि सर्बोन्सीनी फर्नाडीस, गुस्तावो दिअस, जोसे गुइराडो नेटो, जेसिका मज़िजनी मेंडिस।

फ्राँस/स्पेन : लोला बुसुतिल

भारत : रश्मि जैन, मनीष यादव, राकेश राणा।

इंडोनेशिया : हरि नुग्रोहो, लूसिया रतीह कुसुमादेवी, फिना इट्रियती, इंदेरा रत्ना इरावती पट्टिनसारानी, बेनेडिक्टस हरि जूलियावान, मोहम्मद शोहीबुद्दीन, डोमिंगगस एलसीड ली, एंटोनियस एरियो सेतो हार्डजाना, डायना तेरेसा पाकासी, नुरुल ऐनी, गेगेर रियांतो, आदित्य प्रदान सेतियादी।

ईरान : रेयहाने जावदी, नियाश डॉलाती, सैयद मोहम्मद मुतालेबी, एलहम शुशत्राजिदे।

कजाकस्तान : अइगुल जाबिरोवा, बायन स्मागमबेट, आदिल रोदियोनोव, अल्माश त्लेसपयेवा, कुआनिश टेल, अलमागुल मुस्सीना, अकनूर ईमानकुल, मदियार एल्दियारोव।

रोमानिया : रलुका पॉपेस्कू, राइसा–गेब्रियला जमीफिरेस्कू, इरिना एलेना आयन, बियांका मिहायला, एलीना अलेक्सजेंड्रा नितोयू, रुक्सान्द्रा पादुरारु, ऐना– मारिया रेनेतिया, मारिया व्लासेनु।

रूस : ऐलेना ज्द्रावोम्यस्लोवा, डारिया खोलोडोवा।

ताईवान : वान–जू ली, ताओ–युंग लु, यू–वेन लिओ, त्सुंग–जेन हंग, पो–शुंग होन्ग, यी–शुओ हुआंग, यून–येन शेन, शियेन–यिंग शियेन, यू–चिआ चेन।

तुर्की : गुल कोरबासियोग्लू, इरमक एवरेन।

*इस साक्षात्कार में **जिल ब्लैकमोर** ने पिछले दशकों में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के गहन पुनर्गठन, उन्हें चलाने वाली ताकतों और अकादमिक ज्ञान उत्पादन और महामारी न्याय पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की।*

*यह संगोष्ठी वैश्विक विचारों से लेकर जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में विशेष संघ संघर्षों तक, दुनिया भर में कई **श्रमिक आंदोलनों और संघर्षों** को संबोधित करती है।*

***लिंग व्यवस्था की किस्मों** के बारे में इस संगोष्ठी में शामिल लेख वैश्विक विश्लेषण के लिए आवश्यक मैक्रो स्तर पर लिंग संबंधों पर नए दृष्टिकोणों पर चर्चा करते हैं।*

GD

सेज प्रकाशन की उदार ग्रांट से
वैश्विक संवाद का प्रकाशन संभव है।

> इस अंक में

संपादकीय 2

> समाजशास्त्र पर बातचीत

उद्यमी विश्वविद्यालय और महामारी अन्याय
जिल ब्लैकमोर के साथ एक साक्षात्कार
जोहाना ग्रुबनेर, ऑस्ट्रिया द्वारा 5

नए श्रम आंदोलन

कोविड–19 महामारी और वर्ग संघर्ष
डारियो एजेलिनी, मैक्सिको द्वारा 8

फिलीपीन्स में लड़ाका श्रम संगठन
सारा रेमुंडो, फिलीपीन्स द्वारा 10

जापान में संघों और श्रम बाजार का अविनियमन
हिरोकी रिचर्ड वतनबे, जापान द्वारा 12

सुहार्तो के शासन के प्रति इंडोनेशियाई श्रमिकों का प्रतिरोध
वर्ना दिनाह क्यू. वियाजार, इंडोनेशिया द्वारा 14

> लैंगिक व्यवस्था की किस्में

लैंगिक व्यवस्था का भविष्य
सिल्विया वाल्बी, यूके और करेन शायर, जर्मनी द्वारा 16

क्या लिंग व्यवस्था की नई किस्में उभर रही हैं?
सिल्विया वाल्बी, यूके द्वारा 18

परिवार में समाहितः रूढ़िवादी लिंग व्यवस्था
करेन शायर, जर्मनी द्वारा 20

क्या हम यूरोप में लिंग व्यवस्था में बदलाव देख रहे हैं?
मिके वेरलू, नीदरलैंड्स द्वारा 22

सार्वजनिक लिंग व्यवस्थाएंः अभिसारी छितराव
हेइडी गॉटफ्राइड, यूएसए और करेन शायर, जर्मनी द्वारा 24

लिंग व्यवस्था, राजनीति और विश्व –व्यवस्था
वैलेंटाइन एम.मोघदम द्वारा 26

तुर्की पितृसत्तात्मक राज्य के निर्धारक
एसे कोकाबिकैक, यूके द्वारा 28

एक दक्षिणी यूरोपीय लिंग व्यवस्था?
अल्बा अलोंसो और इमानुएला लोम्बार्डो, स्पेन और रॉसेला सिसिया, यूके द्वारा 30

बहुत दूर का संकट? कोविड–19 पश्चात् यूरोपीय संघ की लिंग व्यवस्थाएं
रॉबर्टा गुएरिना, यूके, हीथर मैकरे, कनाडा और एनिक मैसेलॉट, न्यूजीलैंड द्वारा 32

> सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

आग से खेलनाः पुरुषत्व का समाजशास्त्र
रॉविन कॉनेल, ऑस्ट्रेलिया द्वारा 34

> स्मृति में

मोना अबाजा को श्रद्धांजलि (1959–2021)
माइकल बुरावॉय, विनीता सिन्हा, ब्रायन टर्नर, सुआद जोसेफ, पॉल अमर, सैयद फरीद अलतास और सामी जुबैदा द्वारा 37

> भारत से समाजशास्त्र

परिचयः भारतीय समाजशास्त्र में नई दिशाए
सुजाता पटेल, स्वीडन द्वारा 40

मध्य भारत में जनजातीय भूगोल का विखंडन
राकेश एम. कृष्णन, भारत द्वारा 42

नारीवादी प्रतिच्छेदनः नए दृष्टिकोण
स्नेहा गोले, भारत द्वारा 44

भारयुक्त क्षेत्रः हिंसक स्थलों में समाजशास्त्र का क्रियान्वयन
सोइबम हरिप्रिया, भारत द्वारा 46

नगरीय भारत में कलंक और जाति श्रम
शिरीन मिर्जा , भारत द्वारा 48

> खुला अनुभाग

डाटा अंतराल स्त्रैण हिंसा की पहचान और रोकथाम में बाधा डालता है
मिर्ना डावसन, कनाडा द्वारा 50

अमेरिकी राजनीति में नस्लवाद और पर्यावरण–विरोधीवाद
इयान कैरिलो, यूएसए द्वारा 52

"क्या अर्थव्यवस्था, राजनीति और नागरिक समाज के साथ–साथ हिंसा चौथा संस्थागत क्षेत्र है?।"

सिल्विया वाल्बी एवं करेन शायर

> उद्यमी विश्वविद्यालय और महामारी अन्याय

जिल ब्लैकमोर के साथ एक साक्षात्कार

जिल ब्लैकमोर पीएचडी शिक्षा में अल्फ्रेड डीकिन प्रोफेसर, कला और शिक्षा संकाय, डीकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया और सामाजिक विज्ञान अकादमी की फेलो हैं। वे वैश्वीकरण, स्कूल और उच्च शिक्षा नीति, और शासनय अंतरराष्ट्रीय और अंतरसांस्कृतिक शिक्षा, नेतृत्व और संगठनात्मक परिवर्तन, अनुसंधान मूल्यांकन और महामारी न्याययय स्थानिक रीडिजाइन और नवीन शिक्षाशास्त्र, और शिक्षकों और शिक्षाविदों के काम पर नारीवादी दृष्टिकोण से शोध करती हैं। हाल के प्रोजेक्टों ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र गतिशीलता, पहचान, अपनेपन और जुड़ावय चीन और भारत में स्नातक की रोजगार योग्यता के लिए नियोक्ता दृष्टिकोण और स्कूल स्वायत्तता सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। एक पूर्व प्रोजेक्ट का *डिसरपटिंग लीडरशिप इन द एंट्रेप्रेनुरिअल यूनिवर्सिटीः डिसइंगेजमेंट एंड डाइवर्सिटी* (ब्लूम्सबरी, 2022) में प्रकाशन किया जाना है। प्रो. ब्लैकमोर शिक्षा, लिंग समानता और विविधता नीति से संबंधित सलाहकार समितियों और वैधानिक प्राधिकरणों में रहीं हैं। उन्होंने ओईसीडी, सरकारों और निजी और पेशेवर संगठनों को नीतिगत सलाह प्रदान की है, और मूल्यांकन ढांचे का विकास किया है। प्रो. ब्लैकमोर डीकिन सेंटर फॉर रिसर्च इन एजुकेशनल फ्यूचर्स एंड इनोवेशन की प्रथम निदेशक, शिक्षा में ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ रिसर्च की अध्यक्ष और ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की वर्तमान उपाध्यक्ष हैं।

यहां उनका साक्षात्कार **जोहाना ग्रुबनेर**, जोहान्स केप्लर विश्वविद्यालय, लिंज, ऑस्ट्रिया में पीएचडी शोधकर्ता और ग्लोबल डायलॉग के सहायक संपादक द्वारा किया गया है।

जिल ब्लैकमोर

जेजीः आप पिछले 30 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के विशाल पुनर्गठन का अध्ययन कर रही हैं। ये पुनर्गठन क्या थे, किन ताकतों ने उन्हें प्रेरित किया, और अकादमिक ज्ञान उत्पादन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा?

जेबीः ऑस्ट्रेलियाई और अंतर्राष्ट्रीय सरकारों ने विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से कसकर जोड़ने की मांग की है, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में 1990 के बाद इस क्षेत्र में 39 विश्वविद्यालयों के एकीकरण के साथ हुई। लोक प्रशासन के नए उपागमों दृष्टिकोणों और बाजारों को बढ़ावा देने वाली नवउदारवादी नीतियां एंग्लोफोन राष्ट्रों में व्यापक रूप से फैल रही थीं और वे इसी समय विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रही थीं। तीन दशकों के दौरान, विश्व स्तर पर विश्वविद्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीयकरण, प्रबंधकीयवाद, विपणन, वित्तीयकरण, और अब डिजिटलीकरण द्वारा सक्षम डेटाफिकेशन की प्रक्रियाओं का अनुभव किया है। कुलपतियों (वीसी) और अधिष्ठाताओं ने क्रमिक पुनर्गठन के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्ति अर्जित की है और इसने 1990 के दशक के बाद से निर्वाचित डीन और स्कूल के प्रमुखों को नियुक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिया है। उसी समय, इस दावे के आधार पर कि बदलती भू–राजनीति और नीतिगत अस्थिरता के प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालयों को चुस्त होने की आवश्यकता है, वरिष्ठ प्रबंधन के ऊपरी स्तरों का तेजी से विस्तार हुआ है। विश्वविद्यालयों को विशेष पाठ्यक्रमों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षण के लिए वित्त पोषित किया जाता है। कम सरकारी फंडिंग के कारण, ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने विवेकाधीन आय के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर तेजी से भरोसा किया है, जिससे विपणन में काफी निवेश हुआ है और शिक्षण से अनुसंधान का क्रॉस–सब्सिडीकरण हुआ है।

संगठनात्मक पुनर्गठन को दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के समाधान के रूप में देखा गया है लेकिन इसके प्रभावों का मूल्यांकन कभी नहीं किया गया है। शैक्षणिक मंडलों को अब केवल गुणवत्ता आश्वासन की जिम्मेदारी देने के साथ, नीति और बजट के संबंध में प्रबंधकीय शक्ति के केंद्रीकरण ने अकादमिक प्रशासन की कॉलेजिअल प्रथाओं को दरकिनार कर दिया है। उच्च कार्यभार और निर्णय लेने में भूमिका की कमी पर शिक्षाविदों द्वारा महत्वपूर्ण मोहभंग व्यक्त किया जाता है। शैक्षणिक कार्यबल के आकस्मिककरण और उच्च शिक्षण भार के माध्यम से संस्थागत लचीलापन हासिल किया गया है। इसने विशेष रूप से उन महिलाओं को प्रभावित किया, जो अक्सर अनुबंध पर थीं और शैक्षणिक कार्यबल के निचले स्तर पर संकेंद्रित थीं। 2010 में अनुसंधान मूल्यांकन के प्रारम्भ के साथ, ज्ञान

> >

उत्पादन पर इन प्रवृत्तियों का व्यापक प्रभाव यह है कि जो गिना जा सकता है (उदाहरण के लिए, मेट्रिक्स) या जिसका व्यावसायीकरण हो सकता है, वह अधिक मूल्यवान है; इस प्रकार, अकादमिक प्रथाओं को परिमाणीकरण और मापने योग्य और तत्काल आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करके आकार दिया गया है।

जेजी: क्या आप एक व्यापक से उद्यमी विश्वविद्यालय में रूपांतरण के प्रभावों, विशेष रूप से महिला शिक्षाविदों और नारीवादी ज्ञान उत्पादन के लिए, के बारे में बात कर सकती हैं?

जेबी: 1990 के दशक में चूंकि नीतिगत फोकस अनुसंधान क्षमता निर्माण से वैश्विक रैंकिंग और अनुसंधान मूल्यांकन के साथ 2000 के दशक में गुणवत्ता और उत्कृष्टता की ओर बढ़ गया है, कुलपतियों ने शिक्षण और अनुसंधान को प्राथमिकता देकर प्रत्येक विश्वविद्यालय को विशिष्ट बनाने का प्रयास किया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के मध्य और भीतर अधिक अंतर हो गया। इसने एक व्यापक विश्वविद्यालय से उद्योग, सरकार और परोपकारी लोगों के साथ साझेदारी पर केंद्रित एक उद्यमशील विश्वविद्यालय के लिए एक बदलाव को उत्पन्न किया है। अविनियमन और ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रतिस्पर्धा और लाभदायक आला बाजारों में माइक्रो–क्रेडेंशियल– छोटे और सस्ते पाठ्यक्रम पेश करने वाले कई नए निजी तृतीयक शिक्षा प्रदाताओं के फलस्वरूप स्नातकोत्तर बाजार भी ध्वस्त हो गया है।

विश्वविद्यालयों को प्रगतिवाद के स्थानों के रूप में देखते हुए, सामाजिक रूप से रूढ़िवादी सरकारों ने 1990 के दशक में बहुसंस्कृतिवाद, नारीवाद और स्वदेशी सुलह के खिलाफ संस्कृति युद्धों की शुरुआत की, जो लोकलुभावन मर्डोक प्रेस आउटलेट्स और अति–दक्षिणपंथी मीडिया टिप्पणीकारों द्वारा प्रेरित थे। सामाजिक रूप से रूढ़िवादी सरकारों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (एसटीईएमएम) पर ध्यान केंद्रित करने वाली राष्ट्रीय नीतियों के साथ, शिक्षा के प्रति उपकरणवादी दृष्टिकोण के पक्ष में ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का फायदा उठाया है। सरकारी आंकड़ों की अनदेखी करते हुए, उन्होंने तर्क दिया है कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान (HASS) का कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है।

अनेक पुनर्रचनाओं और राजनीतिक विचारधाराओं के प्रभाव को लिंगभेदी बना दिया गया है, जिससे ज्ञान–मीमांसा अन्याय उत्पन्न हुआ है। पहला, क्योंकि HASS संकाय जहां महिलाएं केंद्रित हैं, को समामेलित कर दिया गया है, जिससे कार्यकारी निर्णय लेने के स्तर पर HASS का प्रतिनिधित्व कम हो गया है। दूसरा, विश्वविद्यालयों ने एसटीईएमएम में पैसे का, चाहे इरादतन नहीं, स्वतः ही अनुसरण किया है, जिसके कारण संसाधन एचएएसएस से दूर हो गए हैं। तीसरा, यहां तक कि जब महिलाएं वरिष्ठ प्रबंधन में आती हैं, तब भी राष्ट्रीय स्तर पर पैटर्न में उप–कुलपति (डीवीसी) अनुसंधान विभागों के लिए पुरुषों का वर्चस्व होता है, जो अक्सर हमेशा एसटीईएमएम से होते हैं, और शिक्षण और सीखने के लिए डीवीसी विभागों, या घरेलू श्रम में महिलाओं का वर्चस्व होता है। अंत में, बढ़ते कार्यभार की मांग और एक शोध प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक बढ़ती बाधाओं का विशेष रूप से एसटीईएमएम में, महिलाओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जो ऑस्ट्रेलिया में, सार्वभौमिक चाइल्डकैअर के बिना परिवार, काम और देखभाल का बोझ उठाना जारी रखती हैं। समग्र संरचनात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव इस सन्दर्भ में लैंगिक होते हैं कि किस ज्ञान को महत्व दिया जाता है (ज्ञान मीमांसा अन्याय) और महिलाओं के शैक्षणिक करियर को किस प्रकार आकार दिया जाता है। शैक्षणिक, छात्र और ऑस्ट्रेलियाई आबादी की सांस्कृतिक विविधता के बावजूद, विश्वविद्यालय नेतृत्व में जातीय–नस्लीय विविधता की कमी का नीति या विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कभी भी उल्लेख नहीं किया जाता है।

जेजी: क्या आप इस बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकती हैं कि ऑस्ट्रेलियाई उद्यमशीलता विश्वविद्यालयों में ज्ञान मीमांसा अन्याय के किस प्रकार के संरचनात्मक और राजनीतिक रूप उत्पन्न होते हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं?

जेबी: उद्यमशीलता के तर्क का अर्थ है कि ज्ञान का मूल्यांकन केवल उसकी गणना की क्षमता और व्यावसायीकरण की संभावना की क्षमता के संदर्भ में किया जाता है। परिमाणीकरण का यह तर्क ज्ञान–मीमांसा अन्याय में परिणत होता है। सबसे पहले, यह ज्ञान उत्पादन की सामाजिक और भौतिक स्थितियों – सामूहिकता और सहयोग के सामाजिक संबंध, शिक्षण और शोध के भावनात्मक श्रम, और उस काम का समर्थन करने वाले प्रजनन घरेलू श्रम की उपेक्षा करता है । दूसरा यह बाजार संविदावाद पर आधारित है, जो उन संबंधों की उपेक्षा करता है जिसके माध्यम से ज्ञान का उत्पादन होता है (सामूहिकता)। तीसरा, तर्क मानता है कि नवाचार केवल वही है जो एक प्रक्रिया या उत्पाद का नेतृत्व कर सकता है, और वह आर्थिक संबंधों को सामाजिक संबंधों पर निर्भर होने के बजाय उनसे नितांत अलग मानता है। इसलिए उद्यमितावाद एक रूढ़िवादी और विषाक्त लिंग राजनीति को पनपाता है जो सामाजिक और संबंध पर केंद्रित शैक्षणिक कार्य का अवमूल्यन करती है। यह लोकतंत्रों के लिए खतरनाक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी लेकिन नवउदारवादी सरकारें पोस्ट–ट्रूथ के समय में विश्वविद्यालय क्षेत्र के प्रति विरोधी रही हैं, जहाँ विशेषज्ञता और विज्ञान को न केवल षड्यंत्र सिद्धांतकारों द्वारा बल्कि सरकारों द्वारा भी चुनौती दी जा रही है।

जेजी: विश्वविद्यालय क्षेत्र के प्रति रूढ़िवादी और नवउदारवादी सरकारों के विरोधी रुख की बात करते हुए, हाल के संकटों में – और विशेष रूप से वैश्विक महामारी में – एक ओर सामाजिक–वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान के बीच एक विशिष्ट वियोग देखा जा सकता है, और दूसरी ओर, इन संकटों पर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में। इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियां क्या हैं और हाल के घटनाक्रम क्या हैं?

जेबी: एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत देते हुए, ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने महामारी के दौरान जनता की भलाई के लिए अधिकारों के अस्थायी नुकसान को स्वीकार करने की सामूहिक इच्छा दिखाई; उन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली और विज्ञान के सुरक्षा जाल के लाभों को महसूस किया और उन्हें महत्व दिया। समस्या रूढ़िवादी सरकारों (और कुलपतियों) साथ ही ऑस्ट्रेलियाई संवेदनशीलता की HASS के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य को पहचानने, अक्सर विज्ञान को STEMM के साथ बराबरी करने की विफलता में है। फिर भी महामारी और जलवायु संकट दोनों ही HASS के महत्व को उजागर करते हैं। सबसे पहले, सामाजिक विज्ञान और मानविकी की अकादमियां राष्ट्रीय मंत्रिमंडल को सलाह देने के लिए मुख्य वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए रैपिड रिस्पांस फोरम (विशेषज्ञ मॉडल का पैनल) का हिस्सा थीं। दूसरे, कोविड के प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए राज्य और स्वदेशी नेताओं की संचार प्रथाओं में HASS की भूमिका स्पष्ट थी। महामारी के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए सामाजिक–मनोवैज्ञानिक अनुसंधान महत्वपूर्ण था उतना ही जितना मानवाधिकारों और जिम्मेदारियों पर निगरानी और बहस के प्रभावों का पत्रकारों और

>>

शिक्षाविदों द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण था। इसके बावजूद, जहाँ नवउदारवादी संघीय सरकार ने व्यापार और व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक कार्रवाई की। उन्होंने HASS के खिलाफ अपना वैचारिक युद्ध जारी रखा, विश्वविद्यालयों और कलाओं को संघीय समर्थन से बाहर रख, 500,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को, अगर वे खुद का ध्यान नहीं कर सकते थे, घर लौटने जाने के लिए कहा और विश्वविद्यालयों को प्रति व्यक्ति वित्त पोषण कम करते हुए एचएएसएस विषयों को अधिक महंगा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कम खर्चीला बनाने के लिए कानून पेश किया।

राजनीतिक रूप से, प्रधान मंत्री (पीएम) को राज्य के प्रमुखों द्वारा वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन और राज्य की सीमा को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था, यह कार्यवाही पीएम की समय पर संगरोध और टीकाकरण रोलआउट देने में विफलता की तुलना में नेताओं के रूप में राज्य प्रमुखों की महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी के फलस्वरूप थी। राज्य प्रमुख दैनिक प्रेस कांफ्रेंस में मुख्या स्वस्थ्य अधिकारीयों के साथ विशेषज्ञ साक्ष्य और नीति प्रदान करने के लिए खड़े रहे। विज्ञान की वैधता बहाल हुई चूँकि महामारी विज्ञानी, वैज्ञानिक, और विज्ञान टिप्पणीकार मशहूर हस्तियां बन गए। अंत में, हालांकि कला और आतिथ्य क्षेत्र आर्थिक रूप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थे, लॉकडाउन के ऑनलाइन वातावरण में दृढ़ मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अब स्वास्थ्य लाभ के लिए – वे महत्वपूर्ण थे। एक अन्य विरोधाभास में, प्रधानमंत्री कार्बन उत्सर्जन को कम करने के समाधान के रूप में प्रौद्योगिकी पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान और विकास निधि में वृद्धि नहीं कर रहे हैं।

जेजी: हाल ही में आप उस स्थिति के खिलाफ बोलती रही हैं जो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय – कर्मचारी और छात्र – सरकारी कोविड–19 प्रतिबंधों के दौरान सामना कर रहे हैं। आपकी आलोचना के मुख्य बिंदु क्या हैं और इन विकासों और शिक्षाविदों के भविष्य पर उनके संभावित प्रभावों के बारे में आपकी क्या चिंताएँ हैं?

जेबी: ऑस्ट्रेलियाई सरकारें और हाल की गठबंधन सरकारें विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के प्रति लापरवाह रही हैं। ज्ञान उत्पादक और लोकतंत्र के आलोचक और विवेक के केंद्र के रूप में विश्वविद्यालयों में निवेश करने के बजाय उन्होंने विश्विद्यालयों को आय स्रोत (2019 में शिक्षा सेवाओं का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात) के रूप में माना है। जब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवाह को रोक दिया गया, तो महामारी ने अंडरफंडिंग, अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भरता, नीतिगत अस्थिरता, बदलते इंडो–पैसिफिक भू–राजनीति और चीन के उदय के परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों की भेद्यता को उजागर किया। कुलपतियों ने प्रत्युत्तर में पुनर्गठन (अक्सर प्रबंधन सलाहकारों का उपयोग करते हुए) के अवसर का लाभ उठाया, जिससे 40,000 शैक्षणिक और पेशेवर कर्मचारियों को 18 महीनों (कार्यबल का 20 फीसदी) में अनावश्यक बना दिया गया और अनुबंध या सत्रीय शिक्षाविदों, जो सभी कर्मचारियों के 66 फीसदी हैं, का नवीनीकरण नहीं हुआ। विशेष रूप से HASS विषयों को बंद कर दिया गया है (जैसे भाषाएं, समाजशास्त्र)। नौकरी की अनिश्चितता, उच्च छात्र–कर्मचारी अनुपात, प्रशासनिक अधिभार, अनुसंधान वित्त पोषण की कमी, प्रबंधकीयता, प्रशासन के निगमीकरण, निर्णय लेने से वंचित होने और भवन और वित्तीय बाजारों में जोखिम भरा निवेश के कारण शिक्षाविदों ने पहले ही विश्वविद्यालय प्रबंधन में विश्वास खो दिया था। उभरती सामूहिक कार्रवाई से यह अविश्वास क्रोध में बदल दिया गया है, उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के गठबंधन के गठन के माध्यम से। शिक्षाविद देखते हैं कि निजी शैक्षिक प्रदाताओं और परामर्श फर्मों से विश्वविद्यालय की विशिष्टता खतरे में है। कई प्रदाता सस्ते माइक्रो–क्रेडेंशियल्स की पेशकश कर रहे हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार की आउटसोर्सिंग अनुसंधान और परामर्श से लाभान्वित होने के साथ–साथ प्रशिक्षण में निवेश कर रही हैं। उच्च शिक्षा के खोखलापन को ऐसे समय में उबरने में दशकों लगेंगे जब टिकाऊ भविष्य के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को सूचित करने के लिए कई चुनौतियों के लिए नए ज्ञान, रचनात्मकता और नवाचार की आवश्यकता होती है।

जेजी: आपकी राय में, ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों और छात्रों के लिए स्थिति में सुधार लाने और समाज में विश्वविद्यालयों की भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या हो सकता है? एक सकारात्मक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए मुख्य धुरी बिंदु कहाँ हैं?

जेबी: एक प्रमुख मुद्दा यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भविष्य के लिए विश्वविद्यालयों और HASS के महत्व को समझने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक संवेदनशीलता को कैसे स्थानांतरित किया जाए। इसका मतलब है कि जनता और सरकार को शिक्षित करना कि विश्वविद्यालय विशिष्ट हैं क्योंकि वे स्नातकों को ''नौकरी के लिए तैयार'' करने से ज्यादा कुछ करते हैं। कुलपतियों ने लोकतंत्रों के लिए विश्वविद्यालयों के महत्व के बारे में बहस का नेतृत्व करने या सरकारों को यह समझाने के लिए कि एक स्थायी भविष्य में संक्रमण के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान महत्वपूर्ण है, के अवसर (या सामूहिक इच्छाशक्ति की कमी) को बर्बाद कर दिया है ।

आंतरिक रूप से, विश्वविद्यालय प्रबंधकों को सुरक्षित रोजगार और एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करके अपने कर्मचारियों का विश्वास फिर से हासिल करना होगा। साझा शासन वर्तमान में प्रबंधन द्वारा उपेक्षित शिक्षाविदों की विशेषज्ञता पर आधारित होगा। इसे प्रबंधन और प्रमुख चयन पैनल पर अकादमिक प्रतिनिधित्व; महत्वपूर्ण बहस को सूचित करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वतंत्र शैक्षणिक निकाय; औद्योगिक समझौते जो अकादमिक स्वतंत्रता और कार्य स्थितियों की रक्षा करते हैं और उन्हें बाधित नहीं करते हैं; निर्णय लेने की सहयोगी प्रक्रियाएं जो सार्थक प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करती हैं न कि सांकेतिक परामर्शय और इक्विटी– और पर्यावरण–संचालित रणनीतिक योजनाएं और बजट की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय भी अपने स्थानीय समुदायों के लिए एक व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि विश्वविद्यालय शहरी और क्षेत्रीय समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए केंद्रीय हैं। विश्वविद्यालयों के मध्य अधिक से अधिक विशेषज्ञता और अंतर दूरी और लागत के कारण पहले से ही विश्वविद्यालय में प्रवेश और रहने के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों के अवसरों को कम कर देगा। एक अच्छा विश्वविद्यालय सतत और समावेशी शिक्षण वातावरण और लोकतंत्र के लिए ज्ञान की बहुलता और HASS के महत्व को पहचानेगा। वह सामाजिक या संबंधपरक (बाजार के बजाय) अनुबंधवाद पर आधारित सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देगा जो विश्वविद्यालयों और समाजों में होने और करने के लिए संबंधों (सामूहिकता) को मूल मानता है। ■

सभी पत्राचार जिल ब्लैकमोर को <jillian.blackmore@deakin.edu.au> पर प्रेषित करें।

> कोविड–19 महामारी और वर्ग संघर्ष

डारियो एजेलिनी, यूनिवर्सिडैड ऑटोनोमा डी जाकाटेकास, मैक्सिको द्वारा

18 मई, 2020 को बेहतर कोविड–सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए याकिमा घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि श्रमिक हड़ताल पर हैं। श्रेय: फेसबुक पेज Familias Unidas por La Justicia, एडगर फ्रैंक्स।

पूंजीवाद के तहत संकट मौजूदा असमानताओं को बढ़ाते हैं। यह भी कोविड–19 महामारी से निपटने का एक परिणाम है। पिछले वर्ष की तुलना में 2020 के पहले नौ महीनों में वैश्विक श्रम आय में अनुमानित 10.7 प्रतिशत (या 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर) की कमी आई है। इस बीच, दुनिया भर में 2,200 से अधिक आधिकारिक अरबपतियों की कुल संयुक्त संपत्ति 31 दिसंबर, 2019 को 9.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर एक साल बाद अनुमानित 11.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गई। दुनिया भर के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि गरीब और कामकाजी वर्ग के लोगों को कोविड –19 के कारण संक्रमित होने और अस्पताल में भर्ती होने का अधिक खतरा है और यह कि अश्वेत, स्वदेशी और नस्लीय श्रमिक वर्ग की आबादी अनुपातहीन कोविड –19 संक्रमण और मृत्यु दर का अनुभव करती है।

> महामारी से जुड़े संघर्ष

कामगार वर्ग के लोग और समुदाय महामारी के कारण ''के कारण'' और ''के बावजूद'' विश्व स्तर पर उठे। हड़ताल और विरोध उन क्षेत्रों में हो रहे हैं जो विशेष रूप से बढ़ते परिचालन दबाव और महामारी के कारण संक्रमण के जोखिम से प्रभावित हुए हैं, और इनमें थे पहले से ही खराब कामकाजी परिस्थितियों और कम वेतन की विशेषता है: स्वास्थ्य देखभाल और नर्सिंग, वेयरहाउसिंग, मेल–ऑर्डर व्यवसाय और रसद, यात्री परिवहन, और खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से मांस–प्रसंस्करण और कृषि।

दशकों से नवउदारवादी मित्तव्ययता नीतियों के मुख्य लक्ष्यों में से एक, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने अमेरिका और यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक, दुनिया भर में हमले देखे हैं। इस स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यबल मुख्य रूप से महिला है; विशेष रूप से नर्सों के मामले में, कम वेतन और उच्च जोखिम का लिंग और नस्लीय आयाम होता है। सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में भी हड़तालें हुई हैं। विभिन्न अमेरिकी शहरों में ड्राइवरों द्वारा स्व–संगठित वाइल्डकैट हमले हुए। मई 2020 में ब्रसेल्स में, यूनियन द्वारा प्रबंधन के साथ उनकी सहमति के बिना एक समझौते पर पहुंचने के बाद, सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों ने एक जंगली हड़ताल का मंचन किया। मेक्सिको सिटी, मेडेलिन और सैंटियागो डी चिली और जापानी रेलवे में मेट्रो सिस्टम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। जर्मनी में, ट्रेड यूनियन वर.दी ने शहरी सार्वजनिक परिवहन में कई हड़तालें कीं। नौकरी की सुरक्षा और वेतन में वृद्धि के लिए इटली और ग्रीस को सार्वजनिक और निजी परिवहन क्षेत्र में हड़ताल का सामना करना पड़ा। खाद्य उद्योग में श्रमिकों का संघर्ष पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में मांस प्रसंस्करण क्षेत्र में शुरू हुआ, जहां कार्यबल मुख्य रूप से प्रवासी है और संक्रमण दर बहुत अधिक थी। इटली, स्पेन और अमेरिका में, प्रवासी कृषि श्रमिक हड़ताल पर चले गए। विभिन्न देशों में खाद्य खुदरा क्षेत्र में हड़तालें हुईं। वितरण और रसद क्षेत्र में बढ़े हुए सुरक्षात्मक उपायों के लिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर महामारी के शुरुआती दिनों में हड़तालें हुईं। अमेरिका। इटली में Amazon, TNT, DHL, और UPS सहित सभी रसद कंपनियों और गोदामों ने हड़तालों और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की अनुपस्थिति का अनुभव किया है। इटली में खाद्य वितरण कर्मचारी महामारी के दौरान कई बार हड़ताल पर गए। एक अदालत ने कंपनियों को लाभ के साथ आश्रित श्रमिकों के रूप में साइकिल द्वारा भोजन पहुंचाने वाले सभी 60,000 श्रमिकों को काम पर रखने के लिए मजबूर किया।

> महामारी के बावजूद संघर्ष

हड़तालें और मजदूरों के संघर्ष जिनका महामारी से कोई संबंध नहीं था या केवल सीमित था, भी हुए। श्रम संघर्षों ने उत्पादन

>>

संयंत्रों को जकड़ लिया जहां बड़े पैमाने पर छंटनी या यहां तक कि स्थायी रूप से बंद करने की योजना बनाई गई थी। डच IJmuiden स्टीलवर्क्स में, जो भारतीय टाटा स्टील के स्वामित्व में है, श्रमिकों ने तीन सप्ताह से अधिक समय तक हड़ताल का मंचन किया, जिससे 9,000 श्रमिकों में से 1,000 की बर्खास्तगी को रोका जा सके और 2026 तक रोजगार की गारंटी हासिल की जा सके। भारत में दिसंबर 2020 में, श्रम संबंधों के बड़े पैमाने पर नियंत्रण और विशाल सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण की सरकार की योजनाओं के जवाब में सामूहिक हड़ताल हुई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लगभग 250 मिलियन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सितंबर 2020 से, भारत में किसान निजी निवेशकों और निगमों के पक्ष में नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जनवरी 2021 में दिल्ली के किसानों के तूफान के बाद सरकार ने 18 महीने के लिए कानूनों को निलंबित कर दिया। अक्टूबर 2020 में प्राइम डे सौदेबाजी के लिए, जर्मनी, स्पेन और पोलैंड में अमेजन के कर्मचारी बेहतर वेतन के लिए हड़ताल पर चले गए। इसके बाद जर्मनी भर में अमेजॅन साइटों पर कई–दिवसीय हड़तालों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। बिलबाओ, बास्क देश के बंदरगाह में, विभिन्न कंपनियों के 300 डॉकर्स 55 दिनों तक हड़ताल पर चले गए, जब तक कि कंपनियों ने उनकी कई मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया–जिसमें एक सीमा भी शामिल है। प्रति वर्ष अधिकतम 1,826 कार्य घंटे, काम पर अवकाश और अवकाश।

महामारी के दौरान कई तरह के लोकप्रिय मजदूर वर्ग के विद्रोह भी हुए या जारी रहे। बोलिविया में तानाशाही तख्तापलट शासन के खिलाफ विरोध ने नए चुनावों को मजबूर किया और एमएएस (समाजवाद की ओर आंदोलन) को सत्ता में वापस लाया, जिसे तख्तापलट से हटा दिया गया था। अमेरिका में मुख्य संघ एएफएल–सीआईओ मई 2020 में शुरू होने वाले काले नेतृत्व वाले बहुजातीय मजदूर–वर्ग विद्रोह के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देने में विफल रहा। हालांकि, अकेले मई और जून में, ब्लैक लाइव्स मैटर (BLM) के साथ एकजुटता में 600 से अधिक काम रुक गए या हड़तालें हुईं। बस ड्राइवरों ने प्रदर्शनकारियों को जेल ले जाने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल लॉन्गशोर एंड वेयरहाउस यूनियन (ILWU), जो कि 65 प्रतिशत अश्वेत है, जॉर्ज फ्लॉयड के अंतिम संस्कार वाले दिन 9 जून, 2020 को लगभग नौ मिनट के लिए यूएस पैसिफिक कोस्ट में बंदरगाहों को बंद कर दिया। 19 जून को, जिस दिन अमेरिका में गुलामी की समाप्ति की स्मृति में छुट्टी होती है, ILWU ने सभी 29 वेस्ट कोस्ट बंदरगाहों में पूरे आठ घंटे की शिफ्ट हड़ताल की। 20 जुलाई को, यूनियनों और आंदोलनों, जिनमें ILWU यूनाइटेड फार्म वर्कर्स और नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स अलायंस शामिल हैं, ने 25 से अधिक शहरों में *ब्लैक लाइव्स के लिए हड़ताल* का आयोजन करने के लिए BLM के साथ भागीदारी की।

> श्रम कार्रवाई के नए स्थल

पे डे रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि 2020 में महामारी के दौरान अमेरिका ने 1946 के बाद से हमलों की अपनी सबसे बड़ी लहर देखी। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, – 2009 से अलग– 2020 वर्ष औद्योगिक विवादों की सबसे कम संख्या वाला वर्ष था। हालांकि, बाद में उत्पादन संरचना में बदलाव की अनदेखी करते हुए, केवल एक कार्यस्थल में 1,000 या अधिक श्रमिकों से जुड़े विवादों को गिनता है। नई श्रम अशांति स्पष्ट रूप से हाशिये से आ रही है, पहले असंगठित क्षेत्रों से, नए संघीकरण से, काम करने की परिस्थितियों में जो ''औद्योगिक कार्रवाई'' के रूप में मानी जाने वाली विधियों के अलावा लागू होती हैं।

कोविड –19 महामारी के दौरान, पिछले वर्षों की तरह, श्रमिकों के संघर्षों की शुरुआत स्व–संगठित संघर्षों और यूनियनों के साथ शॉपफ्लोर आयोजन के साथ हुई। शॉपफ्लोर से संघर्ष तेजी से और अधिक लचीले तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पारंपरिक यूनियनों ने ज्यादातर सक्रिय रूप से हड़तालों को बढ़ावा देने से परहेज किया और जब वे शामिल थे, तो यह लगभग हमेशा रैंक–एंड–फाइल दबाव के कारण होता था। नवउदारवाद और उत्पादन में बदलाव ने संगठन के पुराने मॉडल को काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन विश्व स्तर पर नए संघर्ष और संगठनात्मक ढांचे उभर रहे हैं। श्रमिक आंदोलन की कमजोरी को अभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अधिकांश संदर्भों में, श्रम के पक्ष में शक्ति संतुलन को वास्तव में स्थानांतरित करने के लिए जो आवश्यक होगा, उससे बहुत कम कार्रवाई होती है। फिर भी, महामारी के दौरान श्रमिकों की लामबंदी प्रदर्शित करती है कि यह धारणा कि वर्ग अब एक प्रासंगिक श्रेणी नहीं है, गलत है। इसके अलावा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्पष्ट भेद्यता वैश्वीकृत विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों की संरचनात्मक शक्ति को फिर से बढ़ा देती है।

बड़े पैमाने पर मुनाफे को बाधित करना मजदूर वर्ग के पास सबसे शक्तिशाली उपकरण बना रहता है। इस संदर्भ में उत्पादन और प्रजनन के बीच के संबंध पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि वर्ग संघर्ष का मुद्दा होना चाहिए और जो इसे प्रारम्भ करता है। पूंजीवादी केंद्रों में प्रवासी श्रमिक नए मजदूर वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लिंग और ''नस्ल'' न तो वर्ग को प्रतिस्थापित करते हैं और न ही इसका खंडन करते हैं - उन्हें पूंजीवाद और शोषण पदानुक्रम के विश्लेषण में एकीकृत किया जाना चाहिए। महिलाओं द्वारा लड़े गए वर्ग संघर्षों के अपने विश्लेषण में, पाओला वरेला एक महत्वपूर्ण अवलोकन करती हैं: ''कार्यस्थल को एक क्षेत्रीय स्थान के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली स्थिति [...] के रूप में लिया जाता है जो एक *उत्प्रेरक* के रूप में काम कर सकता है और स्वतन्त्र रुप से मजदूर वर्ग के दावों को मजबूत कर सकता है। ■

सभी पत्राचार डारियो एजेलिनी को <da483@cornell.edu> पर प्रेषित करें।

> फ़िलीपीन्स में लड़ाका श्रम संगठन

सारा रेमुंडो, फिलीपींस विश्वविद्यालय, दिलिमन, Bulatlat-com के स्तंभकार और इंटरनेशनल लीग ऑफ पीपल्स स्ट्रगल (ILPS) के आयोजक द्वारा

फिलीपींस में वर्कर्स यूनियन ''किलुसांग मेयो उनो'' (केएमयू) के कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रदर्शन। श्रेयः केएमयू।

स्पेन के लगभग 400 वर्षों के उपनिवेशवाद के बाद उसके विरुद्ध 1896 की फिलीपीन क्रांति की जीत को अमेरिकी साम्राज्यवाद ने नाकाम कर दिया था। स्पेनिश साम्राज्य के अंतर्गत – फिलीपींस, क्यूबा, गुआम और प्यूर्टो रिको जैसे देशों का अमेरिका को हस्तांतरण को 1898 की पेरिस संधि के माध्यम से वैध कर दिया गया था; अमेरिका ने स्पेन को "मुआवजे" के रूप में $20 मिलियन का भुगतान किया। इसने स्पेनिश साम्राज्य और अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा फिलीपींस के निरंतर उपनिवेशीकरण, एक परियोजना जिसे नव–औपनिवेशिक संस्था–निर्माण और नरसंहार द्वारा परिभाषित किया गया था, के अंत को चिह्नित किया। इसके परिणामस्वरूप लगातार आर्थिक अविकसितता बनी हुई है जो आरक्षित श्रम की एक विशाल सेना के साथ एक निर्यात–उन्मुख और आयात–निर्भर अर्थव्यवस्था को बनाए रखती है।

> किलुसांग मेयो ऊनो, मे वन आंदोलन

इस संदर्भ में, वेतन वृद्धि और संविदाकरण योजनाओं जैसे आर्थिक अभियानों को राजनीतिक संघर्षों के रूप में देखा और उठाया जाना चाहिए। किलुसांग मेयो उनो (केएमयू/मे वन मूवमेंट) की स्थापना 1 मई 1980 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थीः 1) मार्शल लॉ के तहत फासीवाद विरोधी अभियानों की वकालत करने वाले प्रगतिशील श्रमिक संगठनों को इकट्ठा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए; 2) अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघर्ष के लक्ष्यों की ओर प्रगतिशील श्रमिक संगठनों को संगठित और समेकित करना।

2018 में, KMU ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (ITUC) को 115,000 की आधिकारिक सदस्यता प्रस्तुत की। इसके वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक संघ कार्य में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड), शहरी गरीब समुदायों, कॉल सेंटरों और निजी अस्पतालों में ठोस और जमीनी आयोजन; मजदूरी के लिए और अत्याचार के खिलाफ अन्य श्रमिकों के साथ व्यापक गठबंधन का गठन; और कोविड–19 महामारी के बीच लोकप्रिय श्रम मुद्दों के लिए एक व्यापक अभियान केंद्र का प्रावधान करना सम्मिलित है। राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष में केएमयू किसान–मजदूर गठबंधन के सिद्धांत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में दृढ़ता से रखता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे ग्लोबल दक्षिण में श्रम को हमेशा साम्राज्यवाद के हिंसक बहाव के खिलाफ लड़ना पड़ा है।

फिलीपीन की 108 मिलियन की आबादी में से, लगभग 3.9 मिलियन (3.6 प्रतिशत) औद्योगिक श्रमिक हैं, जिसमें विनिर्माण, निर्माण, निर्यात–बढ़ते व्यवसायों और अन्य मजदूरी कमाने वाले श्रमिक सम्मिलित हैं। 2017 के बाद से, KMU ने संविदाकरण की प्रघटना और फिलीपीनी श्रम के बढ़ते अर्ध–सर्वहाराकरण को संबोधित करने

>>

के लिए स्वयं को संगठित किया है। उत्तरार्द्ध ने शहरी और ग्रामीण गरीब समुदायों, जहां विक्रेता और अन्य अनौपचारिक कर्मचारी जैसे अनियमित वेतन भोगी (10.4 मिलियन) और गैर–मजदूरी कमाने वाले (6.3 मिलियन) हैं, तक पहुंचने के लिए केएमयू की आयोजन क्षमता को आगे बढ़ाया है।

> फिलीपींस में श्रम के स्थान और तौर–तरीके

विदेशी कृषि व्यवसाय उपक्रमों के लिए भूमिहीन किसानों का वर्ग आरक्षित श्रमिक और वास्तविक कृषि श्रमिक रहा है। विस्थापित भूमिहीन किसान शहर में रहवास करते हैं और स्थानीय कारखानों और बहुराष्ट्रीय ईपीजेड में ठेका मजदूर के रूप में काम करते हैं। संविदाकरण की एक कठोर नीति अनिश्चित कार्य और एक गैर–संघीय कार्यस्थल के लिए स्थान बनाती है। वे अन्य जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करते हैं।

एक औद्योगिक आधार की अनुपस्थिति, जो फिलीपींस में बेरोजगारी का स्रोत है, ने भी श्रम के दो तौर–तरीकों का मार्ग प्रशस्त किया है जो वैश्विक पूंजी द्वारा सस्ते सेवा श्रम की मांग का आउटसोर्स और निर्यात किए गए श्रम के रूप में जवाब देते हैं।

इन तौर–तरीकों में से पहला आउटसोर्स श्रम है। फिलीपींस दुनिया की निर्विवाद "कॉल सेंटर कैपिटल" है जो वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के साथ निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारत को पछाड़ रहा है। देश में 851 पंजीकृत बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनियां हैं; इनमें से आधे से अधिक कॉल सेंटर (429) हैं, और अन्य का एक बड़ा हिस्सा आईटी से संबंधित सेवाएं (400 या 46.2 प्रतिशत) प्रदान करने वाली फर्म हैं। शेष मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन व्यवसाय और एनिमेटेड फिल्म और कार्टून प्रोडक्शन हाउस हैं। एक अमेरिकी अर्ध–उपनिवेश के रूप में, फिलीपींस अपनी आउटसोर्सिंग सेवाओं का 65 प्रतिशत अपने साम्राज्यवादी स्वामी को प्रदान करता है; यह यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ग्राहकों को भी सेवा प्रदान करता है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि बीपीओ उद्योग में कुल 675,600 कर्मचारी हैं। सरकार द्वारा देश के "सनशाइन उद्योग" के रूप में नामित, इस क्षेत्र में फिलिपिनो श्रम को ग्राहक के समय क्षेत्र के काम के घंटों का पालन करना आवश्यक है।

दूसरा तरीका श्रम का निर्यात है, जो वर्तमान तक फिलीपीन राज्य का स्टॉपगैप समाधान और महत्वपूर्ण नीति रहा है। ओवरसीज फिलिपिनो वर्कर्स (ओएफडब्ल्यू) शीर्ष डॉलर कमाने वाले और जीडीपी बूस्टर हैं। 2018 विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि अकेले 2017 में, फिलीपींस ने OFW प्रेषणों से Php 1.72 ट्रिलियन ($ 32.6 बिलियन) की कमाई की।

> मजदूरों के संघर्षों और साम्राज्यवाद विरोधी को जोड़ना

मार्कोस के मार्शल लॉ के बाद से फिलिपिनो श्रम के बदलते परिदृश्य के साथ, श्रमिक संगठन का अभिप्राय ग्लोबल दक्षिण में श्रमिकों के लिए एक साम्राज्यवादी व्यवस्था के मुख्य परिणामों को संबोधित करना भी है। इसमें वैश्विक असमान विनिमय के आधार पर मजदूरी पदानुक्रम के कारण फिलिपिनो श्रम को सस्ता रखना शामिल है। एक अन्य परिणाम परिधि में बेरोजगारों की एक बड़ी सेना का तीव्र उत्पादन है, जिसके परिणामस्वरूप फिलिपिनो श्रम का अर्ध–सर्वहाराकरण बढ़ रहा है। यह श्रम संबंधों को परिभाषित करने वाले विदेशी पूंजी और घरेलू दलाल हितों के बीच साझेदारी के लिए जिम्मेदार है। अर्ध–सर्वहाराकरण जैसा कि फिलीपींस में होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मजदूरों को एक साम्राज्यवादी व्यवस्था द्वारा बेगार, अनियमित और अनुबंधित श्रम के माध्यम से जीवित रहने के लिए मजबूर किया जाता है।

यह शहरी और ग्रामीण गरीब समुदायों को श्रम–संकेंद्रित स्थल बनाता है जहाँ एक साम्राज्यवाद–विरोधी मजदूर वर्ग राजनीति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केएमयू लोगों से वहां मिलता है जहाँ वे सामूहिक रूप से जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों को समुदाय से राष्ट्र में बदलने के लक्ष्य के साथ हैं। जीपनी ड्राइवरों और अनौपचारिक श्रमिकों के परिवार जहां रहते हैं, वहां ये संगठित होता है । कॉल सेंटरों में श्रमिक संगठनों के गठन को रचनात्मक रूप से समर्थन देकर, केएमयू व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग में वेतन अंतरपणन के नवीनतम रूपों को संबोधित करता है।

केएमयू के अपने 40 वर्षों के संघर्ष से एक महत्वपूर्ण सबक यह सीखा जाना चाहिए कि अर्ध–उपनिवेश में संघवाद आर्थिक या राजनीतिक संघर्ष के बीच एक सुविधाजनक विकल्प नहीं बन सकता है। इस संबंध में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह उत्पादन के एक विशेष स्थल के भीतर श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच एक सीमित आर्थिक संघर्ष के रूप में परिवर्तन को वैश्वीकृत राजनीतिक संघर्ष के ठिकाने में सहायता करता है जिसमें राज्य की लेनिनवादी थीसिस की उत्पीड़ितों के शोषण के लिए एक उपकरण के रूप में पुष्टि की जाती है। इस संदर्भ में, ग्लोबल साउथ में केएमयू जैसे श्रम संघ वैश्विक पूंजी के चंगुल से श्रम को मुक्त करने के अपने ऐतिहासिक संघर्ष में केवल साम्राज्यवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीयवादी हो सकते हैं। उनका साम्राज्यवाद–विरोधी और फासीवाद–विरोधी मजदूर वर्ग संघर्ष है, जो एक उज्ज्वल समाजवादी भविष्य की ओर निशुल्क भूमि पुनर्वितरण और राष्ट्रीय औद्योगीकरण के आह्वान से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। ■

सभी पत्राचार सारा रेमुंडो को <sarahraymundo1976@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> जापान में संघों और श्रम बाजार का अविनियमन

हिरोकी रिचर्ड वतनबे, रित्सुमीकन विश्वविद्यालय, जापान द्वारा

2011 में शिम्बाशी, जापान में ''नो मोर करोशी'' (अधिक काम से मौत) विरोध। श्रेय: नेसनाद का खुद का काम, CC BY-SA 4.0

आरम्भिक 1990 के दशक में बुलबुला अर्थव्यवस्था के पतन के बाद से जापान को आर्थिक ठहराव का सामना करना पड़ा है। जापानी कंपनियों ने भी पड़ोसी पूर्वी एशियाई देशों से तीव्र आर्थिक प्रतिस्पर्धा का अनुभव किया है। इस स्थिति से निपटने के लिए अधिक श्रम बाजार लचीलेपन के लिए नियोक्ताओं की मांग के जवाब में, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की सरकार ने नीति निर्माण प्रक्रिया में अपनी सत्तावादी प्रवृत्ति को बढ़ाकर 1990 के दशक से श्रम बाजार नियंत्रण को लागू किया है। नवउदारवादी श्रम बाजार अविनियमन को लागू करने के लिए, एलडीपी सरकार ने कई कैबिनेट परिषदों में श्रमिक संघों को नीति निर्माण प्रक्रिया से बाहर रखा है।

> नवउदार श्रम बाजार का अविनियमन

गैर–नियमित रोजगार के अविनियमन के संबंध में, अस्थायी कार्य एजेंसी कानून में 1999 के संशोधन ने केवल कुछ अपवादों (विनिर्माण सहित) के साथ, नियोक्ताओं को इसका व्यापक रूप से उपयोग करने की अनुमति देकर अस्थायी एजेंसी कार्य को उदार बनाया। 2003 के संशोधन ने नियोक्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में अस्थायी एजेंसी कार्य का उपयोग करने में सक्षम बनाया। जापानी अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को देखते हुए यह संशोधन महत्वपूर्ण था। हाल ही में 2015 के संशोधन ने, यदि नियोक्ता हर तीन साल में अस्थायी कर्मचारियों को बदलते हैं, नियोक्ताओं को बिना किसी समय सीमा के अस्थायी एजेंसी के काम का उपयोग करने में सक्षम बनाया ।

> >

नवउदारवादी श्रम बाजार के अविनियमन को लागू करने के कारण, गैर–नियमित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है; कुल श्रमिकों में गैर–नियमित श्रमिकों का वर्तमान प्रतिशत लगभग 40: है। उनकी रोजगार सुरक्षा कम है, जैसा कि 2007–8 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान और हाल ही में कोरोनावायरस महामारी के दौरान कई बर्खास्तगी में देखा गया है। कम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा तक अपर्याप्त पहुंच इत्यादि के लक्षणों के साथ उनकी कार्य परिस्थितियाँ खराब है।

यद्यपि नियमित श्रमिक अधिक सुरक्षित हैं, लेकिन मजदूरी, काम के घंटे आदि के मामले में उनकी कार्य परिस्थितियाँ खराब हो गई है। उदाहरण के लिए, एलडीपी सरकार ने श्रम मानक कानून में 1998 और 2003 के संशोधनों के साथ ''विवेकाधीन कार्य'' के उपयोग का विस्तार करके काम के घंटे के नियमों में ढील दी। इस श्रेणी के नियमित कामगारों को काम के घंटे बिताने का विवेकाधिकार होना चाहिए, लेकिन सप्ताहांत और राष्ट्रीय अवकाशों और देर रात में काम करने के अलावा वे किसी भी तरह के ओवरटाइम वेतन के हकदार नहीं हैं। जहाँ इन नियमित श्रमिकों को काम के घंटे के आवंटन के मामले में नौकरी की तथाकथित स्वायत्तता होनी चाहिए, अक्सर ऐसा नहीं होता है। इसके बजाय, विवेकाधीन कार्य के विस्तार ने नियोक्ताओं को नियमित श्रमिकों का अधिक लचीले ढंग से उपयोग करने और कम वेतन का भुगतान करने में सक्षम बनाया है।

हाल ही में, एलडीपी सरकार ने 2018 कार्य–शैली सुधार में ''अत्यधिक पेशेवर कार्य'' की शुरुआत की। अत्यधिक–पेशेवर कार्य काम के घंटे के नियमों का और अधिक अविनियमन है, और इस श्रेणी के नियमित कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में ओवरटाइम वेतन के हकदार नहीं हैं। जहाँ वर्क–स्टाइल रिफॉर्म ने ओवरटाइम काम पर अधिकतम कानूनी सीमा भी लगाई, यह सीमा अभी भी अधिक है (किसी भी छह महीने में औसतन 80 घंटे प्रति माह), और इससे *करोशी* (अधिक काम से मृत्यु) और *करो जिसात्सु* (अधिक काम के कारण होने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आत्महत्या) की संख्या में उल्लेखनीय रूप से कमी आने की संभावना नहीं है। नियमित कामगारों पर भी गैर–नियमित कामगारों की बढ़ती संख्या द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का लगातार खतरा बना हुआ है। इसने नियोक्ताओं को नियमित कर्मचारियों पर खराब परिस्थितियों में अधिक कार्य करने का दबाव बनाने में सक्षम बनाया है।

> श्रमिक संघ और अविनियमन

एलडीपी सरकार द्वारा लागू किए गए नवउदारवादी श्रम बाजार के अविनियमन ने भी गैर–नियमित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करके श्रमिक संघों की शक्ति को कमजोर कर दिया है, क्योंकि श्रमिक संघों के लिए गैर–नियमित श्रमिकों को संगठित करना अधिक कठिन है। इसने संघ घनत्व को कम करने में योगदान दिया है, जो वर्तमान में लगभग 17 प्रतिशत है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कई कैबिनेट परिषदों में नीति निर्माण प्रक्रिया तक पहुंच के नुकसान ने भी श्रमिक संघों के शक्ति संसाधनों को कम कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, संघों के बीच श्रम बाजार के अविनियमन में हितों के टकराव ने उनके शक्ति संसाधनों में गिरावट में योगदान दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल और (हाल तक) इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्यधारा के उद्यम संघों ने आवश्यक रूप से श्रम बाजार के अविनियमन का विरोध नहीं किया हो। गैर–नियमित श्रमिकों की कीमत पर नियमित श्रमिकों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए इन संघों ने अक्सर अपनी कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ क्रॉस–क्लास गठबंधन बनाए हैं। नतीजतन, वे गैर–नियमित श्रमिकों की काम की अनिश्चितता और नियमित श्रमिकों की बढ़ती संख्या की खराब कामकाजी परिस्थितियों, जैसे कि अवैध बर्खास्तगी, वेतन का भुगतान न करने और लंबे समय तक काम करने के घंटों के प्रति उदासीन रहे हैं।

इसके विपरीत, व्यक्तिगत रूप से संबद्ध संघ, जिसमें कोई भी व्यक्तिगत कर्मचारी अपनी कंपनी की संबद्धता के बावजूद शामिल हो सकते हैं, ने काम की अनिश्चितता और खराब काम की परिस्थितियों से पीड़ित एकल श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोक्ताओं के खिलाफ अधिक आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी है। ये संघ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) में, जो उद्यम संघों द्वारा संगठित नहीं हैं, गैर–नियमित श्रमिकों और नियमित श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका उद्देश्य व्यक्तिगत श्रम विवादों को हल करना है। हालांकि, व्यक्तिगत रूप से संबद्ध यूनियनों के शक्ति संसाधन – मानव और वित्तीय दोनों – उद्यम संघों की तुलना में बहुत कम हैं।

शक्ति संसाधनों की कमी की भरपाई करने के लिए, कुछ व्यक्तिगत रूप से संबद्ध संघों ने नागरिक समाज संगठनों के साथ गठबंधन बनाकर ''सामाजिक आंदोलन संघवाद'' में संलग्न हुए हैं। उदाहरण के लिए, *शूटोकन सिनेन यूनियन* (एसएसयू, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूथ यूनियन), एक व्यक्तिगत रूप से संबद्ध संघ, जो युवा श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में विशिष्ट है, ने एक नागरिक समाज संगठन, *एक्विटास* (लैटिन में ''निष्पक्ष''), द्वारा आयोजित अभियान ''फाइट फॉर 1500 येन'' में भाग लिया था। यह अभियान सरकार से कामगार निर्धन के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का आग्रह करने के लिए था। हालांकि, ऐसे गठबंधन अक्सर तदर्थ आधार पर होते हैं और पर्याप्त रूप से संस्थागत नहीं होते हैं।

व्यक्तिगत रूप से संबद्ध यूनियनों ने राजनीतिक पैरवी, नीति प्रस्तावों, जन विरोध, आदि के रूप में राजनीतिक एजेंसी का प्रयोग करने का भी प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, SSU ने संबंधित मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय से न्यूनतम वेतन, नौकरी की सुरक्षा और काम के घंटे जैसे मुद्दों के संदर्भ में युवा श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए नीतिगत अनुरोध किए। हालांकि, कुछ ही अपवादों के आलावा, व्यक्तिगत रूप से संबद्ध यूनियनों की राजनीतिक कार्रवाइयों का सरकार की श्रम नीति पर शायद ही कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। व्यक्तिगत रूप से संबद्ध संघों को श्रमिकों को संगठित करने में कठिनाई हुई है, क्योंकि वे आमतौर पर कार्यस्थल में पारंपरिक सामूहिक भर्ती पर निर्भर होने के बजाय श्रम परामर्श के माध्यम से व्यक्तिगत आधार पर सदस्यों की भर्ती करते हैं। नतीजतन, कई व्यक्तिगत श्रमिक अभी भी काम की अनिश्चितता और खराब काम की स्थिति से पीड़ित हैं। ■

सभी पत्राचार हिरोआकी रिचर्ड वतनबे को <hrwatana@fc.ritsumei.ac.jp> पर प्रेषित करें।

> सुहार्तो के शासन के प्रति इंडोनेशियाई श्रमिकों का प्रतिरोध

वर्ना दिनाह क्यू. वियाजार[1], फिलीपींस डिलिमैन विश्वविद्यालय, फिलीपींस द्वारा

अगस्त 2020 में इंडोनेशियाई संघवादी देश भर में श्रम अधिकारों को खत्म करने की सरकारी योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। श्रेय: IndustriALL Southeast Asia.

जैसा कि अक्सर कहा जाता है, जो लोग अतीत को याद नहीं रख सकते, वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। जब हम नवउदारवाद के गंभीर संकटों और हमारे समय की राजनीतिक–आर्थिक असमानताओं के बीच दुनिया भर में सत्तावाद के उदय से जूझ रहे हैं तब इतिहास हमें सबक देता है। यहाँ उन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ट्रेड यूनियन आंदोलनों का अध्ययन करना मददगार हो सकता है, जिन्होंने उत्तर औपनिवेशिक और शीत युद्ध की अवधि के दौरान सत्तावादी शासन से दमन का सामना किया है। ऐसा ही एक उदाहरण इंडोनेशियाई श्रमिक आंदोलन है। इंडोनेशियाई श्रमिक आंदोलन डच के खिलाफ उपनिवेश विरोधी आंदोलन में गढ़ा गया था, इसे सुहार्तो के सत्तावादी शासन के दौरान सताया गया था, और फिर सुहार्तो–पश्चात् की अवधि के दौरान लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया में इसका पुनरुत्थान हुआ। कमजोर होने के बावजूद, सुहार्तो के दमनकारी शासन के दौरान श्रम आंदोलन ने शासन परिवर्तन और लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया में योगदान देने की चुनौती का सामना किया। यह आलेख तर्क देता है कि इंडोनेशिया में ट्रेड यूनियनों और अन्य श्रमिक–आधारित आंदोलनों, जो श्रमिकों के हितों की रक्षा में गठित हुए, सुहार्तो सत्तावादी शासन के खिलाफ लोकतंत्रीकरण के संघर्ष में प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडोनेशिया में लोकतांत्रिक सुधारों और शासन परिवर्तन की दिशा में आंदोलन में संगठित श्रम की भूमिका को समझना इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है कि कैसे सामाजिक ताकतें उभरती हैं और इंडोनेशिया के भीतर और बाहर सत्तावादी प्रथाओं के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करती हैं।

> प्रारंभिक श्रम आंदोलन

1894 से इंडोनेशिया में डच औपनिवेशिक सरकार के तहत श्रम संघों को अस्तित्व में आने और बढ़ने की अनुमति दी गई थी। श्रम संघ आंदोलन 100,000 से अधिक श्रमिकों तक बढ़ गया और 1940 के दशक में एक उग्रवादी, वामपंथी और स्वतंत्रता–समर्थक आंदोलन में विकसित हुआ। सुकर्णो, स्वतंत्रता के बाद के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो (1945 से 1967 तक सत्तारूढ़) को एक समाजवादी क्रांतिकारी माना जाता था, और उन्हें एक उग्र राजनीतिक श्रम आंदोलन, एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी (पार्टाई कोमुनिस इंडोनेशिया या पीकेआई), और एक तेजी से दक्षिणपंथी सैन्य संगठन, जिससे सुहार्तो आये थे, विरासत में मिला था। नतीजतन, सुकर्णो की सरकार के दौरान, वामपंथी झुकाव वाले ट्रेड यूनियन इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी और दक्षिणपंथी सेना के बीच राजनीतिक संघर्ष में फंस गए। सुकर्णो सरकार के तहत कम्युनिस्ट प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, सुहार्तो ने 1968 में तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया।

इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे खूनी विनाश के रूप में कथित, सुहार्तो के न्यू ऑर्डर शासन की स्थापना उन लगभग अनुमानित 500,000 की हत्या और एक मिलियन से अधिक की गिरफ्तारी पर की गई थी, जिन्हें पीकेआई के सदस्यों या उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले के रूप में पहचाना गया था। सुहार्तो सत्तावादी शासन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक संघर्ष के विस्फोट के दौरान पकड़े गए उग्रवादी और वामपंथी

>>

ट्रेड यूनियनों का भी सेना द्वारा सफाया कर दिया गया। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे खूनी तख्तापलट की राख में से एक दमित और राज्य–स्वीकृत श्रमिक आंदोलन उभरा। ट्रेड यूनियन आंदोलन का यह दमन और नियंत्रण दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी देश में सुहार्तो के सत्तावादी शासन (1968–1998) की स्थापना के लिए एक पूर्व–आवश्यकता बन गया।

> श्रम दमन और राज्य–स्वीकृत पंचसिला[2], औद्योगिक संबंध

दो दशकों से अधिक समय तक, इंडोनेशियाई संगठित श्रम सुहार्तो सत्तावादी शासन के नियंत्रण में रहा, जिसे पंचसिला श्रम संबंधों के तहत उचित ठहराया गया। बाद में पंचसिला औद्योगिक संबंधों के रूप में नामित, इस ढांचे ने एक समुदाय के भीतर सद्भाव की तलाश करने की इंडोनेशियाई–आधारित संस्कृति की प्रशंसा की, जैसे कि श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच वर्ग संघर्ष को गैर–इंडोनेशियाई और पंचसिला के सिद्धांतों के खिलाफ कार्य करने वाला माना जाता था। इस तरह के ढांचे मानने से के किसी भी प्रकार के श्रमिक विरोध, विशेष रूप से श्रमिक हड़ताल, की पहचान पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन करने और असामंजस्य को भड़काने के रूप में की गई।

पंचसिला औद्योगिक संबंधों ने इंडोनेशिया को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के सबसे निर्धन देशों की सूची से बाहर निकालने की सुहार्तो की आर्थिक रणनीति का समर्थन किया। सुहार्तो के न्यू आर्डर ने 1970 के दशक में तेल से राजस्व द्वारा समर्थित एक आयात–प्रतिस्थापन रणनीति के माध्यम से इंडोनेशिया के औद्योगीकरण की शुरुआत कीय 1970 के दशक के अंत में तेल संकट के बाद यह 1980 के दशक में निर्यात–उन्मुख विकास रणनीति में स्थानांतरित हो गया। इस रणनीति के परिणामस्वरूप 1980 के दशक से लेकर 1997 के एशियाई वित्तीय संकट तक तीव्र आर्थिक विकास हुआ। इस विकास के लिए कम मजदूरी वाले श्रम बाजार शासन में एक विनम्र ट्रेड यूनियन आंदोलन की आवश्यकता थी। हालाँकि, तीव्र औद्योगीकरण ने नई सामाजिक ताकतों को, औद्योगिक श्रमिकों को, जिन्होंने संगठित होने, सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने और ट्रेड यूनियनवादियों के खिलाफ हिंसा का प्रतिरोध करने की अधिक स्वतंत्रता की मांग की, को जन्म दिया। निर्यातोन्मुखी औद्योगीकरण रणनीति के तहत श्रम हिंसा और शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियों ने निष्क्रिय और राज्य–नियंत्रित श्रम संगठन से असंतुष्ट एक नए औद्योगिक श्रमिक वर्ग को पैदा किया। स्वतंत्र श्रम संघ प्रतिस्पर्धी श्रमिक आंदोलन की ओर बदलाव की शुरुआत करने वाली वाइल्ड कैट हड़तालों के साथ 1990 के दशक के प्रारम्भ से संगठित हो गए थे।

1994 में श्रमिक हड़तालें और प्रतिरोधों की श्रृंखला ने अशांत सत्ता–विरोधी *रिफॉर्मासी* (सुधारवादी) आंदोलन में योगदान दिया, जिसकी परिणति एशियाई वित्तीय संकट के दौरान सुहार्तो के निष्कासन में हुई। भले ही संगठित श्रम और सुधारवादी आंदोलन के मध्य औपचारिक सहयोग नहीं हुआ हो, इंडोनेशियाई श्रमिकों

श्रेय: IndustriALL Southeast Asia.

और श्रम संघों ने लोकतंत्रीकरण आंदोलन के लिए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, इनपुट प्रदान किया, जिसने सत्ता परिवर्तन किया। श्रमिक संघ या संगठित श्रमिक, और श्रमिकों के हितों की रक्षा में गठित अन्य श्रमिक–आधारित श्रमिक आंदोलन, सभी इंडोनेशियाई श्रमिक आंदोलन का हिस्सा हैं। सुहार्तो के सत्तावादी शासन के खिलाफ व्यापक लोकतंत्रीकरण आंदोलनों से जुड़े होने पर यह श्रम आंदोलन मजबूत हुआ।

> निष्कर्ष

इंडोनेशियाई श्रमिक आंदोलन राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में परिवर्तन से प्रभावित होकर अलग–अलग चेहरों और चरणों से गुजरा है और विकसित हुआ है। सुहार्तो के दमनकारी श्रम शासन में ट्रेड यूनियनों को कमजोर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने सत्ता परिवर्तन में योगदान दिया जब श्रमिकों ने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की, जैसे कि संघ की स्वतंत्रता, ऐसे अधिकार जो केवल एक लोकतांत्रिक वातावरण में पनप सकते हैं। उत्पादन संबंधों में बदलाव ने नई सामाजिक ताकतों को जन्म दिया, जैसे कि औद्योगिक श्रमिक वर्ग, शहरी पेशेवर और श्रमिक–आधारित हित समूह जो व्यापक लोकतंत्रीकरण आंदोलन का हिस्सा बने। 1997 के चौंकाने वाले एशियाई वित्तीय संकट के बाद श्रमिक और छात्र आंदोलन सुहार्तो विरोधी आंदोलन का अहम् हिस्सा बने। इंडोनेशिया ने सरकार के सबसे नाटकीय पतन और एक सत्तावादी नेता को हटाने का गवाह बना, जब 1998 में सुहार्तो को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि सैन्य टैंकों ने मध्य–रात्रि में उनके आवास को घेर लिया था। राष्ट्रवादी पंचसिला विचारधारा द्वारा समर्थित सुहार्तो की न्यू ऑर्डर सरकार के पतन ने इंडोनेशिया के लिए राजनीति के एक नए युग के प्रारम्भ का संकेत दिया। ■

सभी पत्राचार वर्ना दिनाह क्यू. वियाजर को <vqviajar@up.edu.ph> पर प्रेषित करें।

1. यह काम रोजा लक्जमबर्ग स्टिफ्टंग–बर्लिन के इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप ऑन ऑथोरिटेरियनिज्म एंड काउंटर–स्ट्रेटेजीज (आईआरजीएसी) में पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप के जरिए संभव हुआ। सुश्री वियाजर वर्तमान में विजिटिंग रिसर्च फेलो के रूप में स्कूल ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस डिलिमैन (यूपी सोलायर) में कार्यरत हैं।

2, पंचसिला एक राजनीतिक ढांचा है जिसे शुरू में औपनिवेशिक स्वतंत्रता नेता सुकर्णो ने देश को एकजुट करने के लिए आगे बढ़ाया था। यह मानवतावाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर स्थापित है। सुहार्तो ने इस लोकप्रिय राजनीतिक विचार को वैधता हासिल करने के लिए विनियोजित किया।

> लैंगिक व्यवस्था का भविष्य

सिल्विया वाल्बी, सिटी, लंदन विश्वविद्यालय, यूके, हिंसा और समाज पर आईएसए के थीमेटिक ग्रुप (टीजी 11) की सह–समन्वयक और अर्थव्यवस्था और समाज (आरसी 02) पर आईएसए शोध समिति की सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष और महिला, लिंग एवं समाज (आरसी 32) की सदस्य और **करेन शायर**, यूनिवर्सिटी ड्यूसबर्ग–एसेन, जर्मनी और आईएसए शोध समिति (आरसी 02) की उपाध्यक्ष द्वारा

वैश्विक स्तर पर लिंग मायने रखता है। आलेखों का यह समूह मैक्रो स्तर पर वैश्विक विश्लेषण के लिए आवश्यक लिंग संबंधों के बारे में नई सोच को संबोधित करता है। वे लैंगिक व्यवस्था की किस्मों को सिद्धांतित करने के सर्वोत्तम तरीके पर बहस करते हैं। वे वर्ग के विश्लेषण में एक अन्तर्विभाजक लेंस जोड़ते हैं, जो अब तक समाजशास्त्र में वैश्विक के मैक्रो–स्तरीय विश्लेषण का मुख्य केंद्र रहा है। वे लिंग के विश्लेषण में एक मैक्रो स्तर जोड़ते हैं, जिसका अब तक मुख्य रूप से सूक्ष्म और मेसो स्तरों पर विश्लेषण किया गया है।

2020 में *सोशल पॉलिटिक्स* में आयोजित एक बहस से आलेख विकसित होते हैं कि कैसे मौजूदा संकट को दूर करने के लिए लैंगिक व्यवस्था के स्वरूपों के सिद्धांतों को विकसित किया जाए और इसमें वैश्विक दक्षिण के साथ साथ वैश्विक उत्तर को और अधिक कड़ाई से शामिल किया जाए। लैंगिक संबंधों पर संकटों, विशेष रूप से COVID संकट के प्रभाव को सैद्धांतिक रूप कैसे दिया जाए? क्या सार्वजनिक लैंगिक व्यवस्था की किस्में उत्तर की तुलना में वैश्विक दक्षिण में भिन्न हैं?

आधुनिकता, या यों कहें, अनेक उलझी हुई आधुनिकताएँ किस प्रकार से लिंगबद्ध हैं? समाजशास्त्रीय सिद्धांत में बहस का एक मुख्य मुद्दा, आधुनिकता की तरफ महान परिवर्तन, लैंगिक कैसे है? सामाजिक संबंधों के घरेलू रूप क्या स्वाभाविक या आकस्मिक रूप से आधुनिक या पूर्व आधुनिक हैं? लैंगिक व्यवस्था के स्वरूपों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या लैंगिक व्यवस्था के घरेलू और सार्वजनिक रूपों के मध्य है? क्या वैश्विक उत्तर में पाए जाने वाले लैंगिक व्यवस्था के नवउदारवादी और सामाजिक लोकतांत्रिक स्वरूपों के बीच का अंतर क्या आम तौर पर लागू होता है, या वैश्विक दक्षिण में लैंगिक व्यवस्था के सार्वजनिक स्वरूपों के बीच अलग–अलग भेद हैं?

लैंगिक व्यवस्था लिंग को परिवार तक सीमित करने वाली पारम्परिक व्यवस्था को चुनौती देती है। लैंगिक व्यवस्था समाज में कई संस्थागत डोमेन द्वारा गठित की जाती है। डोमेन की सीमा पर बहस होती है: कभी–कभी इसमें अर्थव्यवस्था, राजनीति, नागरिक समाज और हिंसा सम्मिलित होते हैंय जबकि अन्य बार कई अतिरिक्त डोमेन सम्मिलित होते हैं।

हिंसा, जिसे व्यापक रूप से अनुभवजन्य रूप से लिंग संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसे शायद ही कभी मूल समाजशास्त्रीय सिद्धांत में एकीकृत किया जाता है, को कैसे संबोधित किया जाना चाहिए? क्या अर्थव्यवस्था, राजनीति और नागरिक समाज के साथ–साथ हिंसा चौथा संस्थागत क्षेत्र है? वृहद स्तर पर लिंग के सैद्धांतिकरण के लिए इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता है। बहुत बार, वृहद स्तर को एक अलैंगिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में सैद्धांतिकृत किया गया है। हिंसा के सैद्धांतिकरण पर बहस में यहां के आलेख अलग–अलग रुख अपनाते हैं। कुछ लोग हिंसा को एक प्रमुख संस्थागत डोमेन के रूप में मानते हुए, वैश्विक स्तर पर लेंगिकता के बारे में वृहद स्तरीय सोच के लिए हिंसा के महत्व को मान्यता देने के लिए तर्क करते हैं जबकि अन्य डोमेन में हिंसा फैलाने के लिए।

देखभाल के संयोजन में नए घटनाक्रम सामाजिक सिद्धांत को चुनौती देते हैं जो परंपरागत रूप से अर्थव्यवस्था को श्रम के बाजारीकृत रूपों तक सीमित कर देता है। देखभाल का काम अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, चाहे उसका भुगतान किया गया हो या अवैतनिक हो। अर्थव्यवस्था के सामाजिक संबंधों में घरेलू संबंधों के साथ–साथ पूंजी और श्रम के मध्य के संबंध भी सम्मिलित हैं।

एक ही क्षेत्र में कई अलग–अलग लिंग वाली राजनीति अक्सर सह–अस्तित्व (और प्रतिस्पर्धी) होती है: ''राष्ट्रीय'' राज्य, यूरोपीय संघ (या अन्य आधिपत्य), संगठित धर्म (जैसे कैथोलिक चर्च)। उनके पास लैंगिक लोकतंत्र की अलग–अलग गहराई है, इसलिए उनके बीच शक्ति संतुलन लिंगबद्ध है।

लिंग संबंधों को फिर से बढ़ाया जा रहा है। वैश्विक लैंगिक देखभाल श्रृंखलाओं को मैक्रो स्तर के साथ–साथ मेसो और माइक्रो स्तर के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। उन्हें पूंजीवाद और लैंगिक व्यवस्था के भिन्न रूपों के प्रतिच्छेदन के विश्लेषण की आवश्यकता है; प्रवास की; और पद्धतिगत राष्ट्रवाद के लिए विशेष रूप से लैंगिक चुनौतियों की। कोई भी राष्ट्र–राज्य समाज ऐसा नहीं है जिसमें सभी सामाजिक डोमेन संरेखित हों। लिंग संबंधों के पुनर्विक्रय में स्थानीय (देखभाल प्रावधान के नए रूप, राजनीतिक परियोजना के नए रूप), और (होगा) आधिपत्य (यूरोपीय संघ और चीन, साथ ही अमेरिका) शामिल हैं। आलेख समय और स्थान के साथ लैंगिक व्यवस्था के प्रक्षेपवक्र के बारे में सोचने के विभिन्न तरीकों की पेशकश करते हैं, संयुक्त और असमान विकास के अलग–अलग लैंगिक स्वरुपों के रूप में।

आलेखों के इस समूह द्वारा सम्बोधित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि क्या कोविड संकट लैंगिक व्यवस्था में बदलाव ला रहा है। एक ओर, बीमारियाँ, अनावश्यक मृत्यु और अलोकतांत्रिकीकरण की प्रक्रियाएँ हैं। दूसरी ओर, एकजुटता और प्रगतिशील परियोजनाओं के नए स्वरुप हैं।

आलेख इन विषयों को संबोधित करते हैं। सिल्विया वाल्बी यह

> >

''लिंग व्यवस्था की अवधारणा परिवार में लिंग की पारंपरिक कटौती को चुनौती देती है। समाज में लिंग व्यवस्था कई संस्थागत डोमेन द्वारा गठित की जाती है''

बताती हैं कि हिंसा को चौथे संस्थागत डोमेन के रूप में कैसे सिद्ध ांतित किया जा सकता है, और लैंगिक व्यवस्था के विभिन्न स्वरुप हिंसा को किस प्रकार तैनात और नियंत्रित करते हैं । करेन शायर संबोधित करती हैं कि कैसे रूढ़िवादी लिंग व्यवस्था की चारित्रिक विशेषता वाली पारिवारिक नीतियां, एक ऐसे परिवर्तन में जो न तो उदार है और न ही सामाजिक–लोकतांत्रिक, देखभाल श्रम के लैंगिक विभाजन को मौलिक रूप से बदलने में विफल रहती हैं। मिके वेरलू इस अवधारणा के लिए बहस करने के बजाय कि समाज शरीर, कामुकता और नातेदारी को कैसे व्यवस्थित करता है, परिवार से हमारा क्या मतलब है, स्पष्ट करने के लिए बहस करते हैं। वे दक्षिण पंथ की तरफ ''लिंग–विरोधी'' झुकाव को अंतरंग संबंधों के वि–परम्परिकरण से मुकाबला के रूप में देखते हैं जैसा हंगरी और पोलैंड में प्रजनन अधिकारों और यौन स्वायत्तता पर हमलों में देखा गया। हेइडी गॉटफ्रीड और करेन शायर जापान और जर्मनी में परिवर्तन के प्रक्षेपवक्र के तुलनात्मक क्षेत्रीय विश्लेषण में लिंग संबंधों में सुधार को संबोधित करते हैं। वैलेंटाइन एम. मोघदम का तर्क है कि ईरान और ट्यूनीशिया में कई नारीवादी लाभों के उलटफेर को तभी समझा जा सकता है, जब विश्व व्यवस्था सिद्धांत से प्रेरणा ले कर, हम इस बात पर ध्यान दें कि आर्थिक परिधि और अर्ध–परिधीय देशों में आर्थिक संकट और आधिपत्य शक्तियों के प्रतिच्छेदन से कैसे प्रभावित होते हैं। ट्यूनीशिया में महिलाओं के अधिकारों में उलटफेर का श्रेय विश्व आर्थिक संकटों के लिए अर्ध–परिधि के अत्यधिक जोखिम को दिया जाता है, जबकि ईरान पर अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंध उस देश में लिंग लाभ के उलट होने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे कोसाबिकाक तुर्की लैंगिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मक राज्य की प्रकृति में परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। अल्बा अलोंसो, रोसेला सिसिया और इमानुएला लोम्बार्डो द्वारा इटली और स्पेन के विश्लेषण से पता चलता है कि दक्षिणी यूरोप एक एकीकृत क्षेत्र नहीं है, इसमें दोनों देशों की लैंगिक व्यवस्थाओं में बड़े अंतर हैं जो कि राजनीति और नागरिक समाजों की परस्पर क्रिया से उभरे हैं। रोबर्टा गुएरिना, हीथर मैकरे और एनिक मैसेलॉट यूरोपीय संघ को एक विशिष्ट लैंगिक व्यवस्था के रूप में सिद्धान्तित करते हैं, जो एकल बाजार परियोजना द्वारा उत्पन्न लैंगिक और नस्लीय असमानताओं को दूर करने में विफल रही हैं, और जो बहुल प्रकार के संकटों से बढ़ी है, जिनमें से नवीनतम कोविड है। ■

सभी पत्राचार सिल्विया वाल्बी को <Sylvia.Walby@city.ac.uk> पर प्रेषित करें।

> क्या लिंग व्यवस्था की नई किस्में उभर रही हैं?

सिल्विया वाल्बी, सिटी, लंदन विश्वविद्यालय, यूके, हिंसा और समाज पर आईएसए के थीमेटिक ग्रुप (टीजी 11) की सह–समन्वयक और अर्थव्यवस्था और समाज (आरसी 02) पर आईएसए शोध समिति की सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष और महिला, लिंग एवं समाज (आरसी 32) की सदस्य द्वारा

लिंग व्यवस्था की उभरती हुई किस्मों के आलोक में तीन मुद्दों पर सवाल उठाने और उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है: हिंसा, देखभाल में असमानता और संकट की अवधारणा। (चित्र 1) श्रेय: संकट का सौंदर्यशास्त्र/फ्लिकर, (चित्र 2) श्रेय: जॉन टूहिग/फ्लिकर, (चित्र 3) श्रेय: संकट का सौंदर्यशास्त्र/फ्लिकर।

लैंगिक व्यवस्थाओं के उभरते हुए रूपों और उन प्रक्षेपवक्रों की पहचान जिनके माध्यम से उन्होंने लिंग संबंधों और समाज के लिए मामलों को विकसित किया है, जैसा कि मैंने और मेरे सहयोगियों ने 2020 में *Social Politics* के विशेष अंक में तर्क दिया है। जहाँ अधिकांश ध्यान लिंग व्यवस्थाओं के बढ़ते असमान रूपों पर रहा है, ऐसी उभरती प्रथाएं भी हैं जो कम असमान लिंग व्यवस्थाओं का संकेत हो सकती हैं। कुछ समाजों (लेकिन सभी नहीं) पर ऐसे दबाव रहे हैं जो लैंगिक असमानता में वृद्धि करते हैं; इन दबावों में कोविड, ब्रेक्सिट और ट्रम्प के साथ–साथ आर्थिक मंदी भी सम्मिलित है। सामूहिक प्रतिक्रिया के ऐसे रूप भी हैं जो, राज्य–आधारित (जैसे, सार्वजनिक स्वास्थ्य) और गैर–राज्य–आधारित (जैसे, नारीवाद) रूपों सहित, लिंग असमानता में कमी लाते हैं। ये हिंसा, देखभाल, नारीवाद और लिंग और वर्ग के प्रतिच्छेदन के मुद्दों को उठाते हैं। लैंगिक व्यवस्था के स्वरूपों पर बहस के संदर्भ में, इन दबावों और संकटों ने क्या बदला या आलोकित किया? इन परिवर्तनों को शामिल करने के लिए हमें लिंग व्यवस्था के स्वरूपों के वर्गीकरण में कौन से नए भेद, यदि कोई हैं, बनाने की आवश्यकता है? अर्थव्यवस्था, राजनीति, नागरिक समाज और हिंसा के क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रक्षेपवक्रों की ओर जाने वाली प्रक्रियाओं को सबसे अच्छी तरह से कैसे समझा जाता है? हो रहे परिवर्तनों पर विचार करने के लिए और क्या आवश्यक है: क्या संकट और महत्वपूर्ण बदलाव बिंदु की अवधारणा पर्याप्त है, या क्या इसमें विभिन्न अस्थायिता और स्थानिकता सम्मिलित हैं जिनके लिए नई अवधारणाओं की आवश्यकता होती है? तीन व्यापक प्रश्नों की पहचान की जा सकती है।

प्रथम, क्या बढ़ती असमानता का विश्लेषण करने के लिए ''नवउदारवाद'' एक पर्याप्त अवधारणा है? दक्षिणपंथ की तरफ झुकाव और असमानता में संबंधित वृद्धि को कैसे पहचाना और उसे सिद्धान्तित कैसे किया जाता है? क्या ''रूढ़िवाद,'' ''अधिनायकवाद,'' या ''फासीवाद'' की अवधारणाओं की आवश्यकता है? हिंसा में वृद्धि के संबंध में, लिंग व्यवस्था के स्वरूपों के भीतर हिंसा के सिद्धांत को नए सिरे से पेश किया गया है। क्या राज्य के सत्तावादी के रूप में चरित्र–चित्रण की आवश्यकता है, या क्या इस हिंसा को अभी भी नवउदारवादी की अवधारणा के भीतर समाहित किया जा सकता है? क्या राज्य की मिलीभगत से काम कर रहे निजी लड़ाकों के उदय के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में फासीवाद की अवधारणा की आवश्यकता है, दोनों नागरिक समाज और राज्य के भीतर से निरंतर संघर्ष इस संभावना को प्राप्त करने से रोकने के लिए पर्याप्त है या

> >

नहीं? कोविड–19 परः क्या लाभार्जन वाली निजी फर्मों की दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के प्रयास के लिए न केवल नवउदारवाद की अवधारणा की आवश्यकता है, बल्कि वर्ग के साथ लिंग के प्रतिच्छेदन की अधिक संलग्न चर्चा की आवश्यकता है?

दूसरा, घटती असमानता का विश्लेषण करने के लिएः क्या उभरती हुई प्रथाओं को समझने के लिए सामाजिक लोकतंत्र पर्याप्त है? क्या सामाजिक लोकतांत्रिक लिंग व्यवस्थाओं के नए रूप हैं जिनका नॉर्डिक देशों में ऐतिहासिक रूप की तुलना में एक राष्ट्रीय राज्य से अलग संबंध है? क्या अवधारणाओं को सामाजिक लोकतांत्रिक रूपों के बीच अंतर करने की आवश्यकता हैः सामूहिकता और एकजुटता के विभिन्न रूपों को शामिल करते हुए राज्य और गैर–राज्य (सामान्य, समुदाय, पड़ोस, स्थानीय)? कोविड परः एक ओर, कोविड संकट एक बार फिर वायरस को दबाने में राज्य–आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य द्वारा निभाई गई केंद्रीय भूमिका में सामाजिक लोकतंत्र के राज्य–आधारित रूपों के महत्व को दर्शाता है। दूसरी ओर, स्थानीय राज्य स्तर पर प्रभावी परीक्षण, अनुरेखण और पृथक्करण के लिए समर्थन को लागू करने के लिए ज्ञान और कार्रवाई की आवश्यकता है। देखभाल प्रदान करने और प्राप्त करने वालों के द्वारा भौतिक और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से वायरस के संचरण को संबोधित करने की अपेक्षाकृत विफलता ने यह तय किया कि क्या यह देखभाल अवैतनिक या मुद्रीकृत है, कम से कम ऐसा यूरोप में तो था। उन्होंने यह सुझाव दिया कि देखभाल पर लिंग संबंधी बहस में कुछ भेद हैं जिनका आश्चर्यजनक रूप से कोविड पर कम कर्षण है। यह कई प्रश्न उठाता हैः देखभाल के प्रावधान पर नारीवादी हस्तक्षेपों का लिंग व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम देखभाल संबंधों में उभरती प्रथाओं को कैसे सैद्धान्तित कर सकते हैं? लिंग व्यवस्था में स्थानिकता और स्केलिंग का सिद्धांत कैसा दिखेगा?

तीसरा, संकट परः क्या संकट के परिणामों का वर्गीकरण(स्वास्थ्य लाभ, तीव्रता, परिवर्तन, या तबाही) पर्याप्त है? क्या एक संभावित बदलाव बिंदु के रूप में महत्वपूर्ण क्षण की संकल्पना पर्याप्त है ? नारीवाद के असमान प्रभाव को कैसे समझा जाना चाहिए? एक नए पथ–निर्माण प्रक्षेपवक्र में महत्वपूर्ण बदलाव बिंदु या टिप्पिंग बिंदु के बदलाव को आमतौर पर एक ''घटना'' के रूप में माना जाता है, मुख्यतः इस आधार पर कि इसकी एक छोटी अस्थायी अवधि और केंद्रित स्थानिकता है। तीन संभावित वैकल्पिक फॉर्मूलेशन जो और भेद प्रदान करते हैं, वह हैंः ''कैस्केड,'' ''उत्प्रेरित,'' और ''लहर।'' कैस्केड की अवधारणा में संकट बिंदुओं के अनुक्रम का संदर्भ है जिसमें संकट समाज की सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से कैस्केड हो भी सकता है या नहीं भी; इसका उपयोग 2008 के वित्तीय संकट और 2020–21 के कोविड–19 संकट के लिए किया गया है। उत्प्रेरित की अवधारणा में, आमतौर पर घटना की अवधारणा में शामिल की तुलना में थोड़ी अधिक लंबी अवधि का संदर्भ है; इसमें अनुक्रम और कैस्केड के अलावा सर्पिल की धारणा से जुड़े त्वरण का विचार शामिल है, जिसका उपयोग नॉर्डिक देशों में बीसवीं शताब्दी के मध्य में सार्वजनिक लैंगिक व्यवस्था के सामाजिक लोकतांत्रिक रूपों के विकास को पकड़ने के लिए किया गया है। लहर में, परिवर्तन की एक गतिशील शक्ति होती है (उदाहरण के लिए, वैश्विक नारीवाद) जो अधिक स्थिर संस्थागत रूपों को प्रभावित करती है, जिसमें परिणाम उनके मध्य अंतर्क्रिया पर निर्भर होते हैं। ये परिणाम ''पुनर्गठन के दौर'' की अवधारणा से प्रेरणा लेते हैं जो बेहतर स्थानिकता के साथ साथ परिवर्तन के कालिक सूक्ष्मांतरों की पेशकश करते हैं।

ऊपर उल्लिखित तीन मुद्दे 2020 में सामाजिक राजनीति में लिंग व्यवस्था के स्वरूपों पर बहस और समकालीन सामाजिक विकास के साथ जुड़ाव की पेशकश करते हैं। ■

सभी पत्राचार सिल्विया वाल्बी को <Sylvia.Walby@city.ac.uk> पर प्रेषित करें।

> परिवार में समाहित : रूढ़िवादी लिंग व्यवस्था

करेन शायर, ड्यूसबर्ग–एसेन विश्वविद्यालय, जर्मनी, और अर्थव्यवस्था और समाज पर आईएसए अनुसंधान समिति (आरसी 02) के उपाध्यक्ष द्वारा

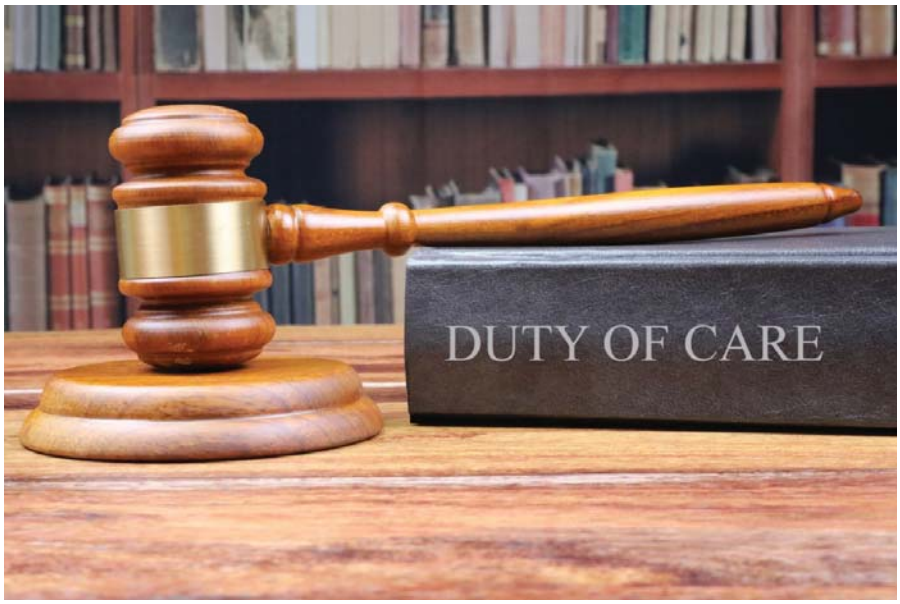

जब महिलाओं के देखभाल के बोझ को कम करने के मुद्दे को परिवार नीति के रूप में, और परिवारों में महिलाओं के समर्थन को बेहतर कार्य–पारिवारिक संतुलन को सक्षम करने के रूप में तैयार किया गया है तो देखभाल करने का कर्तव्य किसका है? श्रेय: निक यंगसन / क्रिएटिव कॉमन्स

लैंगिक व्यवस्था सिद्धांत सार्वजनिक लैंगिक व्यवस्थाओं के विकास के लिए दो आदर्श–प्रकार के प्रक्षेप पथों की कल्पना करता है। पहला एक नवउदारवादी प्रक्षेपवक्र है, जहां महिलाओं के लिए पुरुषों के साथ बराबर की स्थिति हासिल करने के अवसर प्रतिस्पर्धी बाजारों में उनकी समान पहुंच के द्वारा खोले जाते हैं। यह प्रक्षेपवक्र मोटे तौर पर उन तरीकों की उपेक्षा करता है जिनमें अवैतनिक श्रम का लिंग विभाजन और श्रम का लिंग आधारित पृथक्करण महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है। सामाजिक–लोकतांत्रिक प्रक्षेपवक्र लैंगिक समानता को सभी नीतियों, सबसे महत्वपूर्ण, देखभाल नीतियां और अन्य सामाजिक सुरक्षा में जो रोजगार सुरक्षा को समान करती हैं और महिलाओं को राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व में समान भागीदारी की गारंटी देती हैं, के लक्ष्य के रूप में स्थापित करता है।

वास्तविक मामलों के संदर्भ में, अमेरिका नवउदारवादी लिंग व्यवस्था के सबसे करीब आता है, और स्वीडन सामाजिक–लोकतांत्रिक आदर्श के सबसे करीब है। दोनों मामले एक अन्य मामले में समान हैं– उनकी लैंगिक व्यवस्था का विकास आधुनिकीकरण के लोकतांत्रिक मार्गों में अंतर्निहित है। *Social Politics* (2020) में लैंगिक व्यवस्थाओं के स्वरूपों पर विशेष अंक में कुमिको नेमोतो और मैंने एक लेख में तर्क दिया कि लोकतांत्रिक आधुनिकीकरण के ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित आदर्श प्रकार सत्तावादी आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहे देशों की विशिष्टताओं की उपेक्षा करते हैं। सत्तावादी आधुनिकीकरण के दो मामलों –जर्मनी और जापान में लिंग व्यवस्था के ऐतिहासिक गठन के हमारे विश्लेषण में हमने तर्क दिया कि पुरुष–नेतृत्व वाले घरों में महिलाओं को अधीनस्थ करने और परिवार–घरेलू इकाई को राष्ट्रवादी और सैन्यवादी हितों की सेवा में संलग्न एक सार्वजनिक सामाजिक संस्था के रूप में स्थापित करने में परिवार कोड महत्वपूर्ण थे। परिवार में लिंग पदानुक्रम के कानूनी एम्बेडिंग के बारे में इसी तरह के तर्क MENA क्षेत्र (मोघदम), तुर्की (कोकाबीकाक), और स्पेन (अलोंसो और लोम्बार्डो) में सत्तावादी आधुनिकीकरण के अन्य मामलों के लिए *Social Politics* के ही विशेष अंक में दिए गए हैं।

> जर्मनी और जापान में परिवार नीति

1945 में सैन्य हार और विदेशी अधिग्रहण के बाद लोकतंत्रीकरण के दौरान जर्मनी और जापान में परिवार संहिताओं में सुधार ने घरेलू लिंग व्यवस्था को बड़े पैमाने पर अमेरिका के उदार–बाजार मॉडल के अनुसार, लेकिन पूरी तरह से नहीं, स्थापित किया। राष्ट्र की सहायक इकाई के रूप में परिवार के घर के भीतर लिंग पदानुक्रम को कल्याण और रोजगार नीति में पुनर्गठित किया गया था, जिसे जेंडर विद्वानों ने पुरुष पालनकर्ता मॉडल कहा है। 1970 के दशक में दूसरी लहर के नारीवादी आंदोलन ने रूढ़िवादी परिवार के गठन के कई अवशेषों में , उदाहरण के लिए विरासत और तलाक कानून में, सुधार हासिल किया। हालांकि, जो बच गया है वह है देखभाल एवं कर के लिए पारिवारिक जिम्मेदारी और पुरुष पालनकर्ता परिवार के स्वरुप के लिए सामाजिक नीति समर्थन। यद्यपि अब ये सत्तावादी नहीं रहीं, 2000 के दशक में ये लैंगिक व्यवस्थाएं रूढ़िवादी बनी रहीं। ऐसा तब हुआ जब तेजी से उम्र बढ़ने, कम प्रजनन क्षमता और श्रम आपूर्ति में गिरावट ने रूढ़िवादी राजनैतिक नीतियों को सामाजिक और लोकतान्त्रिक ताकतों के साथ देखभाल के सामाजिक संगठन में सुधार लाने और महिलाओं की रोजगार दरों को बढ़ाने के लिए को संरेखित किया।

> >

हालाँकि, स्वीडिश सामाजिक–लोकतांत्रिक लिंग व्यवस्था इन सुधारों के लिए आदर्श नहीं थीय न ही, मेरा तर्क है, ये हो सकती थीं। कई महाद्वीपीय यूरोपीय देशों की तरह, जर्मनी और जापान में सामाजिक कल्याण को सामाजिक बीमा के लिए आय में कटौती के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, और परिवार के आश्रित सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह कल्याणकारी मिश्रण परिवारों में महिलाओं को अवैतनिक देखभाल के लिए उपलब्ध कराना जारी रखता है। टैक्स फंडिंग और सार्वजनिक सुविधाओं के स्वीडिश समाधान को भी यह राजनीतिक रूप से अव्यहारिक बनाता है। इसके बजाय, महिलाओं के देखभाल के बोझ को कम करने का मुद्दा *परिवार* नीति के रूप में, और परिवारों में महिलाओं के समर्थन को बेहतर कार्य – *पारिवारिक* संतुलन को सक्षम करने के रूप में तैयार किया गया है। दोनों देशों में, परिवार नीति ने बच्चे के सामाजिक पुनर्गठन और बुजुर्गों की देखभाल में हस्तक्षेप किया है। हालाँकि किसी में भी, स्वीडन की तरह पारिवारिक नीति ने देखभाल का समाजीकरण नहीं किया है, या अवैतनिक देखभाल श्रम के लैंगिक विभाजन को बिगाड़ा है।

परिवार नीति ने क्या अर्जित किया हैं? परिवार नीति का लैंगिक तर्क तब स्पष्ट होता है जब देखभाल के सबसे चरम रूपों – शिशु और बुजुर्ग, जो अपने बलबूते पर जीवित नहीं रह सकते हैं, पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जर्मनी और जापान दोनों में, पारिवारिक नीतियों ने दोनों प्रकार की देखभाल को परिवार में ही समाहित किया है ।

प्रारंभिक शिशुपालन के विस्तार के कार्यक्रम एक से दो वर्ष की आयु के अधिकांश बच्चों को कवर करने में विफल रहे हैं। जर्मनी में, जहां यूरोपीय संघ के दबावों ने सुधारों का नेतृत्व किया, इस आयु वर्ग (34: कवरेज तक) की देखभाल में धीमा विस्तार ''डे मदर्स'' द्वारा देखभाल के प्रावधान का विस्तार करने के उपायों द्वारा पूरा किया गया, जिसने महिलाओं की भूमिका को छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, यद्यपि अन्य परिवारों में, पुनः मजबूत किया है। जापान में, महिलाओं को, यदि वे चाइल्डकैअर सुविधा में स्थान पाने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं, अब अपने मातृ अवकाश को एक वर्ष से आगे बढ़ाने की अनुमति है ।

बुजुर्गों की देखभाल में दोनों देशों ने 20 साल पहले दीर्घकालिक देखभाल बीमा पेश किया था। हालांकि, एल्डरकेयर सेवाओं के लिए बनाए गए नए बाजार स्पष्ट रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल को सामाजिक बनाने के बजाय पूरक करने का उद्देश्य रखते हैं। सामाजिक देखभाल के बजाय निजी बाजार सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य का समर्थन लिंग संबंधों में परिवर्तन के एक नवउदारवादी प्रक्षेपवक्र का सुझाव देता है।

> एक व्यवहार्य सामाजिक–लोकतांत्रिक विकल्प की खोज

क्या नवउदारवादी सार्वजनिक लिंग व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है? उत्तर की खोज सामाजिक–लोकतांत्रिक लिंग व्यवस्थाओं के स्वीडिश रूप के विकल्पों से सम्बंधित है। इस खोज में, कम से कम प्रारंभिक बिंदु स्पष्ट हैः लैंगिक समानता के लक्ष्य से सूचित एक नवीन नैतिक अर्थव्यवस्था द्वारा सामाजिक देखभाल की एक बुनियादी इकाई के रूप में वैवाहिक/जैविक परिवार का गैर–परम्परिकीकरण और क्षरण।

जर्मनी और जापान में, 1968 के छात्र और नारीवादी आंदोलनों में अंतरंग संबंधों को पुनर्गठित करने के प्रयोगों के लिए, परिवार के बाहर बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल के वैकल्पिक रूपों को बनाने के लिए राज्य सब्सिडी और बीमा प्रीमियम पर रचनात्मक कब्जा करने का प्रमाण है। जर्मनी में, किराये के स्थानों में डे फादर देखभाल के साथ डे मदर्स सहकारी समितियां और वृद्धजन–रहवास की स्थितियां जहाँ वृद्ध अपने बीमा प्रीमियम को एकत्रित कर अपने लिए देखभाल प्रदाता को नियुक्त करते हैं, इसके उदाहरण हैं। जापान में उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल और वैतनिक महिलाओं और अधिकाधिक पुरुषों को भी देखभाल प्रदाता के रूप में अच्छा कार्य उपलब्ध कराने वाली महिला नेतृत्व वाली गैर–लाभकारी संस्थाएं न सिर्फ वृद्धजन देखभाल में अधिक दृष्टिगोचर हैं, बल्कि प्रारंभिक शिशु पालन में भी।

रूढ़िवादी लिंग व्यवस्थाओं में लिंग संबंधों के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यवहार्य सामाजिक–लोकतांत्रिक विकल्प की तलाश, जिस तरह हम जानते हैं, उसकी *परिवार के अंत* से प्रारम्भ होने की सम्भावना है। ■

सभी पत्राचार करेन शायर को <Karen.shire@uni-due.de> पर प्रेषित करें।

> क्या हम यूरोप में लिंग व्यवस्था में बदलाव देख रहे हैं?

मिके वेरलू, रेडबौड विश्वविद्यालय, नीदरलैंड द्वारा

हैशटैग # पाइक्लोकोबीट (महिलाओं के लिए नरक) पोलैंड में गर्भपात तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले नए कानूनों के विरोध का प्रतीक बन गया है। श्रेयः LukaszKatlewa /Wikimedia Commons.

पिछले कुछ दशकों में जेंडर विरोधी अभियानों में तेजी आयी है। ये पूरे यूरोप में फैले हैं जिससे इनमें शामिल लोगों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा उन महत्वपूर्ण मुद्दों का भी विस्तार हो रहा है जो नारीवादी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अब हमें प्रतिक्रियावादी रणनीतियों की जगह भी सक्रिय रणनीतियां दिखायी दे रही हैं जो एक चिंताजनक बदलाव है। ये अभियान महिला विमर्श के मुद्दों के एक विशिष्ट समूह को निशाना बना रहे हैं, खासकर उन मुददों को जो 70 के दशक की नारीवादी परियोजनाओं में रेडीकल नारीवाद द्वारा प्राथमिकता पर रखे गए थे जैसे कि यौन और लिंग को अनावश्यक करार करना, शारीरिक और यौन स्वायत्तता, प्रजनन का अधिकार तथा सेक्स, जेंडर और विषमलैंगिकता से जुड़े सार्वभौमिक सिद्धांतों की जांच करना। यह सब पूरे यूरोप में बढ़ते अधिनायकवाद के संदर्भ में है। लोकलुभावन आंदोलन में लिंग–विरोधी–राजनीति पर चर्चा करते हुए एग्निज़्का ग्रैफ और एल्बिएटा कोरोलजुक की नई पुस्तक इस मुददे पर एक बड़ी बहस का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। मैं यहां यह जानने का प्रयास कर रही हूँ कि क्या ये हमले यूरोप की लिंग व्यवस्था में बदलाव के संकेत हैं जिन्हें समझने के लिए लैंगिक व्यवस्था सिद्धांत के विस्तार की आवश्यकता है।

नारीवादी चिंतक वाल्बी के जेंडर–शासन सिद्धांत में जेंडर व्यवस्थाएं असमानता की जटिल प्रणालियां हैं जो इस बात से अलग हैं कि कैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, हिंसा और नागरिक समाज के विशिष्ट विन्यास लैंगिक असमानता पर प्रभाव डालते हैं। वे घरेलू और सार्वजनिक जेंडर शासनों के मध्य, और सार्वजनिक जेंडर शासन के अंतर्गत, नवउदार एवं सामाजिक लोकतान्त्रिक स्वरूपों के मध्य अंतर करती हैं। घरेलू और सार्वजनिक जेंडर व्यवस्थाओं के मध्य भेद राजव्यवस्था की प्रकृति में अंतर पर आधारित है। घरेलू जेंडर व्यवस्थाओं में राज व्यवस्था एक कमजोर राज्य और परिवार एवं नातेदारी व्यवस्थाओं पर आधारित पुरुष पितृसत्ताओं के लिए मजबूत भूमिका की चरित्र वाली होती है। जबकि सार्वजनिक जेंडर व्यवस्थाओं में यह एक मजबूत राज्य की विशेषता रखती है। वहीं इससे आगे इन दो सार्वजनिक लैंगिक व्यवस्थाओं के मध्य अंतर इस आधार पर किया जा सकता है कि कोई राज्य या राज्य संस्थान वर्ग असमानता को कैसे व्यवस्थित करते हैं। नवउदारवादी दौर की सार्वजनिक लैंगिक व्यवस्थाएं व राज्य संस्थाएं बाजार को जितना संभव हो उतना स्थान देती हैं और इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के पूंजीवादी व्यवस्था में जो वर्गीय असमानताएं उभरती हैं, वे ही प्रतिच्छेदित लिंग असमानताओं को आकार देती हैं। सार्वजनिक सामाजिक–लोकतांत्रिक लिंग व्यवस्था की स्थापना, पूंजीवादी व्यवस्था की असमानताओं की उन सबसे खराब ज्यादतियों को न्यूनतम करने के लिए की जाती है। वे अवसरों की समानता

> >

के एक निश्चित आधार स्तर की ओर जाती है। विशेष रूप से श्रम और देखभाल के आसपास लैंगिक असमानताएं इस मिटिगेशन का हिस्सा हैं।

लैंगिक व्यवस्था का यह भेद मुख्यतः राजनीति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर आधारित है। फिर भी विभिन्न लिंग–विरोधी अभियानों और उनसे जुड़े लैंगिक बदलावों को समझने के लिए, लिंग व्यवस्था सिद्धांत को लैंगिक असमानता और यौन असमानता के उलझाव पर अधिक ध्यान देना होगा। मेरा तर्क है कि यह संभव और आवश्यक है कि शरीर, कामुकता और नातेदारी संबंधों को विनियमित करने वाली समाज की सभी संस्थाओं को समाहित करने वाले कैथेक्सिस डोमेन के साथ जोड़कर लिंग शासन सिद्धांत को संशोधित किया जाए।

मेरे तर्क जेंडर शासन सिद्धांत की चार प्रमुख आलोचनाओं से से जुड़े हैं (*सोशल पॉलिटिक्स* 2020 का विशेषांक जेंडर रेजीम्स देखें), जो वाल्बी के ढांचे में "परिवार" को स्थान देने और इसे अलग–अलग तरीके से कैसे किया जाये की आवश्यकता पर केंद्रित है।

> जेंडर शासन सिद्धांत में परिवार एक डोमेन के रूप में : संभावनाएं और सीमाएं

वेलेंटाइन एम मोघदम दो सार्वजनिक लिंग व्यवस्थाओं की पहचान करती हैः नवपितृसत्तात्मक बनाम रूढ़िवादी–निगमवादी। नव पितृसत्तात्मक लिंग व्यवस्था घरेलू पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जिसे रूढ़िवादी परिवार कानून के माध्यम से राज्य द्वारा संगठित किया जाता है और जो पूंजीवाद के एक रूप के साथ संयुक्त है जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को सीमित करता है, नागरिक समाज को बाधित करता है जिससे निरंतर नारीवादी आयोजन में बाधा आती है और जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अपर्याप्त या गैर–मौजूद कानून हैं। वहीं उभरती रूढ़िवादी–निगमवादी शासन व्यवस्था मजबूत नारीवादी आंदोलनों और विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की उपस्थिति के साथ पारिवारिक सुधार वाले कानून को दर्शाती है। उनका तर्क है कि परिवार को एक डोमेन के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक है क्योंकि पारिवारिक कानून एवं सुधार लैंगिक व्यवस्थाएं कैसे उभरती हैं और कैसे बदलती हैं के लिए धुरीय संस्थाएँ हैं। महत्वपूर्ण रूप से वे राजनीति और नागरिक समाज में विभिन्न गैर या कम–लोकतांत्रिक पदों पर विशेष ध्यान देती है।

राज्य की लोकतांत्रिक या सत्तावादी प्रकृति के भेद के आधार पर करेन शायर और किमिको नेमोतो इस भेद को समझती हैं और वे परिवार की नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देती हैं। उनके अनुसार रूढ़िवादी लिंग व्यवस्था एक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में घरेलू लैंगिक व्यवस्था का गठन करती है और पारिवारिक नीतियों के माध्यम से बदल जाती है जो ऐसे श्रम के लिंग विभाजन को मजबूत करती है, जो न तो नवउदारवादी है और न ही सामाजिक लोकतांत्रिक। ये पारिवारिक नीतियां प्रजनन दर में सुधार के साथ ही महिलाओं के रोजगार का समर्थन करती हैं। वे बताते हैं कि घरेलू लिंग व्यवस्था को गैर–उदार और रूढ़िवादी तरीके से भी आधुनिक बनाया जा सकता है। जिसमें न केवल श्रम व देखभाल का नियोजन है बल्कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता का नियंत्रण भी है। मोघदम के समान ही वे लोकतंत्र बनाम निरंकुशता के आयाम पर लिंग शासन व्यवस्था को अलग करते हैं, जो परिवर्तन के विभिन्न मार्गों से जुड़े होते हैंः सत्तावादी शासन में अधोमुखी और लोकतांत्रिक शासन में उर्ध्वगामी।

एसे कोकाबिकाक परिवार के भीतर श्रम के पितृसत्तात्मक शोषण को बनाए रखने में लिंग–आधारित भेदभाव के माध्यम से, घरेलू से सार्वजनिक लिंग व्यवस्था में बदलाव के दौरान परिवार के महत्व पर अधिक ध्यान देने के लिए इसी तरह का तर्क देती हैं। वे एक आधुनिक घरेलू पितृसत्ता की पहचान करती हैं जिसमें बेदखली और मजदूरी पर बढ़ती निर्भरता के साथ महिलाओं को वैतनिक रोजगार से बाहर रखा जाता है। इस प्रकार श्रम के घरेलू पितृसत्तात्मक शोषण को बनाए रखा जाता है।

इमानुएला लोम्बार्डो और अल्बा अलोंसो भी एक कैथेक्सिस (भावाभिनिवेश) डोमेन के सैद्धांतिकीकरण की जरुरत महसूस करती हैं क्योंकि स्पेन में यौन और प्रजनन संघर्ष लिंग व्यवस्था की गत्यात्मकता को समझने के लिए यह अत्यंत प्रासंगिक है। वे संघर्ष लिंग–विरोधी अभियानों के केंद्र में हैं और अधिक नारीवादी दिशा में लिंग व्यवस्था के और परिवर्तन में बाधा डालते हैं; वे हाल के दिनों में अर्जित लाभ को उलट सकते हैं।

ये सभी लेखक "पारिवारिक" मुद्दों को वाल्बी के ही चार मौजूदा डोमेन में फिट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुश्किल में पड जाते हैं क्योंकि परिवार ज्यादातर श्रम–देखभाल विभाग पर केंद्रित होते हैं। हालांकि, यह लैंगिक असमानता के उन आयामों को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, जिनकी जड़ें समाज में शरीर, कामुकता और नातेदारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले डोमेन से जुड़ी हैं।

संक्षेप में, सार्वजनिक नवउदारवादी और सामाजिक–लोकतांत्रिक लिंग व्यवस्थाओं के बीच लिंग व्यवस्था की किस्मों की वर्तमान अभिव्यक्ति वर्तमान लिंग–विरोधी अभियानों पर पकड़ बनाने के लिए और लिंग संबंधों के कम प्रगतिशील रूपों की तरफ परिणामी झुकाव के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रजनन और यौन स्वायत्तता को प्रतिबंधित करके और रिश्तों तथा परिवार के निर्माण के लिए यौन अधिकारों को अवरुद्ध करके पोलैंड व हंगरी में ऐसा झुकाव पहले ही हो चुका है। यह तेजी से अन्य देशों में और विभिन्न प्रकार के राजनैतिक कर्त्ताओं में फैल रहा है। ऐसे बदलावों पर जोर देने वाले रूढ़िवादी धार्मिक और चरम दक्षिणपंथी कर्त्ताओं का एक मजबूत गठबंधन है। क्या यह नव–पितृसत्ता का आधुनिक सार्वजनिक स्वरूप है?

यह एक गंभीर लिंग व्यवस्था परिवर्तन है। लेकिन यह अपनी असली कुरूपता में तभी सामने आता है जब हम शरीर, कामुकता और नातेदारी संबंधो पर केंद्रित एक नए पूर्ण डोमेन को स्पष्ट करते हैं। ■

सभी पत्राचार मिके वेरलू को <mieke.verloo@ru.nl> पर प्रेषित करें।

> सार्वजनिक लिंग व्यवस्थाएं : अभिसारी छितराव

हेइडी गॉटफ्राइड, वेन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए, और आईएसए की अर्थव्यवस्था एवं समाज पर (आरसी 02) श्रम आंदोलन पर शोध समिति (आर सी 44), महिला, जेंडर एवं समाज पर (आरसी 32) शोध समिति की बोर्ड की सदस्य, और **करेन शायर**, यूनिवर्सिटी ड्यूसबर्ग–एसेन, जर्मनी और आईएसए अनुसंधान समिति (आरसी 02) की उपाध्यक्ष द्वारा

यद्यपि जापान और जर्मनी में प्रजनन का क्षेत्रीय पुनर्गठन महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न होता है, दोनों देशों में प्रवासी देखभाल कार्य व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रेयः पेक्का निक्रस / फ्लिकर

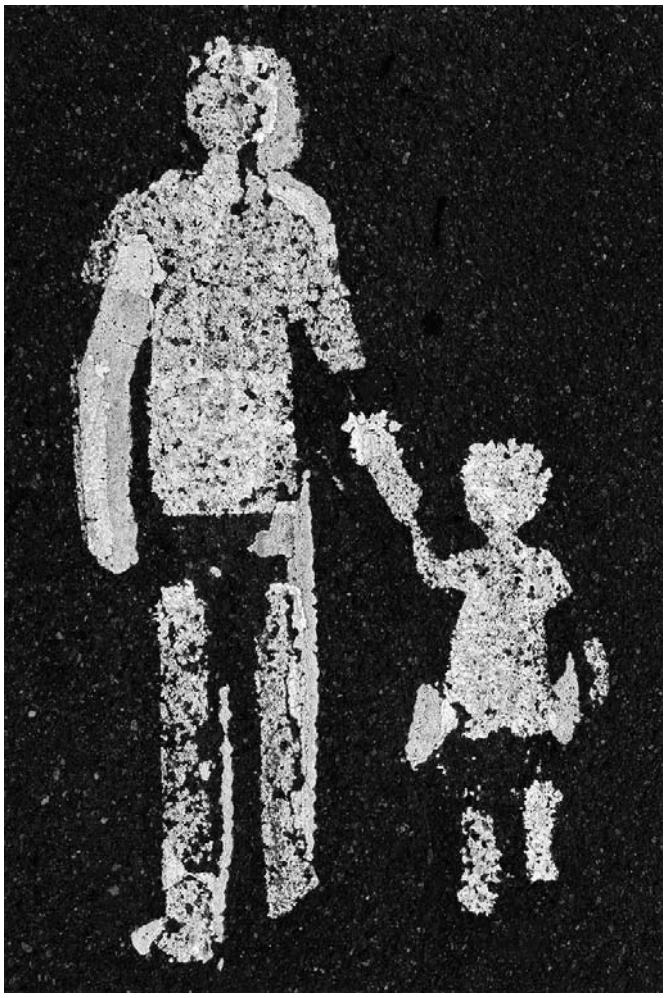

जर्मनी और जापान के उच्च विकास चमत्कारों और आर्थिक विस्तार के मद्देनजर महिलाओं ने उच्च शिक्षा में प्रगति की, फिर भी उनके रोजगार पैटर्न में बदलाव सीमित ही रहे। माताओं के बीच अंशकालिक काम के उच्च स्तर, लगातार बढ़ता लिंग वेतन अंतराल और अवैतनिक देखभाल का लगातार बढ़ते बोझ से बाधित थेय यह एक ऐसा पैटर्न था जो महामारी के दौरान तेज हो गया था। देखभाल के संगठन के उद्देश्य से हाल की नीतिगत फैसलों के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर सामाजिक प्रजनन को फिर से संगठित करने वाली दुनिया में समकालीन लिंग व्यवस्थाओं के बीच "विभिन्नताओं को परिवर्तित" किया है। साथ ही साथ ये प्रजनन श्रम के लैंगिक विभाजन बदलाव में महिलाओं के बीच नए विभाजन पैदा कर रहे हैं। कम मजदूरी वाले प्रवासी श्रमिकों की बढ़ती मांग, विशेष रूप से तेजी से वृद्ध होते देशों के लिए, सामाजिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं का एक मजबूत क्षेत्रीय और वैश्विक एकीकरण तथा वर्ग, लिंग और नस्लध्नागरिकता के साथ असमानताओं का एक कड़ा प्रतिच्छेदन पैदा हो रहा है।

> देखभाल कार्य की पुनर्रचना

जर्मनी और जापान मुख्य रूप से शिशु देखभाल की व्यवस्था को निजी घरों में स्थित करना जारी रखे हुए हैं और सुधार शिशु देखभाल सुविधाओं में पर्याप्त रूप से विस्तार करने में विफल रहे हैं। दोनों देशों में प्रजनन क्षमता में गिरावट जो आंशिक रूप से कसकर बुने पुरुष अर्जक रोजगार व्यवस्था का एक प्रकार्य है, ने वृद्ध आबादी में तेजी से बदलाव किया है और परिणामतः बुजुर्गों की देखभाल की मांग बढ़ी है। दोनों देशों में सामाजिक नीतियों में नवीनतम जोड़, दीर्घकालिक बीमा योजनाएं हैं जो काफी हद तक समान रूप से बुजुर्गों की देखभाल को निजी घरों में स्थानांतरित कर रही हैं। दोनों देशों में केयर सर्विस सेक्टर बीमा प्रीमियम के माध्यम से सेवाओं के लिए आंशिक वित्त पोषण, कम वेतन और अध् र्–पेशेवर श्रमिकां के लिए देखभाल सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहित करने में सहयोगी बना है।

यूरोपीय संघ (ईयू) में यूरोपीय रोजगार नीतियों और उसके लैंगिक लक्ष्यों के दबाव में शिशु देखभाल सेक्टर कम से कम तीन वर्ष से ऊपर उम्र के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर अधिक समाजीकृत हो गया है। हालाँकि, तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल

> >

अभी भी पारिवारिक मामला ही ज्यादा दिखती है। घरेलू श्रम की दृष्टि पुरुषों के व्यवहार में स्पष्ट बदलाव की कमी यूरोपीय संघ के भीतर महिलाओं के अवैतनिक घरेलू श्रम को भुगतान बाजार सेवाओं में स्थानांतरित करने का प्रयास करती है। इसके अलावा, इस बात की परवाह किए बिना कि लिंग व्यवस्था चरित्रगत रूप से सामाजिक लोकतांत्रिक है या नहीं, अत्यधिक कम वेतन और अनिश्चित रोजगार स्थितियों में, भुगतान किए जाने वाले घरेलू और देखभाल श्रम का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी महिलाओं को दिया जाता है। यह महिलाओं की रोजगार की स्थिति को प्रभावित करता है जिसमें नागरिक और गैर–नागरिक महिलाओं के श्रम के बीच स्पष्ट विभाजन होता है जिसके साथ लिंग व्यवस्था की किस्में तेजी से अभिसरण करती हैं। बड़ी संख्या में भुगतान वाले रोजगार में प्रवेश करने के लिए महिलाओं का काम के लिए घरों से बाहर निकलने से जुड़ा प्रजनन का सामाजिक पुनर्गठन, और *पारिवारिक* नीतियों में बदलाव (जैसे घरेलू मदद को काम पर रखने के लिए टैक्स क्रेडिट) का उद्देश्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन के परिदृश्य में महिला श्रमिक भागीदारी को राष्ट्रीय विकास की रणनीति के रूप में बढ़ावा देना है। इस प्रकार विकास रणनीतियां प्रजनन के एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एकीकरण में और अधिक मजबूती से बंधती हैं।

> क्षेत्रीय विविधताएं

जापान के मामले में एशिया–प्रशांत के भीतर और जर्मनी के लिए यूरोपीय संघ में प्रजनन का क्षेत्रीय पुनर्गठन कई महत्वपूर्ण तरह से भिन्न है। यूरोपीय संघ में सेवाओं की स्वतंत्रता और गतिशीलता की स्वतंत्रता ने व्यापार और श्रम गतिशीलता के लिए एक उदार बुनियादी ढांचे को खड़ा किया है। हालाँकि, नए सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा जर्मनी में वैधानिक रूप से कार्य करने की सम्भावना से काफी पहले के भी पर्याप्त साक्ष्य हैं कि पूर्वी यूरोपीय प्रवासन ने जर्मनी के देखभाल क्षेत्र के स्थापित होने के लिए पहले से ही एक अहम् भूमिका निभाई थी। यह जर्मनी में कानूनी रूप से काम करने के लिए राज्यों ने मौलिक मतभेदों के बजाय कार्यात्मक समकक्षों को महत्वपूर्ण मानता है। आसियान देश अपने सदस्य राज्यों के बीच कुशल श्रमिक गतिशीलता के कुछ क्षेत्रों में बाधाओं को हटा रहे हैं, फिर भी यह क्षेत्र यूरोपीय संघ की तुलना में अलग ढ़ंग से काम करता है। जापान ने पुनः स्केल किए गए पुनरुत्पादन की समान गतिशीलता को प्रभावित करने के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर भरोसा किया है। आर्थिक भागीदारी की भाषा में व्यापार समझौतों को संगठित कर, जापान ने देखभाल श्रम गतिशीलता के नए मार्ग तैयार किए हैं। वास्तव में, इन समझौतों में प्रवासन खंडों का मुख्य लक्ष्य देखभाल श्रम है। जापानी उपनिवेश के इतिहास, इस क्षेत्र में अग्रणी दाता राष्ट्र के रूप में जापान का राजनीतिक प्रभाव और सबसे बड़े विदेशी निवेशक के रूप में इसकी स्थिति के आधार पर सबसे प्रमुख स्रोत देश, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम, पूर्व में विकसित क्षेत्रीय लिंक पर ग्राफ्ट करते हैं।

जर्मनी से अलग होकर, जापान ने द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत करके और कुशलध्अकुशल के रूप में देखभाल कार्य के वर्गीकरण को बदलकर प्रवासी देखभाल श्रमिकों की संख्या का विस्तार करने के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। हालाकि इस श्रम आयात रणनीति ने भी देखभाल श्रमिकों की बारहमासी कमी को पूरा नहीं किया है क्योंकि आंशिक रूप से आप्रवासन पर सख्त नियंत्रण, लाइसेंस हासिल करने के लिए उच्च बाधाएं और नागरिकता की राह की सीमाएं जापान में प्रवासी श्रमिकों के प्रवाह को बाधित कर रही हैं। अपनी पुरानी प्लेबुक का अनुगमन करते हुए, जापान सरकार ने मध्यस्थता के केंद्र में खुद ही हस्तक्षेप किया है। इसने न केवल द्विपक्षीय समझौतों की दिशा में बातचीत के लिए एक नियम–सेटिंग एजेंट के रूप में कार्य किया बल्कि एक श्रम बाजार मध्यस्थ के रूप में भी इस क्षेत्र के अन्य देशों से श्रम की आवाजाही का प्रबंधन किया है। यूरोपीय संघ में मुक्त गतिशीलता जर्मनी से सटे देशों से सीमा पार प्रवाह को आसान बनाती है। प्रारंभिक प्रतिबंधों का अर्थ था कि प्रवासी देखभाल श्रमिक जर्मनी में स्व–नियोजित (ईयू में सेवाओं की स्वतंत्रता के तहत) या अपंजीकृत श्रमिकों के रूप में प्रवेश करते थे। इस प्रारंभिक चरण में प्रवासी निजी घरों में किसी श्रम मानकों के (यदि स्व–नियोजित)अपनी सेवाएं देते थे या निजी तौर पर घरों में शिंकायत करने की सुविधा(यदि अपंजीकृत)के बिना काम करते थे। अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की तरह, जिस तरह से देखभाल क्षेत्र ने जर्मनी में प्रवेश किया है, उसने एजेंसी सेवाओं के एक सेक्टर को फलने–फूलने की इजाजत दी (मुख्य रूप से पूर्वी यूरोपीय सदस्य राज्यों में स्थित)। प्रतिबंध हटने से देखभाल क्षेत्र के कर्मियों को स्वरोजगारध्दलाल सेवा संबंधों की अनिश्चित स्थितियों में छोड़ दिया गया। इस प्रकार, प्रवासी देखभाल श्रम को अनिश्चित रोजगार के रूप में तैयार किया गया है।

क्षेत्रीयकरण और वैश्वीकरण दोनों ही सकारात्मक शक्तियां बन सकती हैं। क्योकि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित लैंगिक समानता की नीतियों को रेखांकित कर प्रभावी आंदोलनों को संगठित करने के प्रयासों की दिशा में राज्य और समाज में नारीवादी कार्यकर्ताओं के लिए नए क्षैतिज प्रस्तुत करती हैं। फिर भी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बनी नीतियों को राजनैतिक कर्ताओं द्वारा अधिनियमित किया जाना जरुरी है। सुपरा–नेशनल संस्थानों और राष्ट्रीय शासन के बीच अंतर्निहित तनाव देशों में नीतिगत पहलों के आसान सामंजस्य में बाधक बनता है। यह कोविड के दौरान सरकारों की राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट भी हो गया। कोविड –19 जैसे संकट, सामाजिक प्रणालियों में अपेक्षित परिवर्तनों की संभावना को पैदा करते हैं। नई सार्वजनिक मान्यता के परिणामस्वरूप देखभाल क्षेत्र के काम का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की ओर भी झुकाव हो सकता है नहीं तो घर में देखभाल श्रम की तीव्रता वर्ग, नस्ल और नागरिकता आधारित असमानताएँ, महिलाओं के पुनः पारंपरिकरण को बढ़ा सकती है। ■

सभी पत्राचार हेइडी गॉटफ्राइड को <ag0921@wayne.edu> पर प्रेषित करें।

> लिंग व्यवस्था, राजनीति और विश्व–व्यवस्था

वैलेंटाइन एम.मोघदम, नॉर्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालय, यूएसए और महिला, लिंग एवं समाज पर आईएसए की शोध समिति (आर सी 32) के सदस्य द्वारा

सिल्विया वाल्बी द्वारा एक मैक्रो–स्तरीय समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में विकसित *लैंगिक व्यवस्था* का मोटे तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर सैद्धांतिक विश्लेषण किया गया है, और मुख्य रूप से आर्थिक रूप से अत्यधिक विकसित पूंजीवादी लोकतंत्रों की विशेषता वाले क्षेत्रों में, जो पूंजीवादी बाजार विश्व–अर्थव्यवस्था वाली वित्तीय संरचनाओं में मजबूती से एकीकृत हैं, इन्हें लागू किया गया है। उनके अध्ययन में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, जापान और जर्मनी शामिल हैं। यद्यपि हम इसकी उपयोगिता अल्प–विकसित क्षेत्र, जो लोकतान्त्रिक और सत्तावादी राजनीति के घर हैं, जो या तो विश्व–व्यवस्था से कमजोर रूप से एकीकृत या उन पर अत्यधिक निर्भर हैं, में भी देख रहे हैं। यहाँ मैं ईरान और ट्यूनीशिया पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और कुछ पृष्टभूमि एवं सन्दर्भ के साथ प्रारम्भ करती हूँ।

इजराइल (अमालिया सा'र द्वारा) और तुर्की (एस कोकाबिकाक द्वारा) तथा अल्जीरिया, मोरक्को व ट्यूनीशिया (वर्तमान लेखक द्वारा) माघरेब देशों में इसके उपयोग से पता चलता है कि लिंग शासन की अवधारणा को गैर–पश्चिमी संदर्भों तक, यद्यपि राष्ट्रीय स्तर की विशिष्टताओं और देश के भीतर की भिन्नताओं के लिए आवश्यक समायोजन के साथ, बढ़ाया जा सकता है। नवउदारवादी अर्थव्यवस्था में फिलिस्तीनी–इजराइली महिलाओं के श्रम–बल एकीकरण में ठहराव का वर्णन करते हुए सा'र ने "पितृसत्तात्मक लिंग अनुबंध" (मेरे द्वारा 1998 में लिखी एक पुस्तक में पेश) की अवधारणा को दर्शाया है। इसका परिणाम इजराइल में मुख्य रूप से घरेलू–केंद्रित लिंग शासन है, जिसमें लघु स्तर पर, सार्वजनिक–केंद्रित रुप भी साथ–साथ सक्रिय दिख रहे हैं। एस कोकाबिकाक का तर्क है कि तुर्की में घरेलू लिंग व्यवस्थाएं समय के साथ क्षेत्रीय स्तर पर और उप–राष्ट्रीय स्तर पर अपने पूर्व–आधुनिक और आधुनिक रूपों में भिन्न–भिन्न दिखायी देती हैं। ऐली मारी ट्रिप ने अपनी हालिया पुस्तक, *सीकिंग लेजिटिमेसी* में लिंग शासन की अवधारणा का उपयोग नहीं किया है लेकिन अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया के माघरेब देशों की अन्य मध्य पूर्व/उत्तरी अफ्रीकी (MENA) देशों के साथ उनकी तुलना 'नव–पितृसत्ता' से एक उभरती '' रूढ़िवादी–निगमवादी लिंग व्यवस्था में'' परिवर्तन के मेरे विमर्श की पुष्टि करता है। लिंग व्यवस्था के सिद्धांत का चित्रण न कर उत्तरी अफ्रीका, लेवेंट और फारस की खाड़ी के शेखों में अंतर करते हुए रानिया मकतबी, लैंगिक नागरिकता व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा करती है। मेरे काम में, मैंने गैर–पश्चिमी या गैर–पूंजीवादी आधुनिकता (उदाहरण के लिए, साम्यवाद के तहत या सत्तावादी सेटिंग्स में) के प्रश्न को उठाया है। इसके अलावा, विशेष रूप से ट्यूनीशिया और हाल ही में ईरान जैसे नव–लोकतांत्रिक माघरेब देशों में उभरती नयी लैंगिक व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया है।

सभी मामलों में, नारीवादी सिद्धांत ने पितृसत्ता और स्थापित लैंगिक व्यवस्था, यदि प्रतिगमन नहीं, के विकास में प्रगति और ठहराव दोनों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। एक प्रश्न यह उठता है कि क्या लिंग व्यवस्थाएं न केवल राष्ट्रीय स्तर के संस्थागत डोमेन और वर्ग संरचना द्वारा गठित होती हैं बल्कि उस आर्थिक क्षेत्र– विश्वव्यवस्था के विद्वानों द्वारा कोर, परिधि और अर्ध–परिधि के रूप में विश्लेषित– द्वारा भी आकार लेती हैं जिसमें वे स्थित हैं। इस पैमाने पर लिंग व्यवस्था का सैद्धांतिकरण किस्मों, गतिकी, और संभावनाओं, प्रसार और क्लस्टरिंग एवं अभिसरण व विचलन तथा परिवर्तन व वापसी के चालकों की पहचान करने में पहला कदम हो सकता है।

> वैश्विक दक्षिण लिंग व्यवस्था: वैचारिक मुद्दे

ग्लोबल नॉर्थ से परे इसकी उपयोगिता लागू करने के लिए मैं तीन वैचारिक मुद्दों को प्रकाशित करना चाहूंगी। पहला निजी पितृसत्ता (घरेलू या पूर्व–पूंजीवादी लिंग शासन) की दृढ़ता की प्रकृति और सीमा से जुड़ा है, नए उभरते या स्थापित लैंगिक शासन (रूढ़िवादी बनाम नवउदारवादी या सामाजिक–लोकतांत्रिक) और एक संस्थागत डोमेन के रूप में *परिवार* की निरंतरता के लिए उपयुक्त नाम है।

दूसरा पैमाने से संबंधित है। ईरानी कुर्दिस्तान पर हाल के एक लेख में, जिसका मैंने दो कुर्द–ईरानी समाजशास्त्रियों के साथ सह–लेखन किया है जो सानंदाज की राजधानी पर केंद्रित है जहां ईरान के व्यापक और कहीं अधिक केंद्रीकृत राष्ट्रीय स्तर के नव–पितृसत्तात्मक लैंगिक शासन के भीतर *परिवार* एक महत्वपूर्ण संस्थागत डोमेन बना हुआ है। क्या संस्थागत डोमेन अलग–अलग पैमानों पर अलग–अलग तरीके से काम करते हैं?

एक तीसरा मुद्दा एक लिंगव्यवस्था से दूसरे में बदलाव के पीछे चालक और नायको के और ठहराव या प्रतिगमन के पीछे के कारकों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, माघरेब में लिंगव्यवस्था में बदलाव पर मेरे काम में मैंने *नारीवादी लामबंदी* को परिवर्तन के प्रमुख चालकों के रूप में चिंन्हित किया गया है लेकिन मैंने देखा कि आगे की प्रगति विशेषतः ट्यूनीशिया के लोकतंत्रीकरण में आर्थिक संकट से बाधित हुई है।

ये तीनो मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें चालक और अभिनेता विभिन्न स्तरों पर मौजूद हो सकते हैं और संस्थागत डोमेन वैश्विक के साथ–साथ राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय गतिशीलता से प्रभावित हो सकते हैं। मेरा मूल तर्क यह है कि पूंजीवादी विश्व–व्यवस्था जिसे पूंजीवादी बाजारों और अंतरराज्यीय संबंधों के अत्यधिक असमान

>>

“पूंजीवादी विश्व-व्यवस्था विभिन्न पैमानों पर संस्थागत विन्यास सहित लैंगिक व्यवस्था की संभावनाओं और गतिशीलता की हमारी समझ के लिए वैचारिक प्रवेश-बिंदु होनी चाहिए”

और पदानुक्रमित विन्यास के रूप में समझा जा सकता है– विभिन्न स्तरों पर संस्थागत विन्यास सहित लैंगिक व्यवस्था की संभावनाओं और गतिशीलता की हमारी समझ के लिए एक वैचारिक प्रवेश बिंदु होनी चाहिए।

> ईरान और ट्यूनीशिया में लिंग व्यवस्था: विश्व–व्यवस्था विश्लेषण को लागू करना

मैंने शिक्षित और बदलाव की आकांक्षी महिला आबादी सहित बड़े मध्यम वर्गों वाली दो MENA गणतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुभवजन्य अंतर्संबंधों को समझने का प्रयास किया है। एक सत्तावादीऔर तेल–समृद्ध समाज है लेकिन अमेरिकी कठोर प्रतिबंधों (ईरान) के अधीन है; वहीं दूसरा लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के तहत है पर आर्थिक रूप से दमित और भारी कर्ज में (ट्यूनीशिया) डूबा है। दोनों के पास अलग–अलग राजनीति, अर्थव्यवस्थाएं और नागरिक समाज हैं लेकिन *परिवार* के आसपास लगभग समान तरह की बहस हैं। साथ ही साथ संबंधित लिंग व्यवस्थाएं, जो उनके गठन के आधार हैं। ये सब न केवल आंतरिक कारकों और ताकतों द्वारा ही अस्तित्व में हैं बल्कि वे पदानुक्रमित विश्व–व्यवस्था के स्तर पर काम करने वाली ताकतों के लिए भी अति संवेदनशील हैं।

मेरा मानना है कि कि लैंगिक व्यवस्थाएं विश्व की प्रणालीगत प्रक्रियाओं की उत्पाद हैं जो लैंगिक समानता को सक्षम या बाधित करते हुए राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर और उसके पार अभिकर्ताओं तथा संस्थानों को प्रभावित करती हैं ईरान के मामले में, एक उभरता अर्ध–परिधीय राज्य विश्व–व्यवस्था के आधिपत्य को चुनौती देता है जिसके फलस्वरूप आर्थिक और वित्तीय दंड लगता है जो बदले में घरेलू दक्षिणपंथी ताकतों को मजबूत करता है और महिलाओं की भागीदारी एवं अधिकारों पर प्रगति को बाधित कर उलट देता है। इसमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को केवल पिताओं को जारी करने का एक हालिया मामला अत्यधिक विवादित और आधिकारिक निर्णय वाला शामिल है। ट्यूनीशिया के मामले में, समतावादी दिशा में आगे बढ़ने वाली व्यापक रूप से प्रशंसित लोकतांत्रिक बदलावों के साथ उभरती नयी लैंगिक व्यवस्था देश की छोटी अर्थव्यवस्था, वैश्विक कमोडिटी श्रृंखलाओं की स्पर्शरेखा से जुड़ाव और बाहरी निवेश तथा ऋण पर अतिनिर्भरता से खतरे में है। इसमें बहनों के लिए समान उत्तराधिकार के आसपास गतिरोध व निष्क्रियता सम्मिलित है जो नारीवादी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद निराशाजनक है और हाल ही में राजनीति में विवादास्पद राष्ट्रपति हस्तक्षेप शामिल है। परिधि और अर्ध–परिधि के मध्य वैश्विक दक्षिण देशों के दो मामलें, ईरान और ट्यूनीशिया के विश्लेषण विश्व–प्रणालीगत प्रक्रियाओं के प्रभावों को स्पष्ट करते हैं– अंतरराज्यीय प्रणाली के भीतर आधिपत्य की राजनीति और लैंगिक व्यवस्थाओं पर विश्व–अर्थव्यवस्था के अंतर्गत छोटी अर्थव्यवस्थाओं की कमजोर स्थिति। ■

सभी पत्राचार वैलेंटाइन एम.मोघदम को <v.moghadam@northeastern.edu> पर प्रेषित करें।

> तुर्की पितृसत्तात्मक राज्य के निर्धारक

एसे कोकाबिकाक, द ओपन यूनिवर्सिटी, यूके द्वारा

इस्तांबुल कन्वेंशन, जो मूल रूप से लड़कियों और महिलाओं को सभी प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए पेश किया गया था, से तुर्की की वापसी का विरोध करती महिलाएं और एलजीबीटीआई समुदाय । कादिकोय, 2021.
श्रेय: Yagmurkozmik /Wikimedia Commons.

सामाजिक परिवर्तन के लिए लिंग, वर्ग, और जातीयता आधारित असमानताएं व्यवस्थाओं के समान महत्व पर बल देने के साथ–साथ, लैंगिक व्यवस्था की किस्मों के सिद्धांत, राज्य के पितृसत्तात्मक चरित्र के भीतर बदलावों के आकलन की अनुमति देते हैं। यह आलेख तुर्की में पितृसत्तात्मक राज्य के निर्धारकों की जांच करके लिंग शासन सिद्धांतों का विस्तार करता है। इस्तांबुल कन्वेंशन, महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने वाली एक मानवाधिकार संधि, से तुर्की की वापसी का मामला इस बात की जांच करने में सक्षम बनता है कि राज्य एजेंडों की बहुलता और वि–लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के मध्य लिंग आधारित सामाजिक समूहों का निर्माण पुरुषों की सामूहिक सौदेबाजी क्षमता को गुणात्मक रुप से बढ़ाते है।

> पितृसत्तात्मक राज्य चरित्र के दो रूप

लिंग शासन सिद्धांतों पर निर्माण करते हुए, मेरा सुझाव है कि समाज के लिंग, वर्ग और जाति तथा जातीयता आधारित प्रमुख समूह राज्य पर एक मजबूत प्रभाव स्थापित करते हैं और इस तरह, राज्य एजेंडों की बहुलता के मध्य परस्पर क्रिया का नेतृत्व करते हैं। सिल्विया वाल्बी के अनुसार, लिंग–आधारित बहिष्करण रणनीतियों की प्रबलता लिंग व्यवस्था के घरेलू स्वरुप से जुड़ी हुई है और लिंग–आधारित अलगाव व अधीनता सार्वजनिक लिंग व्यवस्था के नवउदारवादी सामाजिक–लोकतांत्रिक रूपों से जुड़ी हुई है। उनके भेद के आधार पर मैं राज्य के पितृसत्तात्मक चरित्र के दो प्रमुख स्वरूपों की अवधारणा को रखता हूँ: *घरेलू पितृसत्तात्मक राज्य* महिलाओं के श्रम को घरेलू उत्पादन (देखभाल के काम

>>

सहित) तक सीमित रखता है जबकि *सार्वजनिक पितृसत्तात्मक राज्य* विभिन्न प्रकार के वस्तुकरण और डी–वस्तुकरण (घर में महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं द्वारा) का उपयोग भुगतान और अवैतनिक श्रम के लिए महिलाओं के दोहरे बोझ की स्थिरता की गारंटी देने के लिए करता है। जबकि पहला लिंग–आधारित बहिष्करण रणनीतियों को बनाए रखता है, परवर्ती अर्थव्यवस्था, राजनीति व नागरिक समाज तथा हिंसा के संस्थागत डोमेन के भीतर लिंग–आधारित अलगाव व अधीनता को नियंत्रित करता है।

प्रस्तावित ढांचा वैश्विक दक्षिण में राज्य गठन के विश्लेषण के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि वहां राजनीतिक अभिकर्ताओं में विविध समूह शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले भी तर्क दिया है कि तुर्की में राजसत्ता का पितृसत्तात्मक राजनैतिक कर्ता घर के पुरुष मुखिया तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, छोटे पुरुष–उत्पादक भी शामिल हैं। इसके अलावा, जिन परिस्थितियों में लोकतंत्र विरोधी शासन सार्वजनिक निर्णय लेने में काफी लिंग अंतर बनाए रखते हैं, अभिजात वर्ग के पुरुषों का एक विशेष समूह शासन के नेतृत्व पर अपना प्रभाव बनाए रखता है। बदले में यह, पुरुषों की सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ाता है। कुलीन पुरुषों के इस समूह के संदर्भ में मैं *पुरुषों के शासन* की अवधारणा विकसित करती हूँ।

मेरे आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2000 के दशक के बाद से, तुर्की राज्य में सार्वजनिक और घरेलू पितृसत्तात्मक चरित्रों के बीच संघर्ष बढ़ा है। ये परस्पर विरोधी चरित्र शायद कई अन्य राज्यों में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन तुर्की में एक सार्वजनिक पितृसत्तात्मक राज्य की ओर बदलाव सीमित ही रहा है और इसका स्तर अपने घरेलू पितृसत्तात्मक चरित्र की प्रबलता को चुनौती देने के लिए अपर्याप्त है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप शहरी शिक्षा के अपेक्षाकृत निम्न स्तर वाली महिलाओं को घर पर रहने और अवैतनिक देखभाल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को छोटे–मध्यम पैमाने के खेतों में अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों के रूप में बनाए रखते हैं। नागरिक समाज के क्षेत्र में, हाल ही में स्थापित लोकतंत्र विरोधी शासन (2014–15 से) महिलाओं को सार्वजनिक निर्णय लेने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर करता है और सामाजिक आंदोलनों को दबाता है। साथ ही प्रजनन क्षमताओं सहित अपनी कामुकता पर महिलाओं का नियंत्रण, राज्य द्वारा संचालित समलैंगिकता और जन्म–पूर्व नियमों द्वारा प्रतिबंधित है। लैंगिक हिंसा के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप पर एक नजदीकी नजर डालने से पता चलता है कि राज्य महिलाओं को हिंसक विषमलैंगिक परिवार की सीमाओं के भीतर फंसाता है। यह परिदृश्य वहीं एकल और अलग या तलाकशुदा महिलाओं के साथ–साथ स्ळठज्फ़ लोगों के खिलाफ पुरुष हिंसा के प्रति सहनशील बना महिलाओं की पहुंच को व्यवहार्य विकल्पों तक सीमित कर देता है।

> इस्तांबुल कन्वेंशन से तुर्की की वापसी

इस्तांबुल कन्वेंशन से तुर्की की वापसी पर ध्यान केंद्रित करके, मैं इस बात की जांच करने का प्रयास करती हूं कि पितृसत्तात्मक अभिकर्ताओं ने घरेलू पितृसत्तात्मक राज्य चरित्र को बनाए रखने के लिए तुर्की मुस्लिम जातिवादी राज्य के एजेंडे का किस हद तक इस्तेमाल किया है। मेरा आकलन बताता है कि शुरू में, 2015 और 2018 के बीच, पुरुषों के कुछ समूह बाल विवाह पर रोक लगाने, गुजारा भत्ता हासिल करने और बच्चों की कस्टडी को विनियमित करने वाले कानूनी नियमों के खिलाफ संगठित हुए। कानून संख्या 6284, जो कन्वेंशन के संबंध में अधिनियमित किया गया था, की इस अवधि के दौरान जांच की गई। सोशल मीडिया पर विभिन्न चर्चा समूहों की स्थापना कर, दुष्प्रचार अभियान चलाकर और सड़क पर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर, इन समूहों ने दावा किया कि वे उपरोक्त नियमों के शिकार हुए थे। उनके प्रारंभिक अभियानों को भी पुरुषवादी शासन, जिसमें टिप्पणीकार, पत्रकार, शिक्षाविद, धार्मिक संप्रदायों के नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों के पुरुष राजनेता शामिल थे, द्वारा समर्थित किया गया था।

फिर भी, 2019 तक रणनीतिक स्थिति तक पुरुषों की की प्रारंभिक लामबंदी सीमित ही रही। हालांकि 2019 से पहले इस्तांबुल कन्वेंशन का कोई उल्लेख नहीं था, इन पुरुषों ने अपना ध्यान स्थानांतरित कर दिया और (1) न केवल समलिंगी संबंधों को बल्कि पुरुषों से महिलाओं की स्वतंत्रता को परिवार संरचना के तुर्कीपन एवं मुस्लिमत के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में लेबल कर (2) तुर्की और मुस्लिम आबादी के भौतिक व सामाजिक अस्तित्व के लिए खास तरह की पारिवारिक संरचना के महत्व पर जोर दे कर और (3) इस प्रसिद्ध भ्रम को दोहराते हुए कि पश्चिम का लक्ष्य तुर्की को बर्बाद करना है, अपनी मांगों को बदल दिया । इस नई रणनीति को अपनाने के साथ "आम पुरुष" और सत्ताधारी पुरुषों के समूहों के बीच पहले से स्थापित एकजुटता ने प्रभावी ढंग से काम किया है और न केवल जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी के नेतृत्व पर बल्कि मुख्य गठबंधन पार्टी (राष्ट्रवादी आंदोलन पार्टी) और एक विपक्षी दल (फेलिसिटी पार्टी) पर उनके प्रभाव को भी तेज किया। महिलाओं की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करते हुए राज्य द्वारा इसके वापसी का फैसला इतना आसान नहीं था। बहरहाल, मार्च 2021 को, एर्डोगन ने आधिकारिक तौर पर, इस आधार पर वापसी की घोषणा की, कि समलैंगिकता को सामान्य बनाने के लिए कन्वेंशन में हेरफेर किया गया है जो तुर्की के सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के साथ असंगत है।

इस्तांबुल कन्वेंशन के मामले से स्पष्ट पता चलता है कि पुरुषों के अधिकार आंदोलन शुरूआत में (2015–2018) पुरुषों के शासन के प्रयासों के बावजूद राज्य पर अपना प्रभाव बढ़ाने में विफल रहा। इस प्रारंभिक अवस्था में, महिलाओं के मजबूत प्रतिरोध ने उनकी मांगों को रोक दिया। तुर्की मुस्लिम नस्लवादी एजेंडे (2019 से) को अपनाने के साथ, पुरुषों के शासन ने पितृसत्तात्मक अभिकर्ताओं के प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके कारण घरेलू पितृसत्तात्मक राज्य को मजबूत हुआ है। यह आकलन लिंग शासन सिद्धांत की समझ बढ़ाने में निम्न तरह से योगदान देता है: (1) पितृसत्तात्मक राजनीतिक गठजोड़ करने वाले विविध समूहों की जांच, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के संदर्भ में और (2) उन तरीकों की खोज कर जिनसे कई राज्य एजेंडा के बीच परस्पर पुरुषों की सामूहिक सौदेबाजी क्षमता बढ़ती है। ■

सभी पत्राचार एसे कोकाबिकाक को <Ece.Kocabicak@open.ac.uk> पर प्रेषित करें।

> एक दक्षिणी यूरोपीय लिंग व्यवस्था?

अल्बा अलोंसो, सैंटियागो डी कॉम्पोस्टेला विश्वविद्यालय, स्पेन, **रॉसेला सिसिया,** ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूके और रिसर्च कमेटियों ऑन अर्थव्यवस्था एवं समाज (आरसी 02) और गरीबी, समाज कल्याण और सामाजिक नीति (आरसी 19) पर आईएसए की शोध समितियों के सदस्य, और **इमानुएला लोम्बार्डो,** मैड्रिड कॉम्प्लुटेंस विश्वविद्यालय स्पेन द्वारा

स्पेन और इटली को अक्सर लिंग व्यवस्था के घरेलू या रूढ़िवादी मॉडल के रूप में एक साथ जोड़ा जाता है। हालांकि, पिछले दशकों में दोनों देशों ने संकरण के संकेत दिखाए हैं और तेजी से भिन्न हो गए हैं।
श्रेयः Granata92 /Wikimedia Commons.

दक्षिणी यूरोपीय राज्यों की लिंग व्यवस्था के अंतरालों को हम कैसे समझ जा सकते हैं? जेंडर व्यवस्थाओं के विभिन्न प्रक्षेप पथों की व्याख्या कौन करता है? स्पेन और इटली को अक्सर घरेलू या रूढ़िवादी मॉडल से जोड़कर देखा जा सकता है क्योंकि इनकी सत्तावाद की साझा विरासत और कल्याणकारी राज्य की प्रकृति पारिवारिक है जो असमान लिंग संबंधों को मजबूत करती है और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की पहुंच को प्रतिबंधित रखती है। हालांकि, पिछले दशकों में दोनों देशों ने बदलाव के संकेत दिए हैं और तेजी से थोड़ा भिन्न भी हुए हैं। जहां स्पेन अधिक सार्वजनिक रूप की दिशा में बढ़ रहा है, वही इटली में परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत बहुत धीमी है और लिंग शासन व्यवस्था के अधिक निजीकरण की दिशा में जा रहा है।

हमारा तर्क है कि राजनीति और नागरिक समाज की प्रक्रियाएं लैंगिक व्यवस्थाओं के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण "इंजन" हैं। राज्य आधारित नारीवाद पर साहित्य द्वारा राजनीति और नागरिक समाज के बीच गतिशीलता का विश्लेषण किया गया है जिसमें उत्तर–औद्योगिक पश्चिमी लोकतंत्रों के अध्ययनों से पता चलता है कि राज्य नारीवाद किस हद तक महिलाओं के हितों के लोकतांत्रिक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकता है और लैंगिक नीतिगत बहसों के लिए नारीवादी आंदोलनों और महिला निति निर्माण एजेंसियों के मध्य गठबंधन की प्रासंगिकता का विश्लेषण भी करता है। राजनीतिक दल–प्रणाली की विशेषताएं, संस्थागत विरासत, लिंग समानता के पक्ष और विपक्ष में अभिकर्ताओं के नक्षत्र, संगठित धर्म की भूमिका, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और लिंग भूमिकाओं के बारे में प्रचलित सामाजिक विचार राज्य नारीवाद और महिला आंदोलन की भूमिका के पूरक हैं और ये लिंग व्यवस्था के प्रक्षेपवक्र में भिन्नता उत्पन्न करने वाले अंतःक्रियात्मक कारकों के विशिष्ट विन्यास को उत्पन्न करते हैं।

हमारा अध्ययन एक दक्षिणी यूरोपीय लिंग व्यवस्था मॉडल के अस्तित्व को चुनौती देता है जो इस क्षेत्र के सभी देशों पर सही बैठता है। 2000 के दशक में इटली और स्पेन में लैंगिक समानता नीतियों के प्रक्षेपवक्र का विश्लेषण, जो लैंगिक समानता के संस्थाकरण की पूर्व विरासत के संदर्भ में है, दर्शाता है कि दो दक्षिणी यूरोपीय देशों को एक ही मॉडल के तहत एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि वे अपने लिंग शासन में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं। जहाँ जो कि सरकार में पार्टी आधारित सामाजिक–लोकतांत्रिक–प्रगतिशील और नवउदारवादी–रूढ़िवादी रूपों के मध्य चलते हुए स्पेनिश लिंग शासन व्यवस्था तेजी से सार्वजनिक हो रही है, वहीं इतालवी लिंग शासन व्यवस्था अधिक घरेलू और रूढ़िवादी बनी हुई है।

> राजनीति और नागरिक समाज में गतिशीलता

लिंग व्यवस्था में भिन्नता राजनीति और नागरिक समाज डोमेन के भीतर और उनके मध्य की गतिशीलता से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। राजनीतिक आधार पर इटली और स्पेन की लैंगिक व्यवस्थाओं के हमारे मूल्यांकन के कुछ प्रमुख कारक निम्न हैं: (1) इटली में मुख्यधारा के केंद्र में दक्षिणपंथी दलों की ताकत को देखते हुए एक राजनीतिक दल–प्रणाली जो स्पेन की तुलना में इटली में अधिक शत्रुतापूर्ण है; स्पेन में लैंगिक समानता पर अधिक सक्रिय केंद्रीय वाम दलों की उपस्थिति है; और कट्टर–दक्षिणपंथी लोकलुभावन पार्टियों की बढ़ती ताकत–1990 के दशक से इटली में मजबूत और सरकारी भूमिकाओं के साथ लेकिन अब यह स्पेन में उभर रही है, (2) लोकतंत्र की गहराई: स्पेन की तुलना में, जहां 2007 से यह लगभग 40 प्रतिशत बढ़ा है, इटली में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है जो 2018 तक 11 प्रतिशत पर अटका रहा है, (3) संगठित धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप: वेटिकन और उसके नागरिक समाज तथा राजनीतिक सहयोगियों की सरकार तक सीधी पहुंच है और स्पेन की तुलना में इटली में समानता के लिए हानिकारक प्रभाव है, (4) राज्य नारीवाद और महत्पूर्ण त्रिकोण (यानी नीति–निर्माताओं, नारीवादी शिक्षाविदों व विशेषज्ञों तथा नारीवादी आंदोलनों के बीच अन्तर्क्रिया) स्पेन की तुलना में इटली एक कमजोर लैंगिक समानता वाला संस्थाकरण और यह नारीवादी कार्यकर्ताओं, विधायकों, नारीवादियों और शिक्षाविदों के बीच कमजोर गठबंधन को प्रस्तुत करता है, (5) स्पेन में संघवाद एक प्रगतिशील ताकत है जो विभिन्न क्षेत्रों, उनके तथा केंद्रीय राज्य

>>

के मध्य लैंगिक समानता में नीतिगत नवाचार को गति प्रदान करता है जबकि इटली में ऐसा नहीं है (6) स्पेन की तुलना में इटली में कल्याणकारी व्यवस्था की एक विशेषता के रूप में परिवारवाद अधिक मजबूत रहा है।

वही *नागरिक समाज* के लिए हमारे मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक निम्न हैं: (1) महिला आंदोलन के प्रकारः स्पेन जहाँ वामपंथी दलों में महिला राजनेताओं और नारीवादियों की उपस्थिति ने नीतिगत विकास में लैंगिक समानता की निरंतरता को सुनिश्चित किया है की तुलना में कम राज्योन्मुख होने के कारण इटली में यह समानता से ज्यादा भिन्नता पर आधारित है, (2) लिंग–विरोधी आंदोलनों की ताकत और औपचारिक राजनीतिक अभिकर्ताओं द्वारा उनका समर्थनः आंदोलनों और सरकार में कट्टर–दक्षिणपंथी लोकलुभावन दलों के बीच महत्वपूर्ण संबंध के साथ यह स्पेन की तुलना में इटली में अधिक दिखता है जबकि स्पेन में ऐसे राजनीतिक रिश्ते एक नयी घटना है। (3) ज्ञानः जहाँ स्पेन की जनता की राय लैंगिक भूमिकाओं और धर्मनिरपेक्षता के बारे में अधिक प्रगतिशील विचारों की दिशा में विकसित हुई है, इटली में समाज और राजनीतिक संस्कृति व समाज में रूढ़िवाद प्रबल है।

कुल मिलाकर, लैंगिक समानता वाली नीतियों को बढ़ावा देने वाले कारकों ने स्पेन में एक सार्वजनिक लिंग शासन व्यवस्था की दिशा में अपना अधिक दबाव बनाया है जबकि इटली में राजनीति और नागरिक समाज में रूढ़िवादी और लिंग–विरोधी ताकतों संग सार्वजनिक तथा प्रगतिशील लैंगिक व्यवस्था के विकास के लिए एक अधिक शत्रुतापूर्ण संदर्भ का निर्धारण किया है। परिवार, रोजगार और राजनीति में लिंग भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादी विचारों की स्थायीता इटली में पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं के स्थायित्व को प्रभावित करती है, जबकि स्पेन दोहरी कमाई वाले मॉडल की ओर बढ़ रहा है। इटली के लिंग शासन पर भी संगठित धर्म का एक मजबूत हानिकारक प्रभाव है। स्पेनिश समाज अधिक धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति के साथ–साथ इतालवी समाज की तुलना में लैंगिक समानता की दिशा में अधिक प्रगति की अनुमति देता है।

यह तुलनात्मक अध्ययन परिवर्तन के इंजन के रूप में राजनीति और नागरिक समाज डोमेन के मध्य परस्पर क्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए इटली और स्पेन की भिन्न लैंगिक व्यवस्थाओं के समझने के निष्कर्ष पर पहुंचता है। भविष्य के अध्ययनों को अन्य महत्वपूर्ण डोमेन, जैसे कि अर्थव्यवस्था, हिंसा, ज्ञान, और शरीर तथा कामुकता से संबंधित मुद्दों के साथ अंतर्क्रिया को ध्यान में रखना होगा ताकि दक्षिणी यूरोपीय लिंग व्यवस्थाओं के मध्य मतभेदों की अधिक व्यापक समझ विकसित हो सके जो सामान्य और कम सटीक वर्गीकरण को चुनौती देती हो। ■

सभी पत्राचार इमानुएला लोम्बार्डो को <elombardo@cps.ucm.es> पर प्रेषित करें।

> बहुत दूर का संकट?

कोविड–19 पश्चात् यूरोपीय संघ की लिंग व्यवस्थाएं

रॉबर्टा गुएरिना, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यूके, **हीथर मैकरे,** यॉर्क विश्वविद्यालय, कनाडा, और **एनिक मैसेलॉट,** कैंटरबरी विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड द्वारा

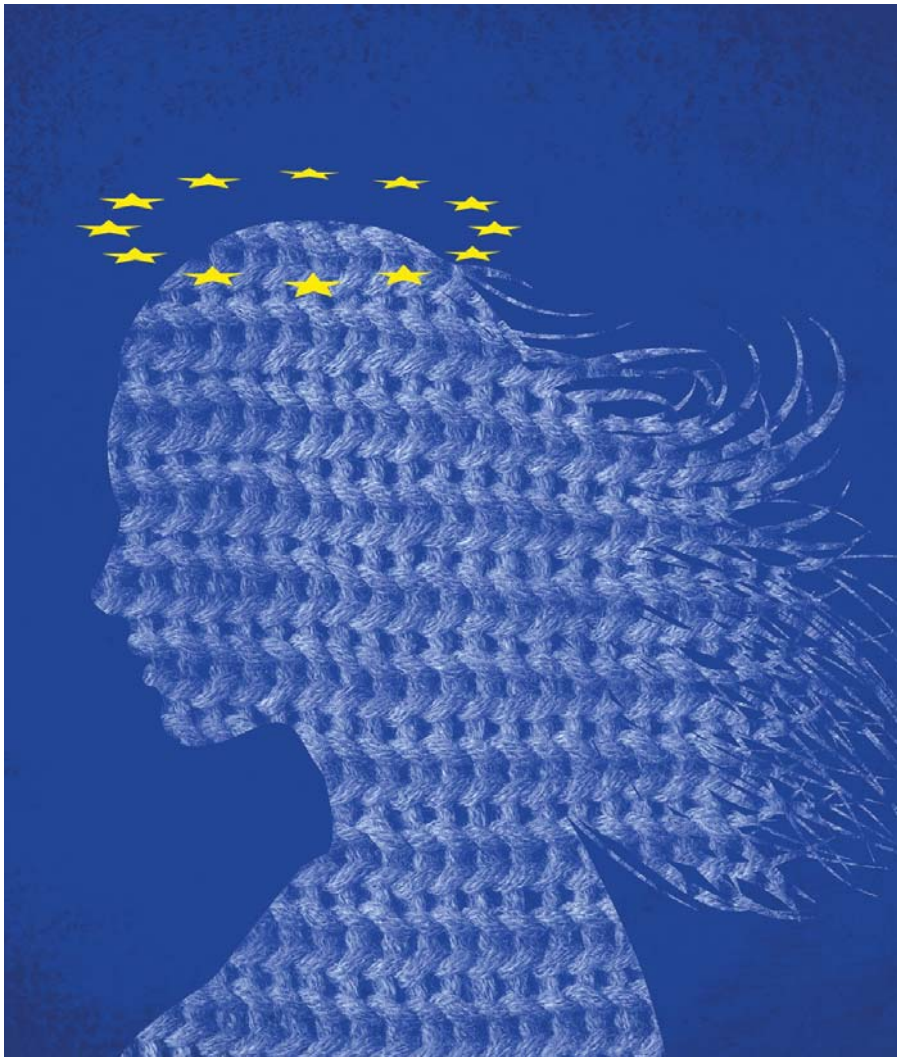

पिछले संकटों की तुलना में महामारी ने यूरोपीय संघ में अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने–बाने को बनाए रखने में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। अरबु द्वारा चित्रण।

वर्ष 2020 को ऐसे साल के रूप में याद किया जाएगा जब दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। कई टिप्पणीकारों के लिए, कोविड–19 के फैलाव ने स्थापित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक निश्चितताओं तथा वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था को निर्देशित करने वाले तमाम मानदंडों को अस्त–व्यस्त कर दिया। कुछ विद्वानों ने इस संकट को पृथ्वी पर हमारे प्रभाव और सामाजिक–राजनीतिक संरचनाओं की की परस्पर सम्बद्ध प्रकृति पर विमर्श करने के एक अवसर के रूप में देखा है। यूरोपीय संघ जो पहले से ही कई अन्य संकटों से जूझ रहा था, उसके लिए यह महामारी एक अस्तित्वगत दुविधा लेकर आयी है: यह वह संकट है जो विघटन के द्वार खोलता है ? या यह एक नए और अधिक समावेशी संघ की परिकल्पना करने का अवसर प्रदान करता है? हमारे विश्लेषण के लिए अधिक विचारणीय रूप से यह है कि महामारी के बाद लैंगिक व्यवस्था में एक अभिकर्ता के रूप में यूरोपीय संघ की क्या भूमिका है? और यूरोपीय संघ की लिंग व्यवस्थाओं का क्या भविष्य है?

यूरोपीय संघ की सीमाओं के भीतर इस संकट के लिंगीय और नस्लीय प्रभाव के साथ साथ एक लिंग अभिकर्ता के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका व संस्थानों द्वारा समानता संबोधन की रणनीतिक तैनाती को अच्छे से प्रलेखित किया गया है। वर्तमान बहुसंकटों का प्रभाव, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके तहत कई और अतिव्यापी संकट यूरोपीय संघ की लिंग शासन व्यवस्था पर "अस्तित्व की स्थिति" में विलीन हो जाते हैं, एक महत्वपूर्ण मोड़ को रेखांकित करता है। यह उभरता परिदृश्य शायद पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सिल्विया वाल्बी का मानना है कि इन बहुसंकटों के दबाव में यूरोपीय संघ की लिंग शासन व्यवस्था कुछ मामलों में सामाजिक–लोकतांत्रिक से अधिक नवउदारवादी–सार्वजनिक लिंग

> >

शासन की दिशा में बढ़ रही है। हालाँकि अन्य मामलों में यह विरोधी रुझानों की तरफ बढ़ रही है। हमारे विशेषण के सन्दर्भ में, ये बहुल संकट यूरोपीय संघ के मूल्यों और पहचान की एक परीक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेष रूप से अपनी सीमाओं के साथ–साथ अपने बाहय भागीदारों और पड़ोसियों के लिए एक लैंगिक अभिकर्ता के रूप में यूरोपीय संघ की निर्धारित भूमिका के संबंध में।

> संकट का एक लंबा इतिहास

यूरोपीय एकीकरण की कहानी संकट की ही कहानी है। ये संकट और इन संकटों के पश्चात के समाधानों को आम तौर पर आर्थिक अवसरों को खोलने व नए राजनीतिक स्थान बनाने के रूप में पौराणिक कथाओं के जरिए वर्णित किया जाता है। यूरोपीय संघ के विद्वानों के रूप में हमने सीखा कि यूरोपीय एकीकरण की परियोजना की जड़ें बीसवीं सदी के यूरोप की जटिल भू–राजनीतिक गतिशीलता में निहित हैं। युद्धग्रस्त यूरोप की राख से उठे फीनिक्स की तरह, यूरोपीय संघ ने 70 वर्षों में अधिकांश भाग के लिए महाद्वीप पर शांति को बनाए रखने में मदद की है। निश्चित रूप से यह एक आंशिक इतिहास है। यह बाल्कन में संघर्ष के साथ–साथ ब्लॉक की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर एकल बाजार के प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय संघ की विफलताओं को नजरअंदाज करता है। इसके अलावा, एक अंतर्विरोधी नारीवादी लेंस को अपनाने से पता चलता है कि ऐसे अवसर सभी के लिए समान रूप से सुलभ नहीं हैं। इसके बजाय लगातार उपजे संकटों ने सामाजिक न्याय और समानता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताओं को हाशिए कर दिया है।

कोविड–19 संकटों की श्रृंखला में नवीनतम है। शायद पिछले संकटों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से, इस वैश्विक महामारी ने निजी क्षेत्र के साथ–साथ औपचारिक अर्थव्यवस्था में भी श्रम के लिंगीय और नस्लीय विभाजनों को उजागर किया है। पोस्ट–कोविड पुनर्बहाली योजना के फोकस को समझने से हम अर्थव्यवस्था और लिंग व्यवस्था के भविष्य के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और विजन का आकलन कर सकते हैं। हमारे लिए यहां सवाल यह है कि क्या वाल्बी द्वारा उल्लेखित लिंग व्यवस्था में बदलाव का संतुलन कम लोकतांत्रिक शासन की ओर जा रहा है या यह और अधिक समावेशी भविष्य की कल्पना करने वाले नए क्षैतिजों को खोलता है। इस प्रकार 2020 के बाद के समझौते को 2008 के यूरो संकट (मित्त्वयत्तता की संबद्ध राजनीति) और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में चल रहे मानवीय संकट तथा और अधिक खतरनाक प्रवास मार्गों व अंत में ब्रेक्सिट और पूरे महाद्वीप में यूरोप विरोधी लोकलुभावन आंदोलनों के उदय द्वारा परिभाषित बहुसंकटों के ऐतिहासिक संदर्भ में इसे समझा जाना चाहिए।

> कोविड–19 के तहत लिंग व्यवस्था

कोविड–19 संकट के पहले चरण के दौरान, ध्यान पैन–यूरोपीय प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लचीलेपन पर केंद्रित था। स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों, डॉक्टरों और नर्सों को वायरस के खिलाफ लड़ाई में नई अग्रिम पंक्ति के रूप में कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए नायक की तरह देखा गया। इस चरण के दौरान, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षित हुआ। जैसे जैसे कई परिवारों ने घर से संचालित होने वाले काम और जीवन को पुनर्संगठित किया, स्कूली शिक्षा और देखभाल का बोझ काफी हद तक महिलाओं पर पड़ा। वास्तविकता यह है कि महिलाएं हर हाल में अधिकांशतः अवैतनिक, अदृश्य और आवश्यक देखभाल प्रदान करना जारी रखती हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था का संबल देता हैं। इस दौरान पैन–यूरोपीय प्रवृत्ति तेजी से एक निजी लिंग व्यवस्था की ओर झुक रही थी जिसने श्रम के पारंपरिक लिंग विभाजन की पुनः पुष्टि की।

कोविड–19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों ने एक नवउदारवादी लिंग व्यवस्था में अंतर्निहित समानता आधारित मॉडल की सबसे मूलभूत विफलताओं में से एक को उजागर किया। श्रम बाजार तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने और स्कूली उम्र के बच्चों के साथ महिलाओं की सक्रियता ने घरों में देखभाल के काम में गहराई से निहित लिंग विभाजन को चुनौती देने के लिए बहुत कम काम किया है। पिछले संकटों की तुलना में, इस संकट ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के साथ–साथ औपचारिक अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए सामाजिक प्रजनन के निरंतर महत्व को स्थापित किया है। "फ्रंटलाइन वारियर्स की तरह वायरस से लड़ रहे" प्रमुख कार्यकर्ता के रुप में सफाईकर्मियों, नर्सों, देखभालकर्मियों में और डॉक्टरों में कई महिलाएं हैं। कई मायनों में कोविड–19 के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाओं ने पुरुष–अर्जक मॉडल से जुड़े मूल्यों की लंबी परम्परा को उजागर किया है। विडंबना यह है कि वैश्विक महामारी के दौरान यूरोपीय समाज को बनाए रखने वाला काम महिलाओं द्वारा किया गया जिसे एक प्रकार से कम–मूल्यवान और कम इज्जतदार माना गया और अर्थव्यवस्था के आधिकारिक लेखांकन में और यूरोपीय संघ की लिंग व्यवस्थाओं के विस्तार में बड़ी आसानी से नजरअंदाज और अदेखा किया गया। ऐसा लगता है कि 2019 में यूरोपीय संघ के कार्य जीवन संतुलन निर्देश को अपनाने से वैश्विक महामारी के दौरान देखभाल करने वालों पर दोहरे बोझ के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में बहुत कम मदद मिली है। हालाँकि "ईयू देखभाल नीति" के उद्भव के लिए एक मंच बना, जिसे ईयू पोस्ट–कोविड रिकवरी प्लान में शामिल किया जाना है।

यूरोपीय संघ की लिंग व्यवस्था पर इस बहु आयामी संकट का क्या प्रभाव होगा? यूरोपीयन आयोग की पुनर्बहाली योजना यह सोचने का अवसर है कि यूरोपीय संघ किस प्रकार का संगठन बनने जा रहा है। इस दृष्टि में एक "न्यायसंगत रुपांतरण" और पुनर्प्राप्ति का समर्थन करने के लिए समान रूप से महत्वाकांक्षी बजट के साथ एक स्पष्ट महत्वाकांक्षा शामिल है। जो प्रश्न अनुत्तरित है वह यूरोपीय संघ के लिंग व्यवस्था और उसके घटक डोमेन पर इस निवेश के प्रभाव से संबंधित है। ■

सभी पत्राचार रोबर्टा गुएरिना को <roberta.guerrina@bristol.ac.uk> पर प्रेषित करें।

> आग से खेलना:
पुरुषत्व का समाजशास्त्र

रॉविन कॉनेल, प्रोफेसर एमेरिटा, सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया, और महिलाओं और समाज (आरसी 32) और संकल्पनात्मक और शब्दावली विश्लेषण (आरसी 35) पर आईएसए शोध समितियों के सदस्य द्वारा

सिडनी विश्वविद्यालय कैंपस में गिलगमेश की आधुनिक प्रतिमा। गिलगमेश को अपने हाथ में पकड़े हुए शेर से लड़ने के बाद यहां अहानिकर चित्रित किया गया है। श्रेयः Gwil5083 / Creative Commons.

मर्दानगी के बारे में सवाल –एक पुरुष की सामाजिक स्थिति पर कब्जा करने के विभिन्न तरीके –किसी भी तरह से नए नहीं हैं। चार हजार वर्ष पहले सुमेरियन–अक्कादियन *महाकाव्य गिलगमेश* ने दो विपरीत मर्दानगी की कहानी सुनाई, गिलगमेश की सभ्य राजशाही और जंगली आदमी एनकीडु की। हेलेनिक साहित्य के महान क्लासिक, द इलियड आवेगी और अपूर्ण साथी पेट्रोक्लस और कटु, कुशल कातिल,अकिलीज के मध्य प्रेम की कहानी है। दरअसल वह रिश्ता होमर की कहानी का आधार था। मर्दानगी का आधुनिक समाजशास्त्र किंवदंतियों पर निर्भर नहीं है, यद्यपि हमें सत्ता, हिंसा और कामरेडशिप की कहानियों में इसकी गहरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को याद रखना चाहिए। जैसा कि दक्षिण अफ्रीकी मनोवैज्ञानिक कोपनो रैटल हमें याद दिलाते हैं, ''पारंपरिक'' पुरुषत्व को अधिक सरल बनाना आसान है। वास्तविक परंपराएं बहुल, जटिल और विवादित हैं।

> उद्भव: सेक्स भूमिकाओं से संरचनात्मक सिद्धांत तक

सामाजिक संकटों, औपनिवेशिक विजय से लेकर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और महिला आंदोलनों की चुनौतियों से मर्दानगी के अर्थ को संदेह में रखा जा सकता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पुरुषत्व के अग्रणी मनोविश्लेषणात्मक अन्वेषण (फ्रायड, जंग और सर्वोपरि एडलर द्वारा) महिलाओं के मताधिकार आंदोलन और मध्य यूरोप में ''नूतन महिला'' के विचार के साथ मेल खाते हैं। यह वह समाज था जहाँ जर्मन नारीवादी शिक्षक मथिल्डे वेर्टिंग द्वारा लिंग पर प्रथम पूर्ण रूप से विकसित समाजशास्त्रीय सिद्धांत विकसित हुआ था।

मर्दानगी पर आधुनिक शोध के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ 1970 के दशक में महिला मुक्ति वैश्विक आंदोलन था। उस समय, लिंग को समझने के लिए अग्रणी सामाजिक–वैज्ञानिक फ्रेमवर्क ''यौन भूमिकाओं'' का विचार था। यह मास मीडिया, सामाजिक मनोविज्ञान और शिक्षा और स्वास्थ्य कार्य जैसे व्यावहारिक क्षेत्रों में एक सुपरिचित विचार बना हुआ है। पुरुषत्व के विकास की व्याख्या यौन भूमिका को सीखने के रूप में की जा सकती है, जबकि धूम्रपान, खराब आहार और युवा पुरुषों में सड़क दुर्घटनाओं को पुरुष भूमिका मानदंडों के परिणामों के रूप में देखा जा सकता है।

यौन भूमिकाओं का विचार लिंग के सामाजिक विश्लेषण का एक उपयोगी प्रथम सादृश्य है। यह इस विश्वास का एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करता है कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व आनुवंशिकी या ईश्वर द्वारा तय किए जाते हैं। यह उन एजेंटों (माता–पिता, मास मीडिया, आदि) पर ध्यान आकर्षित करता है जो मानदंडों को परिभाषित करते हैं और सीखने को प्रभावित करते हैं। यह अवधारणा मानती है कि यदि उन्हें नियंत्रित करने वाले सामाजिक मानदंडों बदलें तो यौन

>>

भूमिकाएं बदल सकती हैं। 1970 के दशक में, कई नारीवादी समूहों ने महिला भूमिका के लिए मानदंडों को बदलने के प्रयास किये। कुछ कार्यकर्ताओं ने महिला मुक्ति के साथ–साथ ''पुरुष मुक्ति'' की बात करते हुए पुरुष भूमिका के लिए भी ऐसा ही करने का प्रयास किया। इस एजेंडें ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1981–82 में गठित पुरुषों के लिए एक प्रगतिशील राष्ट्रीय संगठन को प्रभावित किया।

लेकिन सेक्स भूमिका की अवधारणा में गंभीर कमजोरियां जल्द ही स्पष्ट हो गईं। आमतौर पर यह माना जाता था कि किसी भी समाज में एक पुरुष भूमिका और एक महिला भूमिका होती है। अनुभवजन्य शोध ने बार–बार कई लैंगिक पैटर्न दिखाए। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मौजूद धन, आय और भूमि के स्वामित्व में बड़े पैमाने पर लिंग अंतर की भूमिका सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सका। अधिक से अधिक, यह आर्थिक असमानता में समायोजन दिखा सकता है। यौन भूमिका सिद्धांत को, अंततः, सत्ता और हिंसा के मुद्दों के साथ बड़ी कठिनाई थी।

1980 के दशक तक, कई देशों में सामाजिक वैज्ञानिक भूमिका/मानक दृष्टिकोण से परे काम करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लिंग को वृहद स्तरीय सामाजिक संरचना के रूप में माना, जिसमें अर्थव्यवस्थाओं और राज्यों के साथ–साथ परिवार और अंतर–व्यक्तिगत संबंध सम्मिलित थे। उसी समय, समलैंगिक मुक्ति और नागरिक अधिकार आंदोलनों के साथ–साथ महिला मुक्ति के विचार से प्रेरित हो कर पुरुषत्व के अधिक जटिल चित्र बनाए जा रहे थे। समाजशास्त्रियों ने मनोविश्लेषण, नृवंशविज्ञान और मात्रात्मक अनुसंधान से भी प्रेरणा ली।

1985 में, सिग्रिड मेट्ज–गोकेल और उर्सुला मुलर ने जर्मनी में पुरुषों के जीवन और दृष्टिकोण पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण को रिपोर्ट करते हुए, *डेर मान* प्रकाशित किया। उसी वर्ष, एक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक घोषणापत्र ''टुवर्ड अ न्यू सोशियोलॉजी ऑफ मस्क्युलिनिटी'' प्रकाशित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यकर्ता संगठन के सम्मेलन में ''पुरुषों के अध्ययन'' के बारे में तीन सत्र आयोजित किए गए। इससे पहले भी, भारत में आशीष नंदी ने उपनिवेशवाद में मर्दानगी के निर्माण के अपने शानदार लेख *द इंटिमेट एनिमी* (1983) को प्रकाशित किया था।

> वैश्विक भूभाग

एक दशक के भीतर, अनुसंधान का एक क्षेत्र स्थापित किया गया था, जिसे जर्मन में ''पुरुषों के अध्ययन'' (''महिलाओं के अध्ययन'' के समानांतर), ''मैनरफोर्सचुंग'' (पुरुषों पर शोध), ''पुरुषत्व अध्ययन'' ''पुरुष और पुरुषत्व पर महत्वपूर्ण अध्ययन'' या इसी तरह के वाक्यांश के रूप में जाना जाता है। इसके प्रारंभिक केंद्र समृद्ध देशों और क्षेत्रों: जर्मनी, स्कैंडिनेविया, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में थे। विश्वविद्यालयों ने पुरुषों के अध्ययन विभागों की स्थापना नहीं की। बल्कि, पुरुषत्व के बारे में शिक्षण आमतौर पर व्यापक लैंगिक–अध्ययन कार्यक्रमों में, या समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य और अन्य मानव विज्ञान के विभागों में लैंगिक पाठ्यक्रमों में किया जाता था।

1990 के दशक के दौरान और उसके बाद, विशेष पत्रिकाओं का निर्माण किया गयाय अब पांच अलग–अलग देशों में मर्दानगी से संबंधित प्रकाशित होने वाली आठ शोध पत्रिकाएं हैं। विशेष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए कई पहल की गई हैं, लेकिन कुछ ही जारी हैं। हालाँकि, शोधकर्ताओं के सम्मेलन 1990 के दशक से अक्सर होते रहे हैं। ग्रंथ सूची के एक शक्तिशाली पराक्रम में, प्रकाशनों की एक बहुत व्यापक सूची 1992 से ऑनलाइन रखी गई है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में माइकल फ्लड द्वारा समन्वित किया गया है, यह www.xyonline.net. पर ओपन–एक्सेस है ।

चर्चाएँ शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय थीं, और अनुसंधान क्षेत्र तेजी से वैश्विक हो गया। सदी के अंत तक, भारत, चिली, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और नॉर्डिक देशों से मर्दानगी पर न केवल व्यक्तिगत लेख बल्कि शोध के पूरे संग्रह सामने आए थे या आने वाले थे। हिंसा की रोकथाम के लिए पुरुषों के साथ अनुसंधान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा बहुराष्ट्रीय स्तर पर प्रायोजित किया गया है, उदाहरण के लिए दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों में। मर्दानगी और खेल, आपदाओं में मर्दानगी, और स्वदेशी मर्दानगी जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए अधिक बहु–देश संग्रह दिखाई दिए हैं।

इस विश्वव्यापी प्रयास में, पुरुषत्व अनुसंधान का सबसे निरंतर कार्यक्रम जोस ओलावरिया, टेरेसा वाल्डेस और चिली में उनके सहयोगियों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, पुस्तकों और अनुसंधान परियोजनाओं की श्रृंखला है। यह कार्यक्रम बीस वर्षों से अधिक समय से उत्पादक रूप से चल रहा है, और हाल ही में एक वर्षगांठ खंड: *मैस्कुलिनिडेड्स एन अमेरिका लैटिना: वीन्टे एनोस डी एस्टुडियोस वाई पॉलिटिकस पैरा ला इगुल्डैड डी जेनेरो* के साथ मनाया गया है।

क्षेत्र का हमेशा एक व्यावहारिक पक्ष रहा है। मुक्ति आंदोलनों की शुरुआती कड़ी का मतलब बदलती मर्दानगी और उत्पीड़न से लड़ने में दिलचस्पी थी। अनुसंधान और सक्रियता का संयोजन करते हुए लिंग आधारित हिंसा को कम करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, –चाहे यह कार्य कितना भी कठिन रहा हो। लड़कों की शिक्षा, परामर्श और मनोचिकित्सा, और पुरुषों के स्वास्थ्य के मुद्दों (आहार, दुर्घटना की रोकथाम, धूम्रपान, शराब की खपत, कार्यस्थल तनाव और यौन संचारित रोगों सहित) सहित पेशेवर क्षेत्रों में पुरुषत्व अनुसंधान ने तेजी से जगह बनाई।

> मर्दानगी के बारे में विचारों को बदलना

कोई भी शोध क्षेत्र स्थिर नहीं रह सकता; शोध, आखिरकार, हमारे ज्ञान को बढ़ाने और सही करने के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले चालीस वर्षों में, मर्दानगी अनुसंधान ने निश्चित रूप से बहस, बदलाव और कभी–कभी झटके देखे हैं।

बहसों में से एक का संबंध ''आधिपत्य पुरुषत्व'' की समाजशास्त्रीय अवधारणा से है। यह विचार 1980 के दशक के दौरान एक संरचनात्मक विश्लेषण में पेश किया गया था, जो पुरुषत्व के मध्य पदानुक्रम को पुरुषों और महिलाओं के बीच समग्र असमानताओं के साथ जोड़ता है। तब से, वर्चस्ववादी पुरुषत्व के विचार का उपयोग अक्सर सामाजिक संरचना के पृष्ठभूमि विश्लेषण के बिना किया जाता रहा है। इस सरलीकरण के बावजूद, इस अवधारणा ने मर्दानगी अनुसंधान को लिंग संबंधों में शक्ति और असमानता के बारे में जागरूक रखने में मदद की है। इसलिए यह मर्दाना कुलीनों पर शोध के साथ–साथ स्कूलों, कार्यस्थलों और जनसंचार माध्यमों के अध्ययन में महत्वपूर्ण रहा है।

लेकिन हम संरचनात्मक निर्धारण पर अधिक जोर दे सकते हैं। उस समस्या के जवाब में, मर्दानगी की परिभाषा और अभ्यास में लचीलेपन पर अधिक जोर दिया गया है। उत्तर–संरचनावादी दृष्टिकोण जो जेंडर को मुख्य रूप से विवेचनात्मक शब्दों में समझते हैं, ने इसका समर्थन किया है। यह सुझाव कि अधीनस्थ मर्दानगी के पहलुओं को अपनाने से पुरुषत्व के आधिपत्य रूप बदल सकते

> >

हैं, विशेष रूप से दिलचस्प हैं। इस विचार ने ''हाइब्रिड मर्दानगी'' की अवधारणा को जन्म दिया है, जो यह समझने में सहायक है कि लिंग के क्रम कैसे बदलते हैं।

परिवर्तन का प्रश्न एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विषय को उठाता है। हम पुरुषत्व के अधिक समतावादी रूपों को कैसे सिद्ध करते हैं, जो हम उम्मीद कर सकते हैं, पुरुषों के लिए लिंग–समान समाज में रहने के तरीकों को पूर्वनिर्धारित करते हैं? शुरुआती दिनों से ही इस तरह के शोधों की भरमार रही है। शोधकर्ताओं ने पर्यावरण आंदोलन में, ''निष्पक्ष परिवारों'' में गृहकार्य साझा करने वाले पतियों पर, घर–पति बनने वाले श्रमिकों पर, अधिक व्यस्त पितृत्व का अभ्यास करने वाले युवाओं पर, शांति कार्यकर्ता बनने वाले सैनिकों पर, फिर से कल्पना की जा रही मर्दानगी को देखा है। कई देशों में सामाजिक दृष्टिकोण के सर्वेक्षणों में युवा पीढ़ी में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता और समलैंगिक पुरुषों की अधिक स्वीकृति के प्रति अधिक प्रतिबद्धता पाई गई है। क्या हमें इन प्रतिमानों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मर्दानगी का एक नया रूप बहस का विषय है। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि शोध सकारात्मक बदलाव की कहानियों के साथ–साथ हिंसा और उत्पीड़न की कहानियों को भी जन्म देता है।

> दुनिया की तस्वीर को जटिल बनाना

समाजशास्त्र के कई अन्य क्षेत्रों की तरह, पुरुषत्व का अध्ययन प्रतिच्छेदन के विचार से प्रभावित हुआ है। मर्दानगी पर शोध ने बहुत पहले सांस्कृतिक मतभेदों को मान्यता दी थी, खासकर सामाजिक वर्ग के संबंध में। *लर्निंग टू लेबर* (1977) में ब्रिटिश वर्किंग–क्लास यूथ का पॉल विलिस का अध्ययन एक उल्लेखनीय उदाहरण है। हाल के दशकों में जातीयता, नस्ल और स्वदेशी के प्रश्न अधिक ध्यान में आए हैं।

''इंटरसेक्शनलिटी'' ने क्रॉस–कटिंग सामाजिक पदानुक्रमों के लिए एक नाम प्रदान किया, लेकिन ज्यामितीय रूपक ने अक्सर अंतर की एक स्थिर तस्वीर तैयार की। कोलंबिया में उनके शोध पर आधारित मारा विवेरोस विगोया की *लेस क्यूलर्स डे ला मस्कुलिनिटे* (2018) जैसे हालिया काम से पता चलता है कि ऐतिहासिक रूप से गतिशील उपचार कैसे सत्ता, उत्पीड़न और सामाजिक संघर्ष की वास्तविकताओं को उजागर कर सकता है।

क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण, पुरुषों और मर्दानगी पर सामाजिक शोध अधिक उत्तर औपनिवेशिक, गैर–औपनिवेशिक, स्वदेशी और वैश्विक दक्षिण दृष्टिकोणों को शामिल कर रहा है। एक दशक तक भारत में आशीष नंदी द्वारा उपनिवेशवाद में मर्दानगी का अध्ययन और एओटेरोआ न्यूजीलैंड में जॉक फिलिप्स का अध्ययन व्यावहारिक रूप से अकेला था। इतिहास का यह क्षेत्र अब बहुत समृद्ध है। उत्तर–औपनिवेशिक और अर्ध–परिधीय देशों से सर्वेक्षण, नृवंशविज्ञान, संस्थागत अध्ययन, और मर्दानगी के बारे में सिद्धांत की बढ़ती संपत्ति भी है। अब हमारे पास, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका से, एक सामान्य खाते की शुरुआत है कि कैसे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और उत्तर–औपनिवेशिक निर्भरता ने मर्दानगी के निर्माण को आकार दिया है।

> ज्ञान की राजनीति

मैंने इस लेख को ''आग से खेलना'' कहा, क्योंकि मर्दानगी पर गंभीर शोध शक्तिशाली हितों के खिलाफ होने की संभावना है। सामाजिक अनुसंधान और सिद्धांत आम तौर पर पारंपरिक मान्यताओं के लिए खतरनाक होते हैं जो सामाजिक पदानुक्रमों की रक्षा करते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूहों – अरबपतियों, अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रबंधकों, जनरलों, राजनीतिक अभिजात वर्ग, धार्मिक अधिकारियों को देखते हैं –हम दृढ़ता से मर्दाना समूहों को देख रहे हैं। बैकलैश आश्चर्य की बात नहीं होगी, और बैकलैश आ गया है।

मर्दानगी पर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें शोध–आधारित साहित्य नहीं है; बल्कि वे एक काल्पनिक ''सच्चे मर्दानगी'' के पॉप मनोविज्ञान उत्सव हैं। 1980 के दशक में मर्दानगी पर अनुभवजन्य शोध के लिए मुझे जो पहला अनुदान मिला था, उस पर राष्ट्रीय संसद में रूढ़िवादी राजनेताओं ने हमला किया था। लिंग अध्ययन के पूरे क्षेत्र को हाल ही में हंगरी की सत्तावादी सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अन्य सरकारें आम तौर पर मानविकी और सामाजिक विज्ञान को डी–फंडिंग कर रही हैं। ''लिंग सिद्धांत'' पर हमले हाल ही में कैथोलिक चर्च में अति–रूढ़िवादियों से आए हैं, एक अभियान में जो अब दक्षिणपंथी दलों और आंदोलनों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है।

तो यह शोधकर्ताओं के लिए शांतिपूर्ण क्षेत्र नहीं है! लेकिन सामाजिक विज्ञान और सामाजिक न्याय संघर्ष दोनों के लिए मर्दानगी की गहरी समझ मायने रखती है। यह लिंग और कामुकता के अध्ययन और पारिवारिक अध्ययन से लेकर औद्योगिक समाजशास्त्र तक के क्षेत्रों में अनुसंधान का एक आवश्यक हिस्सा है। मर्दानगी के बारे में ज्ञान हमें सामाजिक परिवर्तन के दबाव और परिवर्तन के प्रतिरोध दोनों को समझने में मदद करता है। ज्ञान का यह क्षेत्र समाजशास्त्रियों को सामाजिक आंदोलनों और पेशेवर प्रथाओं दोनों के साथ नए संबंध प्रदान करता है। शायद सबसे महत्वपूर्ण, मर्दानगी के अध्ययन ने शक्ति की हमारी समझ में एक नया आयाम जोड़ा है, और कैसे शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में अंतर्निहित हो जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि यह काम जारी रहना चाहिए। ■

सभी पत्राचार रॉविन कॉनेल को <raewyn.connell@sydney.edu.au> पर प्रेषित करें।

> मोना अबाजा को श्रद्धांजलि (1959–2021)

माइकल बुरावे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यूएसए द्वारा

मोना अबाजा, द अमेरिकन यूनिवर्सिटी, काहिरा में अपने डेस्क पर।

द कॉटन प्लांटेशन रिमेम्बर्ड से उनकी तस्वीरों की प्रदर्शनी में मोना अबाजा।

5 जुलाई 2021 को दुनिया ने अपने एक महान समाजशास्त्री को खो दिया। दो साल से अधिक समय तक कैंसर से जूझने के बाद मोना अबाजा आखिरकार हमें छोड़ कर चली गई। अंत तक वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए दृढ़ थी, अंतिम सांस तक उन्होंने राजनीति के उतार–चढ़ाव और महामारी का सामना किया, अंत तक उन्होंने अपने दोस्तों के जीवन आग्रहों का पालन किया। असहनीय पीड़ाओं को झेलते हुए, शरीर के कई अंगों के कामकाज करना बंद कर देने के बावजूद भी, उन्होंने बर्लिन में अपने बिस्तर से काहिरा में अमेरिकी विश्वविद्यालय के अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना जारी रखा। अपने जीवंत अकादमिक करियर के दौरान उनका लेखन मिस्र की ग्रामीण महिलाओं, इस्लाम और पश्चिम के बीच संबंध, शहरी उपभोक्ता संस्कृति, मिस्र की पेंटिंग और अरब स्प्रिंग तक विस्तृत था।

मोना अबाजा का समाजशास्त्र उनकी अंतिम दो पुस्तकों में पूर्णता लिए एक कला रूप में भी दिखता है। *द कॉटन प्लांटेशन रिमेम्बरड* (2013) उनके परिवार की जायदाद का एक इतिहास है, जो कई दशकों से चल रहे अपने लेखाकारों, क्लर्कों, श्रमिकों और किसानों की आंखों और साक्षात्कार के प्यार भरे वृतांतों एवं खींचे गए सुन्दर फोटो से सजी है। उनकी अंतिम आखिरी पुस्तक *कैरो कोलाजेस* (2020) 2011 की जनवरी क्रांति के बाद के दशक के दौरान एक असंभव शहर में जीवन का एक गीतात्मक प्रतिपादन है। काहिरा के केंद्र में स्थित उनकी ईमारत के अंदर और बाहर होने वाले नाटकों को जीवंत रूप से कैप्चर करता यह नृवंशीय प्रतिभावान कृति लिफ्ट के बार बार टूटने, ठीक होने के इर्द गिर्द घूमता है। यह पूरे शहर का एक रूपक है –यूटोपिया और डिस्टोपिआ का जादुई मिश्रण।

अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन के साथ–साथ अरबी में भी धाराप्रवाह मोना एक योजक थीं जो बहुत स्पष्ट साफ–सुथरे वर्गीकरण ों–उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम और स्थानीय–महानगरीय से लबरेज थीं और दूसरों की दुर्दशा के प्रति हमेशा उदार और सहानुभूति पूर्ण रवैया रखती थीं। वे *ग्लोबल डायलॉग* की करीबी साथी थी जिसमें अरब स्प्रिंग के उत्थान–पतन के उनके ब्यौरे "तहरीर स्क्वायर में क्रांतिकारी क्षण" के सचित्र अविस्मरणीय वर्णन से प्रारम्भ कर "द वॉर ऑफ द वॉल्स", ''मिस्र की प्रति–क्रांति की हिंसा'' और अंत में "क्रांतिकारी मिस्र के बाद का भाग्य" पर एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था। नीचे हम मोना के कुछ मित्रों और सहकर्मियों द्वारा श्रद्धांजलि को प्रकाशित कर रहे हैं। ■

विनिता सिन्हा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर से

मोना अबाजा का जाना एक ऐसी क्षति है जिसे शब्दों में बयां करना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं उसे तब से जानती थी, जब उसने अपने दक्षिणपूर्व एशियाई शोध के दौरान सिंगापुर में समय बिताया। एक असाधारण समाजशास्त्री, कर्मठ कार्यकर्ता, गंभीर नारीवादी चिंतक और एक संरक्षक जिसने अपने साथियों सहित छात्रों को भी समान रूप से प्रेरित किया। उनके निधन ने एक अथाह शून्य छोड़ दिया है। निःसंदेह, उनकी प्रतिबद्ध, तीक्ष्ण और भावुक विद्वता अग्रणी रही। एक सम्मानित वैश्विक विद्वान के रूप में उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उदय उस समय हुआ, जब दुनिया भर के शिक्षाविद् लिंग, नस्ल और धार्मिक पूर्वाग्रहों के इतिहास से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मोना अथक परिश्रम करने वाली, ऊर्जावान और आत्मा की उदारता से भरी हुई इंसान थी। तब भी जब वे अपने जीवन में व्यक्तिगत संघर्षों का भी सामना कर रही थीं। उनकी समावेशी मानवता की दृष्टि, जो भेदभाव भरे इतिहास और पूर्वाग्रहों के अवशेषों के प्रति

> >

संवेदनशील थी, की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक थी। उनके पास दृष्टिगोचर अत्याचारों के खिलाफ बोलने और कार्रवाई करने का दृढ़ विश्वास और साहस था। मैंने हाल के वर्षों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आईएसए की बैठकों में मोना के साथ अंतर्क्रिया की थी, जहां मैंने हमेशा उन्हें एक साधारण मानवता का विस्तार जारी रखते हुए देखा जो विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के युवा और महिला विद्वानों के प्रति उनकी परवाह और चिंता के बारे में बताता है। वे नारीवादी विद्वान् के रूप में एक प्रेरणादायक रोले मॉडल और सलाहकार थी जो हमारे सामाजिक संसार को गहनता से अंकित करने वाली कामुकता, लिंग और शक्ति की गतिशीलता को पुर्नसंगठित करने के लिए प्रतिबद्ध थीं। ये चीजें हमारे सामाजिक संसार को गहराई से चिह्नित करती हैं। सबसे बढ़कर, मैं मोना की टिमटिमाती आँखों, उसकी संक्रामक मुस्कान और एक सुस्त सम्मेलन सत्र से निकलकर दोस्त के साथ एक कप कॉफी पीने का समय चुराने की इच्छा के लिए मैं हमेशा याद करुँगी। मोना, शांति में रहो। आप बहुत याद आती हो। ■

ब्रायन टर्नर, ऑस्ट्रेलियाई कैथोलिक विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया द्वारा

मोना एक चमकदार करिश्माई बुद्धिजीवी थीं। जिनकी रुचियों का फैलाव आसान विवरण की अवहेलना करता है। उनकी असामयिक मृत्यु मित्रों, छात्रों, काहिरा में अमेरिकी विश्वविद्यालय और व्यापक शैक्षणिक जगत के लिए एक दुखद आघात है। मैं भाग्यशाली था कि मेरा अपना जीवन मोना के प्रक्षेपवक्र से अक्सर प्रतिछेदित हुआ। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड, जर्मनी में बीलेफेल्ड, नीदरलैंड, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज, काहिरा और सिंगापुर में उनका साथ मिला। उन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन में अग्रणी ब्रिटिश पत्रिका *थ्योरी, कल्चर एंड सोसाइटी* में अपना काम अक्सर प्रकाशित किया –लेकिन उनके शोध में 2013 में कपास के बागान के इतिहास जैसे अदभुत विषय भी शामिल है। 1990 में बीलेफेल्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी और एक साथ कई भाषाओं पर उनके अधिकार के साथ मोना एक सच्ची महानगरीय महिला थीं जिसका काम और जीवन पूर्व व पश्चिम के मध्य सेतु था। इस्लामी विद्वान अक्सर मध्य पूर्व पर विशेष ध्यान केंद्रित करने तक सीमित रहते हैं, जबकि शुरुआत से ही मोना ने अपने काम में मिस्र, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंतर्संबंधों को जोड़कर संबोधित किया। 2002 में उनका पहला प्रकाशन *डिबेट्स ऑन इस्लाम एंड नॉलेज इन मलेशिया एंड इजिप्ट* "ज्ञान के इस्लामीकरण" के क्षेत्र में अग्रणी था जिसका महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। ■

सुआद जोसेफ, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस, यूएसए द्वारा

मैं मोना अबाजा से बीस वर्ष वर्ष पहले मिला था, जब मैं दो साल तक काहिरा में अमेरिकी विश्वविद्यालय में कैलिफोर्निया शिक्षा विदेश कार्यक्रम का निदेशक बना तो मुझे उनके विभाग में ही पदस्थापित किया गया था। तब वे मुझे एक गायब रहने वाली लगती थी क्योंकि वे इतनी प्रतिष्ठित थी और उनकी इतनी मांग थी की वे अक्सर बीज व्याख्यानों और अन्य सम्मानों के आमंत्रणों के फलस्वरूप अक्सर यात्रा पर रहती थी। राहत के क्षण में, जब कभी हमें इत्मीनान से बाते करने का मौका मिला, आपसी दोस्तों के घर पर या रात के खाने पर, उसने मुझे अपनी प्रतिभा और अपनी समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि के साथ मिस्र और अरब क्षेत्र की चीजों के प्रति अपने जुनून से चकित कर दिया। उनकी यह प्रतिबद्धता मिस्र के 2011 के प्रतिरोधों में तेजी से चमकी। मोना ने अपने अध्ययन और पड़ताल के विषयों में मिस्र में 2011 के विरोध प्रदर्शनों को बहुत प्रतिबद्धता के साथ लिया। जैसा उन्होंने और अन्य लाखों लोगों ने आधुनिक मिस्र और अरब क्षेत्र के सबसे आशावादी क्षणों में भाग लिया, वे अपने राजनीतिक और विद्वतापूर्ण जुड़ाव के साथ प्रतिबद्धता के कारण अलग से दिखाई दीं। प्रदर्शनकारियों ने जिसे क्रांतिकारी संचार की रचनात्मक भाषा के रूप में तैयार किया, मोना उन्हें अध्ययन और जांच के केन्द्रीय विषय के रूप में लिया जैसे "तहरीर स्क्वायर" के आसपास की इमारतों की दीवारों पर बने बैल के सींग के भित्तिचित्र जो लोगों को बोलने के लिए बुला रहे थे। वह प्रतिदिन चौक पर जाती थी, विद्रोह की आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए भित्तिचित्रों की तस्वीरें खींचती थी, उन ऐतिहासिक क्षणों को चिह्नित करती थी जिन्होने मिस्र के लाखों लोगों की कल्पना, आशा और भावना को पकड़ लिया था। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे तहरीर के चारों ओर चौक के आस–पास की तमाम गलियों में घुमाया और उस रचनात्मकता का वर्णन किया जिसने बोलने और सुनने के लिए संघर्ष किया। मोना ने उन सबको सहेजा, रिकॉर्ड किया, और उनका दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने उस कला को इतिहास में बदल दिया। मैं उनकी बातों और उनके क्रांतिकारी संघर्ष की गहरी समझ तथा रोजमर्रा के जीवन में मिस्रियों को सशक्त बनाने की उनकी जीजिविषा का कायल हूं।

वर्षों बाद, मैंने और मेरी सह–संपादक जीना जातारी ने उन्हें मध्य पूर्व की महिलाओं के विषय में हमारी पुस्तक *हैंडबुक ऑफ मिडिल ईस्ट वीमेन* (रूटलेज) में आलेख देने के लिए आमंत्रित किया। वह पहले से ही बीमार थी। फिर भी तमाम दर्द के बावजूद उन्होने लिखा। उनकी मृत्यु के कुछ ही सप्ताह पहले हमने इस पुस्तक को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। मोना अब इस दुनियां में नहीं थी लेकिन हमारे पास उनका लिखा शानदार अध्याय था। किसी भी जरुरी संशोधन के लिए मोना की प्यारी बेटी ''लौरा स्टौथ" ने हमारे साथ काम करने की सहमति दी है। मोना फिर कहीं गायब हो गई। वह तो हमेशा हमारे पास है। हमारे पास उनका महान लेखन है जिसमें वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। ■

पॉल आमेर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा, यूएसए द्वारा

मोना अबाजा पारंपरिक पश्चिम–केंद्रित समाजशास्त्र में सबसे अक्षम अंतराल को पाटने के लिए एक वैश्विक मॉडल प्रदान करती है। जो शहरी से ग्रामीण, धार्मिक विषयों से आर्थिक विषयों और सौंदर्य से सामग्री तक को विभाजित करता है। इस कारण से मोना का काम समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक क्रांति है। उसके हाथों में मिस्र का संश्लेषण समग्र रूप में 21वीं सदी के समाजशास्त्र के लिए एक दृष्टि बन जाता है। उनके द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ की संख्या आश्चर्यजनक है। जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र को आकार देने वाला और अजस्र योगदान करने वाला है। उपभोक्ता संस्कृति का उनका शहरी समाजशास्त्र विवादास्पद और कमोडिटीकृत स्थानों के आर्थिक नृविज्ञान से समृद्ध है। उनका ग्रामीण समाजशास्त्र दुनिया के विभिन्न हिस्सों (मलेशिया, यूरोप, मध्य पूर्व) में रोजमर्रा के इस्लाम के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से लिंग और वर्ग पर नवीन दृष्टिकोण लाता है। कला का उनका समाजशास्त्र स्थानीय ''स्ट्रीट'' भाषायी दृष्टिकोण से प्रभावित है जो स्मृति, शोक और स्मृतिकरण का विश्लेषण करने के लिए रिफ्लेक्सिव विधियों का आविष्कार करता है। ये क्षेत्र को आकार देने वाले तीन हस्तक्षेप, एक दूसरे को गतिशील और प्रेरक तरीकों से प्रतिच्छेद करते हुए प्रेरित करते हैं। मोना न केवल महान और विशिष्ट विद्वान थी, वह एक अविश्वसनीय उदारता से भरी गुरु भी थीं। उनकी कक्षाएं प्रसिद्ध थीं। विदेशी विद्वानों का स्वागत करते हुए उन्होंने काहिरा के अमेरिकी विश्वविद्यालय में अपने विभाग को पहचान देते हुए इसे विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। ■

सैयद फरीद अलतास, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर द्वारा

मोना एक असाधारण विद्वान, महान चिंतिक और प्रतिबद्ध मित्र के रुप में एक अद्भुत इंसान थीं। उनके निधन ने मुझे घनिष्ठ और मधुर मित्रता की अनमोलता की याद दिला दी जिसके बिना विद्वता अर्थहीन और अलग–थलग पड़ सकती है।

मेरी नजर में मोना की विद्वता में कई विषय शामिल थे। वह न सिर्फ शानदार और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि वाली थी। उसने मुझे बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से छुआ। उनके शुरुआती शोध ने मिस्र और मलेशिया में ज्ञान उत्पादन की गंभीर जांच की। यह फोकस अद्वितीय था क्योंकि वह उन कुछ विद्वानों में से थीं जिनकी अपने क्षेत्र, अरब दुनिया और मलय–इंडोनेशियाई द्वीप समूह दोनों में गंभीर रुचि थी। दक्षिण–दक्षिण पंथी अनुसंधान और इस पर होने वाली बातचीत आज ज्ञान के विघटन के संदर्भ में चर्चा का विषय है। लेकिन मोना 30 साल पहले यह सब बाते कह रही थी।

मोना के बारे में मेरी सबसे चिरस्थायी याद उस समय की है जब मैंने उनसे 2020 में फोन पर बात की थी। उसका बर्लिन में इलाज चल रहा था। अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद, सिंगापुर में एक हमारे कॉमन मित्र, जो बहुत बीमार था, के बारे में पूछने के लिए उसके पास होश और चिंता थी। मोना एक गंभीर और प्रभावशाली समाजशास्त्री तो थी ही एक दयालु सलाहकार भी थीं। मैं उन्हें एक प्यारे और दयालु इंसान के रूप में ही सबसे अच्छी तरह याद कर पाता हूं। अलविदा मोना..... आप की अगले जन्म की यात्रा आरामदायक हो। ■

सामी जुबैदा, लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, यूके द्वारा

मैं मोना को उनके छात्र जीवन से, फिर विभिन्न यूरोपीय संस्थानों जर्मनी, हॉलैंड, स्वीडन, जहां उसने अपनी बहुआयामी विद्वता हासिल की, में मुलाकातों से कई दशकों से जानती हूं। उसकी संगत और बातचीत हमेशा ही आनंद देने वाली और हास्य से तरोताजा कर देने वाली होती थी चाहे लीडेन में उनके साथ शराब पीना हो या लुंड में दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करना हो। मैंने बड़ी रुचि और खुशी के साथ वर्षों उनके विभिन्न प्रोजेक्टस का अनुगमन किया। मैं विशेष रूप से मिस्र के जीवन और घटनाओं के उनके विशद चित्रण के के प्रति आकर्षित थी जो एक ही समय में विश्लेषणात्मक के साथ व्यक्तिगत भी थे, शहरी जीवन के उतार चढ़ाव को जीवंत करते हुए शॉपिंग माल्स से लेकर आवासीय ब्लॉक्स से लेकर शहर में आवागमन की परेशानियों को हमेशा सूक्ष्मता और व्यंगात्मक हास्य के साथ प्रस्तुत करती थी, यहाँ नृवंशविज्ञान अपनी चरमोत्कर्ष पर था। सबसे उल्लेखनीय तो तहरीर चौक की घटनाओं और उसके बाद की घटनाओं का भावुक वर्णन था जिसमें भित्तिचित्रों का उनका अग्रणी अध्ययन शामिल है। वह सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं बल्कि उनके परिवार के *इज़्बा* और गांव का उनका संस्मरण *द कॉटन प्लांटेशन रिमेम्बर्ड* ग्रामीण जीवन के बदलावों का गहन वर्णन होने के साथ–साथ जीवनी और इतिहास के संयोजन का एक शानदार उदाहरण है। मोना की विभिन्न नृवंशविज्ञानियों में सबसे उल्लेखनीय उनकी फोटोग्राफी है, अंतर्दृष्टि और कलात्मकता का एक अतिरिक्त आयाम है। मोना का इतने जल्दी चले जाना, हम सभी के लिए और अकादमिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ■

मोना अबाजा की प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें:

- *Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt, Shifting Worlds*. Routledge Curzon Press, UK, 2002
- *Changing Consumer Cultures of Modern Egypt: Cairo's Urban Reshaping*. Brill-Leiden co-published with AUC Press, 2006.
- *Twentieth-Century Egyptian Art: The Private Collection of Sherwet Shafei*. The American University in Cairo Press, 2011.
- *The Cotton Plantation Remembered: An Egyptian Family Story*. The American University in Cairo Press, 2013.
- *Cairo collages. Everyday life practices after the event*. Manchester University Press, 2020.

> परिचय: भारतीय समाजशास्त्र में नई दिशाएँ

सुजाता पटेल, उमिया विश्वविद्यालय, स्वीडन, समाजशास्त्र के इतिहास (आरसी 08), शहरी और क्षेत्रीय विकास (आरसी 21), वैचारिक और शब्दावली समाजशास्त्र (आरसी 35), ऐतिहासिक समाजशास्त्र (आरसी 56) पर आईएसए की शोध समितियों के सदस्य और आरसी 08 के बोर्ड सदस्य द्वारा

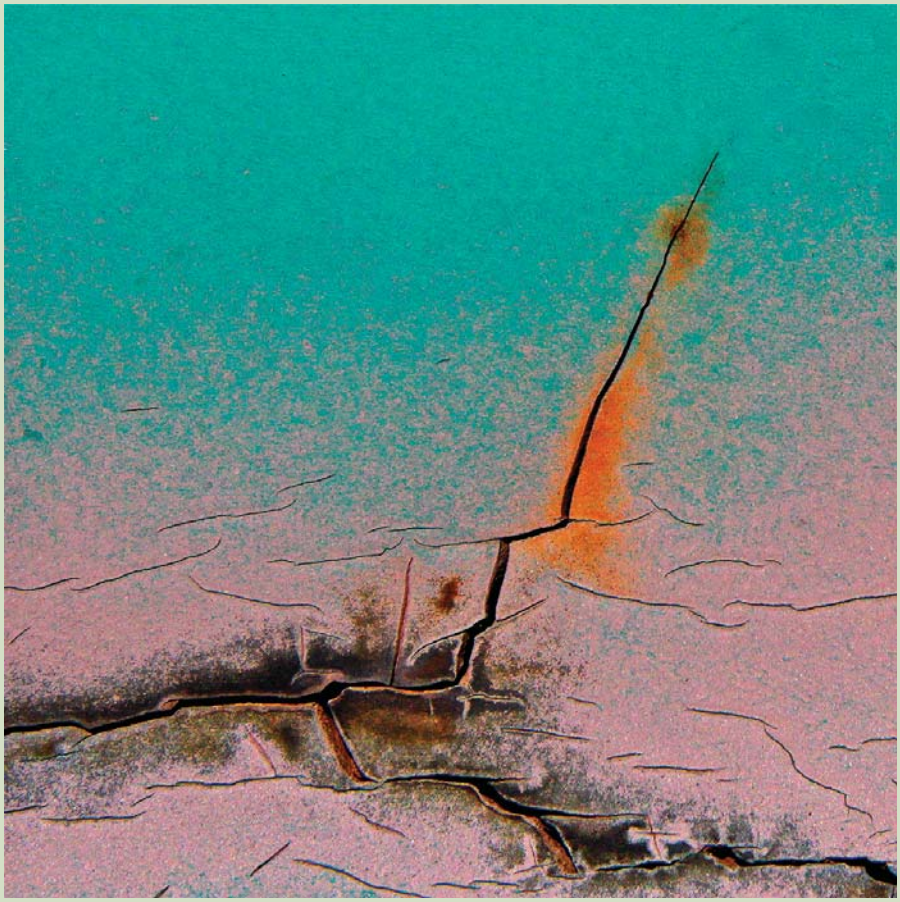

वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक विकास प्रक्रियाओं को समझने के लिए, नए सैद्धांतिक दृष्टिकोण और दिशाओं की आवश्यकता है, क्योंकि वे हाल के वर्षों में भारतीय समाजशास्त्र में तेजी से स्थापित हो गए हैं।
श्रेय: एवलिन बर्ग / flickr.

भारत में समाजशास्त्रीय ज्ञान, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की राजनीतिक परियोजनाओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। हालाँकि, 1980 और 1990 के दशक से, प्रक्रियाओं के दो स्तरों ने व्यक्तियों और समूहों को अधिकारों की एक नई भाषा अपनाने और भारतीय राज्य द्वारा व्यक्त निष्क्रिय नागरिकता की अवधारणा पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। एक स्तर पर, महिलाओं, जनजातियों, निचली जातियों और जातीय समूहों के सामाजिक आंदोलनों, और आत्मनिर्णय और उप–राष्ट्रवाद के क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ–साथ कश्मीर और भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवाद का विकास हुआ है; और दूसरे स्तर पर, हिंदू बहुसंख्यकवाद को मजबूत किया गया है।

इन विकासों का समाजशास्त्रीय सोच पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि नृवंशविज्ञान द्वारा निर्धारित स्थापित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की सामग्री में दरारें दिखाई दीं हैं। विद्वानों की एक नई पीढ़ी भारत में स्वदेशी समाजशास्त्र बनाम पश्चिमी समाजशास्त्र के आसपास शोध प्रश्नों, दृष्टिकोणों और अध्ययन के तरीकों को पुनः परिभाषित करने के बहस से आगे बढ़ गई है। वे प्रश्न करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, और क्या यह भारतीय ''सामाजिक'' को समझने के लिए नृवंशविज्ञान जैसे औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी तरीकों से जुड़ना जारी रख सकता है। यदि नहीं, तो कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते हैं? क्या ये तरीके तुलनात्मक आकलन को बढ़ावा दे सकते हैं? अंत में, न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर में शोषित, भेदभाव और बहिष्कृत लोगों के साथ समाजशास्त्र का क्या संबंध है?

भारतीय समाजशास्त्र पर इस विशेष खंड में प्रस्तुत चार आलेख भारत में गठित हो रहे नए ''सामाजिक'' को समझने के तरीकों पर पुनर्विचार करने के इस प्रयास का हिस्सा हैं। ये आलेख भारतीय राष्ट्र–राज्य द्वारा प्रचारित आधुनिकता की समकालीन प्रक्रियाओं से पूछताछ करते हैं। साथ ही वे उन दरारों और संघर्षों का पता लगाते हैं जो इनसे उत्पन्न हुए हैं, जिसके कारण सबाल्टर्न समूहों को लक्षित प्रत्यक्ष और गुप्त हिंसा की प्रथाओं का जन्म हुआ है तथा जिसके कारण इन समूहों के भीतर और बीच स्तिथ व्यक्तियों के बीच विश्वास प्रभावित हुआ है। आलेख उन सीमाओं और बाध ाओं पर विचार–विमर्श करते हैं जिनका लेखकों ने नृवंशविज्ञान को सिद्धांत और पद्धति के रूप में लागू करने में सामना किया है। वे

> >

अपनी शंकाओं और प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं, और अपने शोध प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करने के लिए नई अवधारणाओं और सिद्धांतों तथा विधियों पर चिंतन का प्रयास करते हैं ताकि इस देश में होने वाले परिवर्तन की जटिल प्रक्रियाओं को समझा जा सके।

राकेश कृष्णन का सुझाव है कि द्वैत के सिद्धांत ने भारत के मध्य क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों– सामाजिक समूहों के संबंध में औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद की नीतियों को निर्धारित किया। एक ओर, औपनिवेशिक और बाद में राष्ट्रवादी राज्यों ने अपनी संस्कृतियों को मुख्यधारा के ''सभ्य'' और ''बसे हुए'' किसान क्षेत्रों से बचाने के लिए अनुसूचित जिलों नामक प्रशासनिक क्षेत्रों के संदर्भ में आदिवासी समूहों की पहचान की। दूसरी ओर, रैखिक परिवर्तन और विकास में विश्वास ने इन शासनों को इन समूहों को सभ्य और आधुनिक क्षेत्रों में मुख्यधारा में लाने के लिए कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इस द्वंद्व ने जनजातीय आंदोलनों द्वारा संघर्षों और अंतर्विरोधों और संप्रभु अधिकारों के दावे को जन्म दिया है। इस विरोधाभास से निपटने के लिए, कृष्णन सीमांत की अवधारणा के उपयोग का सुझाव देते हैं। उनका तर्क है कि मध्य भारत का अध्ययन अव्यवस्थित है, और केवल एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण समाजशास्त्रियों को राज्य और उसके लोगों के बीच द्वंद्वात्मकता का आकलन करने और इस मुठभेड़ के संघर्षों, अंतर्विरोधों और गड़बड़ी को उजागर करने में मदद कर सकता है।

जनजातियों के नृवंशविज्ञानियों/मानवविज्ञानिओं के विपरीत, जिन्होंने द्वैत की वकालत करने वाली औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी नीतियों का समर्थन किया, लिंग अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों ने – 1970 के दशक के उत्तरार्ध से – ऐतिहासिक समझ के लिए नृवंशविज्ञान को छोड़ दिया। स्नेहा गोले का तर्क है कि इस दृष्टिकोण ने भारत में नारीवादी अध्ययनों को जिस तरह से ''महिलाओं'' को औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी फ्रेम में और भारत में महिला आंदोलन की प्रारंभिक अवधारणाओं में माना गया, उन कट्टरपंथी तरीकों से पूछताछ और अस्थिर करने की अनुमति दी है। 1990 के दशक में प्रतिच्छेदन पर बहस की शुरूआत ने इस पुनर्विचार को आगे बढ़ाया है। गोले ने जीवन कथा पद्धति और स्मृति अध्ययनों से अंतर्दृष्टि के उपयोग पर चर्चा की, ताकि यह समझा जा सके कि कैसे नारीवादियों की तीन पीढ़ियां एक अंतर–परिप्रेक्ष्य के माध्यम से अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करती हैं और अपने पहले के सक्रिय हस्तक्षेपों की पुनर्व्याख्या करती हैं। उनका तर्क है कि उनका आकलन उन तरीकों को स्पष्ट करता है जिनमें वर्ग, जाति, कामुकता, विकलांगता और क्षेत्र प्रतिच्छेद करते हैं और उनकी नारीवादी पहचान को फ्रेम करते हैं। उनका तर्क है कि इन जीवन कथाओं ने भारतीय संदर्भ में अंतर्संबंधों को समझने के लिए एक वैचारिक तंत्र प्रदान किया है।

अगले दो आलेख नए संदर्भों में और नए दृष्टिकोण के साथ नृवंशविज्ञान का उपयोग करने के तरीकों पर बहस करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जिसकी आबादी (एक बार फिर से) अंग्रेजों द्वारा जनजातियों के रूप में पहचानी गई थी, विद्रोही आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है। जो कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी जारी रहा, नए राज्य द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम ने सेना को इस क्षेत्र पर शासन करने की शक्ति दी, जिसने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नागरिकों के बजाय अधीन बना दिया गया है। इस प्रकार, सोइबम हरिप्रिया पूछते हैं: जिस तरह से हम नृवंशविज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अभ्यास करते हैं, वह संदर्भ क्या लाता है? सेना और विद्रोहियों के बीच बढ़ते टकराव से सहयोगियों को पहचानने में विश्वास की कमी और भ्रम पैदा होता है। इसके अलावा, मात्र संदेह पर आधारित अंधाधुंध हत्याएं सामाजिक क्षेत्र को अफवाहों से भर देती हैं और आपसी अविश्वास को बढ़ावा देती हैं। सोइबम का तर्क है कि यह भार युक्त संदर्भ एक देशी/अंदरूनी समाजशास्त्री, एक ही जातीय/आदिवासी समूह के सदस्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश करता है। इस संदर्भ में, वह प्रश्न करती हैं कि एक समाजशास्त्री उन तरीकों का विश्लेषण कैसे कर सकता है जिनसे हिंसा सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है? सोइबम हिंसक जगहों में फील्डवर्क करने की पद्धति पर चिंतन करतीं है और तर्क देतीं है कि साहित्यिक ग्रंथों में प्रवेश, नृवंशविज्ञान द्वारा परिभाषित क्षेत्र की तुलना में संदर्भ को अधिक ग्राफिक रूप से समझने में मदद करता है।

इस खंड में अंतिम आलेख शिरीन मिर्जा का है, जो सुझाव देतीं हैं कि नृवंशविज्ञान, जाति विचारधारा को आधुनिकता के साथ जोड़ने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। उनका नृवंशविज्ञान कार्य आधुनिक भारत में शहरी स्वच्छता प्रणाली पर केंद्रित है, जो जाति प्रदूषण का सरकारीकरण करता है। उनका अध्ययन मुंबई की स्वच्छता प्रणाली के बारे में है, जहां नगर पालिका ने कचरे को चुनने और साफ करने के लिए ''प्रदूषित'' जातियों की भर्ती की है, जो कि जाति पदानुक्रम में सबसे नीचे हैं: सफाई, झाड़ू लगाना, वध करना और कचरा हटाना। वह सुझाव देती हैं कि कलंक और जाति श्रम की अवधारणाएं वर्तमान संदर्भ को समझने में मदद करती हैं, जिसमें इस श्रम गतिविधि में काम करने वाले लोग प्रदूषण से अभिव्यंजित होते हैं। वह जाति और धर्म की अलग–अलग पहचान दिखाने के लिए दलित मुस्लिम और दलित हिंदू कचरा बीनने वालों का मामला लेती हैं। यह नृवंशविज्ञान कार्य उन्हें उस औपनिवेशिक समझ से प्रश्न करने के लिए मजबूर करता है जिसने हिंदू जातियों को अन्य अल्पसंख्यकों से विभाजित किया था। मौजूदा और प्राप्त धारणाओं को अस्थिर करते हुए, मिर्जा ने मुंबई के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग में जाति और कलंक के शारीरिक इतिहास का वर्णन किया है। उनकी नृवंशविज्ञान उन तरीकों का खुलासा करता है जिनमें कलंकित शरीर को जाति की भौतिकता के एक पात्र के रूप में उत्पादित किया जाता है और विशेष वस्तुओं के संबंध में आकार दिया जाता है।

ये आलेख उन बारीकियों को उजागर करते हैं जिनका मूल्यांकन समाजशास्त्रीय सोच में ''अच्छे अभ्यासों '' के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। वे न केवल एक रिफ्लेक्सिविटी के लिए तर्क देते हैं जो ज्ञान उत्पादन और इसके प्रसार की राजनीति का आकलन कर सकता है, बल्कि समकालीन को समझने और इसे मानवता की चिंताओं से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक आकलन की प्रासंगिकता की पुष्टि भी करता है। ■

सभी पत्राचार को सुजाता पटेल को <patel.sujata09@gmail.com> पर प्रेषित करें ।

> मध्य भारत में जनजातीय भूगोल का विखंडन

राकेश एम. कृष्णन, हैदराबाद विश्वविद्यालय, भारत द्वारा

इस निबंध में, मेरा तर्क है कि आदिवासी समुदायों की समाजशास्त्रीय समझ को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक समाजशास्त्र महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, जनजातीय समुदायों पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण की सूचना देने वाले मानवशास्त्रीय साहित्य में संदर्भ और ऐतिहासिक आयाम दोनों का अभाव है। इसलिए, विश्लेषण की श्रेणियों का तुलनात्मक ऐतिहासिक पुनर्संदर्भीकरण जनजातीय दुनिया की अव्यवस्थित उलझनों को स्पष्ट कर सकता है। मेरा तर्क है कि एक श्रेणी के रूप में ''सीमान्त'' इन अव्यवस्थित उलझनों, राज्य शक्ति की सीमाओं और लोगों की आकांक्षाओं को पकड़ सकती है। यहां सीमांत के दो अर्थ हैं, बस्तियों के किनारे जिसके आगे अज्ञात मौजूद है और जो किसी विशेष विषय या उनकी गतिविधियों के बारे में अज्ञात है। एक अवधारणा के रूप में सीमान्त आलोचनात्मक रूप से सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक इंजीनियरिंग की विभिन्न संस्कृतियों के बीच इंटरफेस का मूल्यांकन करता है।

> औपनिवेशिक भूगोल

अंतर और पदानुक्रम की धारणाओं ने आदिवासी समुदायों के बारे में औपनिवेशिक नीतियों को निर्धारित किया है– पहाड़ी मध्य भारत, नदियों का एक क्षेत्र, घने जंगल और समृद्ध खनिज संसाधनों के क्षेत्र, में रहने वाले सामाजिक समूह। औपनिवेशिक विस्तार ने ''जनजाति'' शब्द का मानकीकरण किया; औपनिवेशिक शासकों ने इसे अफ्रीकी उपयोग से उधार लिया था। उन्होंने इन समूहों को उनकी जीववादी धार्मिक प्रथाओं को देखते हुए, ''आदिम,'' ''जंगली,'' और ''बर्बर'' के रूप में वर्गीकृत किया किया और उन्हें बसे हुए हिंदू जाति किसान समुदायों से अलग किया। उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत से विद्रोह और विद्रोह के स्थल रहे इन ''जंगली इलाकों'' को शासित करने में कठिनाई के चलते औपनिवेशिक अधिकारियों ने 1874 के अनुसूचित जिला अधिनियम को पारित किया। औपनिवेशिक कानून ने अलग–अलग भौगोलिक क्षेत्रों का निर्माण किया, जहाँ औपनिवेशिक राज्य ने आदिवासी समुदायों को, सभ्य समाज के बाहर रख नियंत्रित किया। इन प्रशासनिकध्भौगोलिक परिक्षेत्रों के भीतर, औपनिवेशिक प्रशासकों और मिशनरियों ने जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक ''सभ्यता मिशन'' प्रारम्भ किया। शासन की औपनिवेशिक योजना में जनजातीय समुदायों की अधीनस्थ स्थिति ने राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर के लोगों और स्थानों के रूप में आदिवासी समुदायों की पूर्व–औपनिवेशिक समझ को तोड़ दिया।

औपनिवेशिक कानूनों ने आदिवासी समुदायों के प्राकृतिक संसाधनों और भूमि पर अतिक्रमण किया, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में तनाव पैदा हुआ। आदिवासी समुदाय ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध करने वाला पहला सामाजिक समूह था, क्योंकि शिकारी पूंजीवाद, भूमि अतिक्रमण, गतिहीनता और कर प्रणाली ने उनके जीवन के तरीकों को अव्यवस्थित कर दिया था। औपनिवेशिक प्रशासनिक विद्वानों और मानवविज्ञानियों ने, नृवंशविज्ञान सर्वेक्षणों, प्रलेखन और रिपोर्टों के माध्यम से, मतभेदों और पदानुक्रमों को स्थापित करने की परियोजना में सहायता की। स्वतंत्रता–पश्चात् की राज्य नीतियों और मानवशास्त्रीय अध्ययनों ने उन्हें जंगलीपन के भीतर निहित लोगों के रूप में संदर्भित करना जारी रखा, जिन्हें सभ्य संस्कृतियों के बाहर के क्षेत्रों तक सीमित रखने की आवश्यकता थी।

> आदिवासी समुदाय और राष्ट्र निर्माण परियोजना

औपनिवेशिक–पश्च और स्वतंत्रता–पश्चात् के प्रारंभिक वर्षों में, मानवविज्ञानियों ने राष्ट्र–निर्माण परियोजना के भीतर आदिवासी समुदायों के स्थान पर बहस की। ये दृष्टिकोण ''कुलीन जंगली'' की दुनिया के विचार से लेकर हिंदू समाज के साथ आत्मसात करने तक थे। यद्यपि इन दृष्टिकोणों ने अलग–अलग रणनीतियां तैयार कीं, लेकिन उन्होंने आदिवासी समुदायों की अवधारणा में अंतर और पदानुक्रम की औपनिवेशिक समझ को विस्थापित करने के बजाय जारी रखा। जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानवविज्ञानियों की सहायता से, राज्य ने गैर–आलोचनात्मक रूप से औपनिवेशिक श्रेणियों को स्वीकार करते हुए, आदिवासी समुदायों को राष्ट्र–राज्य से सहायता की निरंतर आवश्यकता के रूप में निरक्षर समूहों के रूप में देखा। नृविज्ञान सहित राष्ट्रवादी सामाजिक विज्ञानों ने भी इन भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादन की शक्तियों और लोगों की आकांक्षाओं में ऐतिहासिक परिवर्तनों पर विचार नहीं किया। न ही उन्होंने उत्तर–औपनिवेशिक समाज में औपनिवेशिक मतभेदों और पदानुक्रमों की ऐतिहासिकता और प्रासंगिकता के बारे में पूछताछ की। इसलिए, आदिवासी समुदायों को विकास चक्र के पहले चरण में, स्थिर और परिवर्तन – प्रतिरोधी, अधीनस्थ सामाजिक समूहों के रूप में माना जाता रहा। दो कार्यनीतियों ने अनुवर्ती नीतियों को निर्धारित किया – हिंदू किसान समुदायों से सुरक्षा और भेद, और साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्रों का पूंजीवादी विकास। राज्य और सामाजिक विज्ञानों ने आदिवासी उप–योजना क्षेत्रों और एक एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी के रूप में क्षेत्रीय आधार पर आदिवासी समुदायों के ''विकास'' का अनुसरण किया। शैक्षिक, चिकित्सा, और अन्य अवसंरचनात्मक पहलों ने ''आधुनिकता'' प्रदान की, भले ही निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को कानूनी विशेषाधिकार और सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त थी।

राष्ट्रवादी सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास ने आदिवासी क्षेत्रों में पूंजी और गैर–आदिवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नहीं

>>

''जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानवविज्ञानियों की सहायता से, राज्य ने गैर–आलोचनात्मक रूप से साक्षर पूर्व समूहों के रूप में आदिवासी समुदायों को राष्ट्र–राज्य से सहायता की निरंतर आवश्यकता में समूहों के रूप में देखते हुए औपनिवेशिक श्रेणियों को स्वीकार कर लिया''

उलटा। इसके अलावा, राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माण ने आदिवासी समुदायों को राष्ट्र–राज्य से अलग कर दिया। खनन और बांधों जैसी प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण परियोजनाओं में वृद्धि ने आदिवासी परिदृश्य को पंगु बना दिया, जिससे जनजातीय स्वायत्तता आंदोलनों को गति मिली। 1970 के दशक से, कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों और मोहभंग जनजातीय समुदायों ने बेदखली द्वारा संचय की प्रक्रिया को मुखर रूप से उजागर करना शुरू कर दिया।

प्रत्येक आदिवासी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं बना और सभी आदिवासी लोग अलग–थलग नहीं रहे। कुछ पहाड़ी समुदायों को कोई सुरक्षा नहीं मिली, और उनकी भूमि शहरीकरण और पर्यटन के लिए स्थान बन गई। अन्य पहाड़ी और वन समुदायों ने वृक्षारोपण और लकड़ी की खेती के लिए अपनी भूमि खो दी। प्रशासनिक परिक्षेत्रों के बाहर के जनजातीय समुदाय दिहाड़ी मजदूर बन गए, और जो परिक्षेत्रों के भीतर थे वे अलग–थलग और पूंजी के सर्किट से बाहर रहे। औपनिवेशिक और उत्तर–औपनिवेशिक पूंजी द्वारा बढ़ाए गए इस अराजक परिदृश्य का भारत में मानवविज्ञानी/समाजशास्त्रियों द्वारा अपर्याप्त मूल्यांकन किया गया है।

> ''सीमांत'' : सरकारी श्रेणियों को विस्थापित करना

आदिवासी समुदायों का समाजशास्त्र औपनिवेशिक ढांचे से बहुत अधिक प्रभावित है और समावेशी बहिष्कार के राज्य के निर्धारण को गैर–आलोचनत्मक रूप से स्वीकार करता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रशासन के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के माध्यम से उन्हें सामान्य आबादी से एक साथ बाहर करने और शैक्षिक और अन्य समावेशी रणनीतियों के माध्यम से उन्हें एकीकृत करने तथा, मतभेदों और पदानुक्रमों को कायम रखती है। यह काफी हद तक समस्या–समाधान के अनुभवजन्य कार्यों पर केंद्रित सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के मूल्यांकन तक ही सीमित है। इस बीच, राष्ट्रवादी समाजशास्त्रियों के पास आदिवासी समुदायों से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए ऐतिहासिक और तुलनात्मक संवेदनशीलता का अभाव है, जो भारत में वर्चस्ववादी समाजशास्त्रीय परिकल्पना की विरासत का एक हिस्सा है। औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी ढाँचे में जनजातीय लोगों की अधीनता आदिवासी सांस्कृतिक भूगोल के पतन के बजाये एक प्रशासनिक स्थान और इन प्रशासनिक परिक्षेत्रों के अंदर और बाहर जनजातीय इंटरफेस के विशिष्ट प्रक्षेपवक्र जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को रोकती है। ज्ञान–मीमांसा श्रेणियों के साथ जुड़ाव की इस कमी के लिए जनजाति की अवधारणा के निर्माण में निहित शक्ति को विस्थापित करने के लिए एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य के भीतर ऐतिहासिक और भौगोलिक आयामों को फिर से सम्मिलित करने के लिए एक अनुमानी उपकरण की आवश्यकता है। इस प्रकार, एक अवधारणा के रूप में सीमांत, औपनिवेशिक और उत्तर–औपनिवेशिक राज्यों द्वारा गठित भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर जनजाति की श्रेणी को संदर्भित करके मानव विज्ञान की सीमाओं पर सवाल उठाने की अनुमति देता है। एक श्रेणी के रूप में, सीमांत, जनजातीय जीवन जगत में गतिशीलता और प्रवाह और राज्य और उसके लोगों के बीच अव्यवस्थित द्वंद्वात्मकता पर कब्जा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ज्ञात और अज्ञात के बीच एक विभाजक के रूप में, यह राष्ट्रवादी समाजशास्त्र को उपनिवेशवाद और उत्तर–औपनिवेशिक राष्ट्र–राज्य द्वारा स्थापित मतभेदों और पदानुक्रमों के साथ जुड़ने की याद दिलाता है। इसलिए, मेरा तर्क है, सीमांत अवधारणा उन विचारधाराओं को उजागर करती है जो भौगोलिक क्षेत्रों में अंतर्निहित हैं जो ''अधीनस्थ'' सामाजिक समूहों में निहित व्यक्तिपरकता को आकार देते हैं, जिससे हमें सामाजिक विज्ञान पर पुनर्विचार करने में मदद मिलती है। ■

सभी पत्राचार को राकेश एम. कृष्णन को <rakeshmkrishnan@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> नारीवादी प्रतिच्छेदन: नए दृष्टिकोण

स्नेहा गोले, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, भारत द्वारा।

2014 में महाराष्ट्र राज्य के गढ़िंगलाज–कोल्हापुर शहर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में आंदोलन।
श्रेयः संजीव बोंडे /Wikimedia Commons.

यह पत्र नारीवादी क्षेत्रों और उनमें ''महिला'' श्रेणी के पुनर्गठन के साथ संलग्न है। मैं इस बात की जांच करती हूं कि भारत में प्रतिच्छेदन और इसका विशेष वैचारिक प्रक्षेपवक्र (संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंग–प्रजाती के संदर्भ के विपरीत) पद्धतिगत रूप से कथा और स्मृति अध्ययनों को एक साथ लाकर, समकालीन समझ पर पुनर्विचार करने के नए तरीके प्रदान करता है। मैं इसे महाराष्ट्र राज्य से नारीवादी कार्यकर्ताओं (महिला आंदोलन में भाग लेने वाली) के जीवन कथाओं के विश्लेषण के माध्यम से करती हूं। मैं सक्रिय आवाजों को विशेषाधिकार देने का चुनाव करती हूँ, क्योंकि वे नारीवादी राजनीति के विषय को समझने और संचालन में सबसे अधिक निवेशित हैं। मैंने जिन कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया, वे एक भाषा समुदाय से तीन पीढ़ियों तक विस्तारित थे; साक्षात्कारों से पता चलता है कि उन्होंने अपनी यादों को, प्रतिच्छेदन के सिद्धांत के संदर्भ और जिस तरह से यह महिला की श्रेणी पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है, में पुनः तैयार किया।

> एक एकाश्म ''महिला'' तैयार करना

आधिपत्यवादी औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी ढांचे ने विशिष्ट विशेष रूप में ''महिला'' श्रेणी की कल्पना की। औपनिवेशिक ढांचे में, ''मूल निवासी महिला'' की स्थिति, सभ्यता (या उसके अभाव) के लिए प्रतिनिधि और उपनिवेशवादियों और कुलीन मूल निवासी पुरुषों के बीच राष्ट्रवादी टकराव के माध्यम से ''प्रामाणिक'' ''भारतीय'' परंपरा के आसपास बहस के लिए स्थल बन गई। इसने महिलाओं को राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में –भारत माता से लेकर राष्ट्र के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक के खिलाफ निजी के मूल्यवर्धन अनुभूति के लिए प्रेरित किया। *सवर्ण*/उच्च जाति मध्यवर्गीय महिला ''भारतीय'' महिला के लिए प्रतिनिधि बन गई। वर्चस्ववादी राष्ट्रवादी ढांचा महिलाओं को ''संस्कृति के प्रतीक'' के रूप में दर्शाता रहा, लेकिन उत्तर–औपनिवेशिक राज्य ने भी महिलाओं को समाज के ''कमजोर वर्गों'' के रूप में संबोधित किया, और उन्हें आधुनिकता और परंपरा के भीतर एक साथ स्थापित किया। महिलाओं को संस्थागत परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से या तो जैविक प्रजननकर्ता के रूप में संबोधित किया जाता था या *महिला मंडल* (राष्ट्रवादी रूप में आयोजित महिला संघ) जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से ''गैर–कामकाजी'' पत्नियों के रूप में संबोधित किया जाता था। निम्न–जाति की कामकाजी वर्ग की महिलाओं के साथ–साथ भाषा समुदायों के भीतर परिभाषित क्षेत्रीय भेद इस उत्तर–औपनिवेशिक सूत्रीकरण के लिए अदृश्य और हाशिए पर रहे।

1970 के दशक में, महिला आंदोलन के एक नए चरण ने ज्ञान के निर्माण और संरचनात्मक भेदभाव (वामपंथी विचारधाराओं के माध्यम से समझे गए) और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अग्रभूमि प्रश्नों के एक स्थल के रूप में अनुभव के लिए बहस करके इन प्राप्त श्रेणियों पर पुनर्विचार किया। आंदोलन के इस चरण ने ''परंपरा,'' निजीध्सार्वजनिक विभाजन, और राष्ट्र के प्रतीक के रूप में महिलाओं
>>

की ढलाई को चुनौती दी। इसने ग्रामीण और कामकाजी वर्ग की महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी शोषित मेहनतकशों और उत्पादकों के रूप में भूमिका पर प्रकाश डाला। इसने प्रमुख राष्ट्रवादी और औपनिवेशिक ढांचों को चुनौती दी, लेकिन उनके बीच की असमानताओं की व्याख्या करते हुए उन्होंने विकासध्आधुनिकता की विषय–वास्तु के रूप में महिलाओं को गोचर (एकाश्म तरीके से) बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

> प्रतिच्छेदन की ओर बढ़ना

1990 के दशक ने एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें राष्ट्रवादी सम्भाषण ने महिलाओं को शासन के संवाद के माध्यम से समझने और महिला आंदोलनों द्वारा महिलाओं से लिंग की ओर बदलाव सहित एक परिवर्तन को चिन्हित किया। यह वह संदर्भ है जिसमें दो स्तरों पर प्रतिच्छेदन को स्पष्ट रूप से परिचालित किया गयाः विश्लेषण के लिए एक वैचारिक संबोध के रूप में और विभिन्न उत्पीड़ित समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर–दलीय महिला समूहों द्वारा अपनाई गई एक संगठनात्मक रणनीति के रूप में, जैसेः दलित (इसका शाब्दिक अर्थ है ''टूटा हुआ'' ''लेकिन पूर्व–अछूत जातियों द्वारा एक पहचान चिह्नक के रूप में पुनः पहचान प्राप्त किया है), समलैंगिकोंय मुसलमान (संकटग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्यक)य और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग – सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन द्वारा चिह्नित निचली जातियाँ)। इनमें से प्रत्येक ने एक विशेष प्रतिच्छेदन के अनुभव को संदर्भित किया और भारत में नारीवादी राजनीति की मुख्यधारा से इसके ऐतिहासिक रूप से गायब होने पर प्रश्न उठाया। हालांकि इसे नस्ल–लिंग के इर्द–गिर्द अफ्रीकी–अमेरिकी अवधारणाओं से प्रेरणा मिली थी, भारत में प्रतिच्छेदन का एक जटिल प्रक्षेपवक्र था, क्योंकि लिंग को कई अक्षों – वर्ग, जाति, जनजाति, कामुकता, विकलांगता, भाषा समुदायों और धार्मिक संबद्ध ता के साथ पुनर्विचार किया गया था। दलित नारीवादी सिद्धांत ने दलित महिलाओं के विभिन्न अनुभवों और संघर्षों को केंद्रित करके नारीवादी विषय के रूप में महिला की अस्थिरता को सबसे तेजी से रेखांकित किया, विशेष रूप से जैसा परिवार–विवाह– नातेदारी प्रणाली में परिलक्षित होता है। हालांकि, जातिध्वर्ग या सवर्णध्दलित के युग्मक की तुलना में श्रेणीबद्ध असमानता के रूप में जाति एक अधिक जटिल तस्वीर पेश करती है और इसलिए इसकी अधि ाक जांच की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, मैंने तर्क दिया है कि नारीवादी राजनीति क्षेत्र ''महिला'' श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अंतःप्रतिच्छेदन थीसिस के आलोक में स्थानांतरित हो गया है , जैसा कि उन्हीं कार्यकर्त्ताओं द्वारा समय के विभिन्न बिंदुओं पर वर्णित जीवन कथाओं में बदलाव से स्पष्ट है। नतीजतन, मेरे काम से पता चलता है कि प्रतिच्छेदन सिद्धांत उन तरीकों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संसाधन बन जाता है जिसके माध्यम से ''महिला'' को वर्गीकृत असमानताओं के माध्यम से पुनर्गठित किया जाता है।

> कथा और स्मृति का काम

यदि 1970 के दशक ने नारीवादी कार्यकर्ताओं को उनकी विशिष्ट जाति की स्थिति से उत्पन्न अंतर को कम करने और एक एकाश्म, सार्वभौमिक स्त्रैण अनुभव को चिह्नित करने की अनुमति दी, तो आज के राजनीतिक संदर्भ और जिस तरह से महिलाओं के प्रश्न को पुनः परिभाषित किया गया है, उसने इन कार्यकर्ताओं को उनकी विशेष जाति–वर्ग की स्थिति को समझने और परिवार –विवाह– नातेदारी–कामुकता की संस्थाओं के साथ इनकी पुनः संकल्पना, और इस बात पर विचार करने के लिए कि ये कैसे उनके अनुभवों को आकार देते हैं, के लिए प्रभावित किया है। 1970 और 1990 के दशक में राजनीतिक रंग दिए जाने वालों सहित कार्यकर्ता, अपने बचपन और प्रारंभिक वर्षों को नए चश्मे के माध्यम से याद करते हुए अपने जीवन की समझ बना रहे हैं, कि एक विशेष जाति में पैदा हुई महिलाओं के रूप में और इस प्रस्थिति ने जीवन की परिस्थितियों और अवसरों को कैसे आकार दिया। यहां तक कि वे कार्यकर्ता जिनकी विचारधाराओं ने पहले यह सुझाव दिया था कि जाति को एक पूर्व–आधुनिक श्रेणी के रूप में देखना चाहिए, और आधुनिकता में इसका उपयोग पहचान की राजनीति को दर्शाता है और इसलिए एक राष्ट्रव्यापी नारीवादी राजनीति बनाने में विभाजनकारी था, समकालीन भारत में प्रतिच्छेदन को परिभाषित करने वाली जाति–वर्ग–लिंग–लैंगिकता प्रणाली के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए, अब अपने जीवन का पुनः वर्णन करने के लिए तैयार थे। परिवार, विवाह और नातेदारी की संस्थाओं द्वारा मध्यस्थता वाले जाति–वर्ग समाजीकरण के संदर्भ में स्वयं की कहानी को अब नए सिरे से याद किया गया था। जीवन कथाओं को एक विधि के रूप में उपयोग करने से न केवल सामाजिक स्थिति और विशेषाधिकार की उनकी जी गई प्रतिच्छेदित वास्तविकताओं की यादों की पुनर्व्याख्या करने में मदद मिलती है, बल्कि भारतीय संदर्भ में प्रतिच्छेदन के सैद्धांतिकरण करने में भी मदद मिलती है। इस प्रक्रिया में प्रतिच्छेदन के भारतीय संस्करण के संबंध में नए नारीवादी सिद्धांतों को तैयार करना संभव है।

इस प्रकार स्मृति अध्ययनों के साथ जीवन कथा पद्धति हमें यह देखने में मदद करती है कि नारीवादी क्षेत्र में समकालीन दृष्टिकोण ने एक नए नारीवादी–कार्यकर्ता स्वयं के पुनर्निर्माण को कैसे प्रभावित किया है; वे उनके लिए और नारीवादी अध्ययन के लिए भारत में विभिन्न पदानुक्रमों में विशेषाधिकारध्अधीनता के प्रश्नों को खोलते हैं। इस पद्धति इसका उपयोग, जब वर्चस्ववादी ढांचों जैसे औपनिवेशिक, राष्ट्रीय, या प्रारंभिक नारीवादी के भीतर के भीतर एक अवधारणा के रूप में ''महिला'' विमर्श को चुनौती देने के लिए किया जाता है तो यह न केवल नारीवादी प्रतिक्रियात्मकता के महत्व की ओर इशारा करती है बल्कि यह समकालीन प्रतिच्छेदन कैसे समझा जाये की सैद्धांतिक समझ में मदद करती है। साथ ही, यह पद्धतिगत जुड़ाव हमें सामूहिक राजनीति में बदलाव को समझने और संभावित रास्तों की रूपरेखा तैयार करने के लिए व्यक्तिगत यादों को खोलने और पुनः संदर्भ देने की अनुमति देता है। इस प्रकार प्रतिच्छेदन सिद्धांत को समकालीन भारतीय समाज में जाति समूहों/धार्मिक समुदायों/ भाषा समुदायों के वर्गीकरण की जटिल स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। बेशक, यह देखते हुए कि ये साक्षात्कार एक भाषा समुदाय के भीतर आयोजित किए गए थे, हमारी परिकल्पना एक क्षेत्र में प्रतिच्छेदन के आकलन तक ही सीमित है। लेकिन यह भारत के भीतर अन्य भाषा समुदायों के भीतर मौजूद ऐसे पदानुक्रमों के बीच अंतर और अंतर्संबंधों पर चर्चा के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। यह परियोजना, तब, अन्य क्षेत्रीय और राजनीतिक संदर्भों को समझने के लिए एक टेम्पलेट की पेशकश नहीं करती है, बल्कि इन प्रश्नो पर पहुंचने का एक मार्ग प्रदान करती है। यह कहानी, जो एक विशेष क्षेत्रीयता से ली गई है, भारत में महिला के समकालीन निर्माण की हमारी समझ के लिए कई सबक प्रदान करती है। ■

सभी पत्राचार स्नेहा गोले को <gole.sneha@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> भारयुक्त क्षेत्र:

हिंसक स्थलों में समाजशास्त्र का क्रियान्वयन

सोइबम हरिप्रिया, स्वतंत्र शोध विद्वान, भारत द्वारा

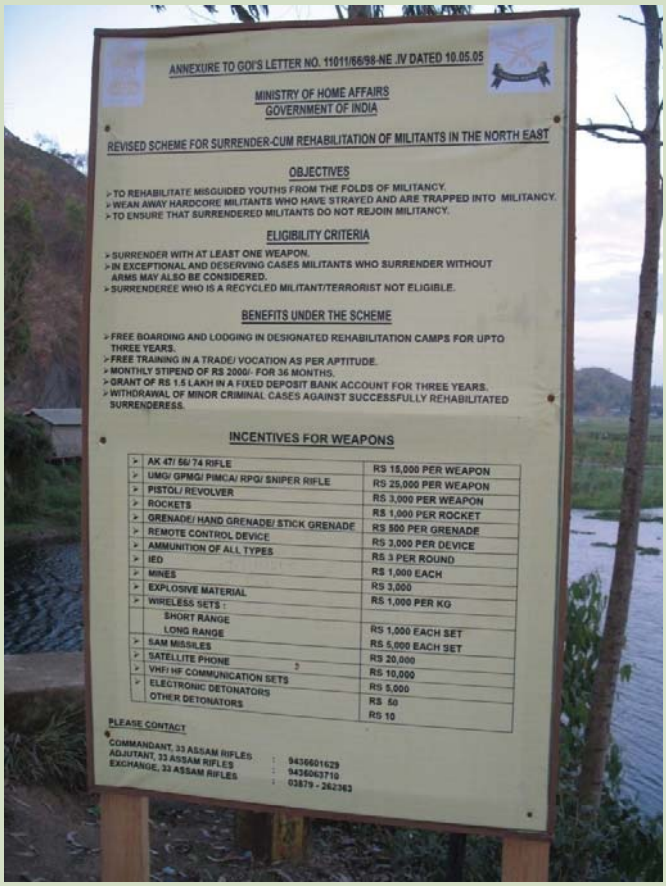

अप्रैल 2011 में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में करंग के पास एक साइनबोर्ड। श्रेय: सोइबम हरिप्रिया।

इस निबंध में, मैं यह विचार करती हूं कि समाजशास्त्र/सामाजिक मानवविज्ञान को राज्य द्वारा उत्पन्न हिंसा की जांच कैसे करनी चाहिए। भारतीय राष्ट्र–राज्य परियोजना का विरोध देश में कई संघर्षों में से एक है, जिसने इसे ग्रस रखा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इस क्षेत्र ने राष्ट्र–राज्य परियोजना के नतीजों का अनुभव किया है और आत्मनिर्णय आंदोलनों के हिस्से के रूप में सशस्त्र संघर्षों द्वारा चिह्नित किया गया है।

नतीजतन, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 (AFSPA) किसी न किसी रूप में उत्तर पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम को छोड़कर) के राज्यों में लागू है। 1958 में असम के तत्कालीन नागा पहाड़ियों में प्रस्तावित किया गया, AFSPA उस राजनीतिक–प्रशासनिक प्रणाली का हिस्सा है जिसके माध्यम से यह क्षेत्र शासित होता है। सशस्त्र बलों को संदेह पर मारने के लिए दी गई विशेष शक्तियां जीवन के अधिकार को निलंबित कर देती हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राष्ट्र की आधिपत्य की धारणा उस क्षेत्र में साझा नहीं की जाती है जहां AFSPA दण्ड से मुक्ति की संस्कृति, अफवाहों के एक नेटवर्क और आपसी संदेह को बढ़ावा देता है।

मणिपुर में, विद्रोही समूह शुरू में चार से बढ़कर 32 समूहों (विभिन्न खंडित समूहों को छोड़कर) से अधिक हो गए हैं। कई शोध कार्य यह स्थापित करते हैं कि राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए वर्षों से सेना का उपयोग करने के कारण हिंसा को सीमित करने की असंभवता सुनिश्चित की है; यह जीवन के हर पहलू को इस तरह से चित्रित करता है कि राज्य या गैर–राज्य के कारण होने वाली मौतों का श्रेय देना व्यर्थ हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकारों पर नागरिक समाज गठबंधन (2016) की एक संयुक्त हितधारकों की रिपोर्ट से पता चलता है कि 30 लाख से कम की आबादी के लिए 50,000 भारतीय सैनिक मणिपुर में तैनात हैं। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान बताता है कि 2000 और 2004 के बीच मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा 450 नागरिक मारे गए थे। इस तरह के आंकड़े मणिपुर को एक ऐसी जगह के रूप में पेश करते हैं जहां राष्ट्र–राज्य, व्यवस्था लागू करने में विफल रहा है। चुनौती उस स्थान को समझने में है जिसे राज्य के कानूनों/नीतियों द्वारा अराजक बना दिया गया है।

> नृवंशविज्ञानियों के लिए चुनौतियां

नृवंशविज्ञान क्षेत्रीय कार्य भारत में पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषय का केंद्र है, जहां समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान के बीच का अंतर धुंधलाता है। एम.एन. श्रीनिवास के समाजशास्त्र के स्कूल के ढांचे में, इस क्षेत्र का उपयोग नृवंशविज्ञान के माध्यम से किया जाता है। शोधकर्ता रोजमर्रा की जिंदगी में उस अर्थ को निकालने के लिए भाग लेता है जो लोग अपने जीवन को देते हैं। यह उस क्षेत्र को ''प्राकृतिक सेटिंग'' के रूप में मान्यता देता है जहां शोधकर्ता एक अंदरूनी सूत्र के रूप में परिचित होने का दावा करता है। अंदरूनी/बाहरी व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं है (हालांकि मोटे तौर पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में ''बाहरी व्यक्ति'' उन लोगों को संदर्भित करता है जो इस क्षेत्र के समुदाय से संबंधित नहीं हैं)। एक ही जातीय समुदाय का सदस्य या उत्तर–पूर्व से होने पर अधिक व्यापक रूप से व्यक्ति को एक अंदरूनी सूत्र बना देता है। हालाँकि, एक ही समुदाय/क्षेत्र से होने के बावजूद, किसी को अभी भी परिजन या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर बाहरी माना जा सकता है।

मणिपुर में मेरे एक शोध का उद्देश्य यह समझना था कि लोग हिंसक मौतों और इससे पैदा होने वाली भय की संस्कृति से कैसे निपटते हैं। एक मणिपुरी होने के नाते, मुझे एक अंदरूनी सूत्र माना जाता था; हालांकि, विश्वास/अविश्वास उन केंद्रीय मुद्दों में से एक था, जिनसे मुझे निपटना था। विश्वास जीतने हेतु, मुझे सबसे पहले क्षेत्र में कार्यरत शब्दावली पर पुनर्विचार करना पड़ा। ''मुखबिर'' और ''सहयोगी'' जैसे शब्द नियोजित करने के लिए समस्याग्रस्त हैं। राज्य के सैन्य तंत्र के एजेंट होने के अपमानजनक अर्थ पैदा

>>

इस तरह की विरोध कार्रवाई आम घटनाएं हैं। श्रेयः सोइबम हरिप्रिया, 2011.

2011 में भारतीय सेना द्वारा मनमाने ढंग से उठाए गए एक युवक का विरोध। श्रेयः सोइबम हरिप्रिया।

करने वाले शब्दों को छोड़ना विश्वास जीतने के लिए पहला कदम है। दूसरे, अनुसंधान जांच के लिए एक सामान्य प्रतिरोध होता ही है। यह महसूस किया जाता है कि अनुसंधान उपकरण हिंसा की ऐतिहासिकता को पकड़ने में विफल होते हैं और अंत में लोगों के औपनिवेशिक नृवंशविज्ञान प्रतिनिधित्व को एक दूसरे के प्रति और समुदाय के बाहर के लोगों से स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण और संदिग्ध के रूप में पुनः पेश करते हैं। एक ओर, ''बाहरी'' अनुसंधान को ऐसे क्षेत्रों में सहभागिता के प्रश्न के रूप में प्रवेश करना चाहिए, भले ही कोई राज्य हिंसा की परियोजना के लिए सक्रिय रूप से सहमति न दे। दूसरी ओर, चूंकि क्षेत्र आपसी संदेह को बढ़ावा देता है, क्षेत्र तक पहुंच अनिवार्य रूप से किसी की पहचान द्वारा मध्यस्थता की जानी चाहिए। चूंकि सामाजिकता की वर्तमान परिस्थितियों को सैन्यीकरण के वर्षों से आकार दिया गया है, इसलिए उपकरणों और विधियों की पर्याप्तता पर सवाल उठाने की जरूरत है। तीसरा, एक कथित रूप से ''अंदरूनी'' शोधकर्ता के रूप में, मुझे इस क्षेत्र तक पहुंच अधिक कठिन लगी क्योंकि लोग राज्य या गैर–राज्य के संबंध में रिश्तेदारों, दोस्तों और संस्थानों को वर्गीकृत करते हैं। क्षेत्र और विधियों पर अधिकांश चर्चाएँ इस बात से जूझती हैं कि क्या ''मुखबिर'' सच कह रहे हैं अथवा नहीं। हालांकि, ऐसे क्षेत्र स्थलों में, शोधकर्ता पुनः अवलोकन की स्थिति में होता है; अर्थात, सत्य, मिथ्याकरण, और विश्वसनीयता का प्रश्न – जो आमतौर पर क्षेत्र पर लागू होता है – अब शोधकर्ता पर निर्भर करता है।

> एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता

प्रवेश प्राप्त करने और ''क्षेत्र'' का विस्तार करने के लिए, मैंने एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण लिया, जिसमे 1980 और 2010 के बीच लिखी गई कविता को शामिल करके क्षेत्र की कथाओं को पूरक बनाया।1980 में, AFSPA को पूरे मणिपुर में विस्तारित किया गया था। मैंने उस अवधि की कविता का उपयोग यह समझने के लिए किया कि कविता में भय की संस्कृति कैसे परिलक्षित होती है (अन्य सांस्कृतिक कलाकृतियाँ, जैसे गीत, कथा, उपन्यास भी व्यवहार्य स्रोत हैं जिनसे खोज की जा सकती है)। उदाहरण के लिए, मैंने थांगजम इबोपिशाक की व्यंग्य कविता ''मैं एक भारतीय गोली से मारना चाहता हूं'' का इस्तेमाल किया। इस कविता में, पांच तत्व –अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश –बिना किसी प्रशंसनीय कारण के, इस स्पष्टीकरण के अलावा कि यह पुरुषों को मारना उनका मिशन था, कवि को उसके घर पर मारने के लिए आते हैं। कवि उनसे भारत में बनी गोली से उसे मारने का अनुरोध करता है। उसका जीवन बक्श दिया जाता है क्योंकि वे उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मैं मौत के दस्तों की गुमनामी को दर्शाने वाले पांच तत्वों का विश्लेषण करती हूं (इस बात को दोहराने के लिए की, राज्य या गैर–राज्य को हिंसा का श्रेय देना असंभव है) जो अपने पीड़ितों को उठाते हैं या उन्हें अपने ही घरों में मार देते हैं। मारने के लिए एक संभावित कारण की कमी का अर्थ है कि किसी की मृत्यु या किसी के जीवन को बख्शा जाना (जैसा कि कवि के मामले में) बेतुका, मनमाना निर्णय है। कवि का अनुरोध राष्ट्र–राज्य का उपहास है जिसके द्वारा जीवन का संवैधानिक अधिकार देने का दावा खोखला है; यह सैन्यीकरण के खिलाफ गुस्सा व्यक्त करता है जिससे हिंसा घरेलू क्षेत्र में घुसपैठ करती है।

इस तरह की कविताएं मौत पर प्रतिबिंबों को एक ऐसे संदर्भ में सुलभ बनाती हैं जहां क्षेत्र कथाएं जीवन के लिए खतरा हो सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मानवविज्ञानियों को कविता के लिए नृवंशविज्ञान को त्याग देना चाहिएय मेरे सुझाव अनुसार यह वे तरीके हैं जो ठोस सबूत के अभाव में हिंसा की जांच करते हैं। शोधकर्ताओं को पद्धतिगत संकरता से सावधान रहने की जरूरत है; हालाँकि, जब नृवंशविज्ञान को एक साहित्यिक शैली के रूप में सुधारा गया है, तो कविता को एक ऐसी शैली के रूप में शामिल नहीं करने का कोई कारण नहीं है जो हिंसा के अनुभव को पकड़ती है जिसे ''तटस्थ'' क्षेत्र प्राप्त करने में विफल होते हैं। क्षेत्र के तथ्यों के साथ, सामाजिक ज्ञान का निर्माण करके कविता मिटाने का विरोध करती है। सामाजिक मानवविज्ञान को इसके लिए अपने अनुसंधान उपकरणों की जांच करने, अपने स्रोतों का विस्तार करने और अन्य विषयों से सीखने की जरूरत है ताकि राज्य द्वारा उत्पन्न हिंसा की साइटों में इसकी आलोचनात्मकता को बनाए रखा जा सके। ■

सभी पत्राचार सोइबम हरिप्रिया को <priya.soibam@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> नगरीय भारत में कलंक और जाति श्रम

शिरीन मिर्जा, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारत द्वारा

देवनार मुंबई का एक उपनगर है जिसे शहर में सबसे बड़ा लैंडफिल होने के कारण प्रमुखता मिली है। श्रेयः शिरीन मिर्जा।

इस आलेख में, मेरा तर्क है कि पहचान का समाजशास्त्र, एक ओर जाति और धर्म को क्रमशः हिंदुओं और मुसलमानों से संबंधित अलग–अलग सामाजिक श्रेणियों के रूप में बनाता है। दूसरी ओर, पूंजीवाद और शहरीकरण की प्रणालियाँ उन प्रथाओं को मिलाती हैं जो जाति और धर्म को कलंकित श्रम और स्थानिक पृथक्करण के माध्यम से परिभाषित करती हैं। इस संदर्भ में, कलंक को एक श्रेणी के रूप में केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्रॉस–कटिंग संरचनाओं का अध्ययन करने और उनकी औपनिवेशिक–राष्ट्रवादी वंशावली के साथ अनुशासनात्मक श्रेणियों को पूर्ववत करने की अनुमति देता है। आलेख का तर्क है कि जटिल वास्तविकताओं को पकड़ने के लिए हमें नई श्रेणियों की आवश्यकता है और नृवंशविज्ञान के माध्यम से, नई श्रेणियां बनाई जा सकती हैं।

> जाति और धर्म का असम्बद्ध विभाजन

जाति का वर्चस्ववादी समाजशास्त्र, कलंकित श्रम और जाति के बीच की कड़ी को हिंदुओं की धार्मिक विचारधारा के साथ–साथ पारंपरिक हिंदू सामाजिक प्रथाओं से ट्रेस करता है । *मनुस्मृति* नामक एक प्राचीन हिंदू ग्रन्थ में उच्चारित *कर्म* (स्वयं के कार्यों से उत्पन्न बल), *धर्म* (धार्मिकता का मार्ग), और *वर्ण* (व्यवस्था) जैसे विचारों से, जाति को, इसकी वैधता प्राप्त करते देखा जाता है। ये विचार पवित्रता और प्रदूषण की धारणाओं को संरचित करते दिखाई देते हैं, जो भारतीय समाज को चार सामाजिक समूहों में विभाजन करने के साथ–साथ *वर्ण* के बाहर स्थित अछूत (*अवर्ण*) जातियों में, जो ''अशुद्ध'' कार्य करते हैं, में अनुष्ठानिक रूप से बांटते हैं। उच्च जाति समूहों को सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ के रूप में मजबूत करने के लिए जाति शुद्धता के सम्भाषणो पर आधारित समाजशास्त्रीय विश्लेषणों को चुनौती दी गई है, जिससे उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होती है। अनुष्ठान शुद्धता और अशुद्धता के प्रबंधन के लिए एक हिंदू सामाजिक व्यवस्था के रूप में जाति की एक असम्बद्ध समझ भी सीमित है क्योंकि यह धार्मिक समूहों में कलंक और जाति–आधारित श्रम के समकालीन स्थानिक प्रथाओं को समझने के लिए एक उपयोगी ढांचा प्रदान करने में विफल रहती है।

असम्बद्ध दृष्टिकोण के भीतर, जाति और धर्म दोनों को ज्ञान–मीमांसा के रूप में और साथ ही अलग–अलग क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है। जाति का यह एक श्रेणी के रूप में ज्ञान मीमांसात्मक विभाजन – जो राष्ट्र और उसकी राजनीति के लिए ''आंतरिक'' है, और एक श्रेणी के रूप में (धार्मिक) अल्पसंख्यक ''बाहरी'' है और जो एक कालातीत इस्लामी विचारधारा या स्थानीय सामाजिक संदर्भों के

> >

अनुकूलन से संबंधित है – जो औपनिवेशिक–राष्ट्रवादी वंशावलीके माध्यम से उभरती है। इस वंशावली के भीतर, एक श्रेणी के रूप में ''अल्पसंख्यक'' एक क्षेत्र के रूप में धर्म का पर्याय है जो जाति के क्षति के कारण उभरता है। औपनिवेशिक–राष्ट्रवादी वंशावली में, जाति और धर्म को सामाजिक कार्यक्षेत्र के रूप में उत्पादित किया जाता है जो राजनीतिक और आर्थिक श्रम श्रेणियों जैसे वर्ग और उत्पादन के तरीकों से वैचारिक रूप से भिन्न होते हैं। तारतम्यहीन सामाजिक श्रेणियों के रूप में जाति और धर्म के बीच यह वंशावली विभाजन भारतीय समाज को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जैसे अलग–अलग धार्मिक समूहों में वर्गीकृत करने के औपनिवेशिक उद्यम का परिणाम है। अतः, जाति और धर्म का सैद्धांतिकरण पूंजीवाद –संचालित शहरीकरण के प्रभावों से मुक्त रहता है। व्यवहार में, हालांकि, यह युग्मक सही नहीं है, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम सहित गैर–हिंदू समूहों को ''अशुद्ध'' श्रम करने के लिए उसी तरह कलंकित किया जाता है। कलंकित श्रम न केवल व्यक्ति को बल्कि समुदाय–स्व को भी सत्तामूलक रूप से अशुद्ध मानता है। यह सत्तामूलक अशुद्धता ब्राह्मणों जैसी ''शुद्ध'' जातियों के लिए उपलब्ध अस्थायी अस्पृश्यता से अलग है, जिसमें अशुद्धता की स्थिति अस्थायी होती है और उस अनुष्ठानिक शुद्धि द्वारा उसे उलटा जा सकता है।

आधुनिकीकरण के सिद्धांतों में निहित सामाजिक परिवर्तन के रैखिक मॉडल की अपनी धारणा के कारण जाति श्रम की समकालीन प्रथाओं की व्याख्या करने में सक्षम होने के कारण आधिपत्यवादी समाजशास्त्र और सीमित है। यह अनुपयोगी है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक विकास पदानुक्रम की बंद व्यवस्था को व्यक्तिगत गतिशीलता के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की एक खुली प्रणाली में परिवर्तित नहीं करता है। इसके बजाय, नगरीकरण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने जाति के संस्थागतकरण को जन्म दिया है, विशेषकर भारतीय शहरों के स्वच्छता विभागों के भीतर।

> कलंकित श्रम और अनुशासनात्मक श्रेणियों को पूर्ववत करना

उदाहरण के तौर पर, औपनिवेशिक बॉम्बे नगरपालिका के स्वच्छता विभाग ने शहरी अपशिष्ट को संदर्भित करने के लिए स्थानीय भाषा में *कचरा* शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें *कचरे* को स्थानीय उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों और स्थानीय कच्ची बस्ती क्षेत्रों से पैदा होते देखा गया था, जिनके स्थानीय समाधान की आवश्यकता थी। इसके अलावा, इसने फारसी शब्द *हलालखोर* को स्वच्छता के लिए आधिकारिक शब्द के रूप में अपनाया। हलालखोर का तात्पर्य निम्न–जाति के मुस्लिम कामगारों से है जिनके लिए सभी भोजन वैध थे। विभाग ने पूर्व में 'अछूत'' जातियाँ, हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम की भी भर्ती की, जिनके ''पारंपरिक'' व्यवसाय को सफाई, झाड़ू लगाना, पशु वध और अपशिष्ट हटाने के रूप में देखा जाता था। नगर पालिका के भीतर जातियों की भर्ती ने इस दावे के आधार पर जाति की पहचान को स्वच्छता श्रम में बंद कर दिया कि अशुद्धता, जाति की पहचान के भीतर समाहित है। यह जातिगत श्रम को आर्थिक लेनदेन के हिस्से के रूप में किए गए मजदूरी श्रम से अलग बनाता है।

1899 में औपनिवेशिक स्वच्छता राज्य द्वारा बनाए गए मुंबई शहर के सबसे बड़े और सबसे पुराने लैंडफिल देवनार में, कूड़ा उठाने का अनौपचारिक श्रम दलित हिंदू मतंग उप–जाति के साथ–साथ बिहारी दलित मुसलमानों द्वारा किया जाता है। जब वे देवनार लैंडफिल में कचरा उठा रहे होते हैं, तो एक मुस्लिम दलित कूड़ा बीनने वाले से मतंग जाति के हिंदू दलित कचरा बीनने वाले को अलग करना मुश्किल होता है। दोनों समुदायों के सदस्य अपनी पीठ पर पॉलीथिन कवर, कांच की बोतलें, फेंके हुए जूते और कपड़े से भरे सफेद प्लास्टिक के बोरे लेकर लैंडफिल से लौटते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चार से पांच बैग उठा कर लाते है जिसे वे *माल* कहते हैं (शाब्दिक रूप से लूट का सामान, जिसे संसाधन के रूप में भी समझा जा सकता है) और कचरे की परतों के बीच खोदने के लिए एक धातु का दरांती जिसे *अकड़ी* कहा जाता है। सिर पर एक टोर्च बंधी होती है, और मोटे जूतों के ऊपर फटे हुए मोजे पहने जाते हैं ताकि वे बेकार सीरिंज और टूटे हुए कांच के चुभने से स्वयं को बचा सकें। यहाँ संचय और फेंकने की पूंजीवादी संस्कृतियों द्वारा उत्पन्न फालतू आधिक्य में जो ''दुर्गन्ध'' के साथ–साथ दृश्य आधिक्य के प्रति उन्मूलन और घृणा के विचार के माध्यम से अलग–अलग पड़ोस के रूप में लैंडफिल का उत्पादन करता है, के साथ कामगार का कार्य समानहै।

मेरा नृवंशविज्ञान कार्य दर्शाता है कि नगरीकरण का यह मॉडल जाति और धर्म की संयुक्त धारणाओं को सह–उत्पादित करता है। इसे देवनार में लैंडफिल के आसपास दलित और मुस्लिम बस्तियों के स्थान–निर्माण इतिहास में देखा जा सकता है, जिसे ''प्रदूषित'' उद्योगों के स्थान के लिए एक खतरनाक बेल्ट के रूप में नियोजित किया गया था। उदाहरण के लिए, 1947 के मास्टर प्लान में, इस क्षेत्र को *कचरा पट्टी* (अपशिष्ट बेल्ट) के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें दलित और मुस्लिम श्रमिक वर्ग की आबादी का पुनर्वास किया गया था। कलंक, इसलिए, पूंजीवादी संचालित नगरीकरण को इस तरह से सह–उत्पादित करता है जो जाति और धर्म की क्रॉस–कटिंग पहचान को मजबूत बनाता है।

मैं कलंक को घृणा और बेचैनी के एक मूर्त अनुभव के रूप में समझती हूं जब एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान को अस्थिर रूप में अनुभव किया जाता है। जाति को कलंक की सामाजिक–राजनीतिक प्रथाओं के एक उपसमूह के रूप में देखा जा सकता है जो अशुद्धता, मलिनता और अव्यवस्था की धारणाओं को परिभाषित करके व्यवस्था और वर्गीकरण की प्रणालियों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। यह जाति और कलंक के बीच संबंधों को इस तरह से सुझाता है कि इतिहास शरीर पर अंकित हो जाता है। इसका अर्थ गंदगी या मैले को एक उद्देश्य के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक श्रेणी के रूप में देखना, जिसकी व्याख्या एक व्यापक सामाजिक–राजनीतिक परिवेश के हिस्से के रूप में नस्लीय, जातीय, यौन और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों की ''अन्य'' प्रथाओं के माध्यम से की जाती है।

सामाजिक–राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में कलंक को अग्रभूमि में रखने से एक व्यापक ढांचे की अनुमति मिलती है जो जाति और धर्म की अनुशासनात्मक श्रेणियों को निरस्त करता है। ऐसा करने के लिए, हमें जाति और धर्म की प्राप्त श्रेणियों से परे जाने की जरूरत है, जिन्हें तारतम्यहीन देखा जाता है, उन्हें कलंकित श्रम के विचार के भीतर एक अनुभवातीत तथापि आकस्मिक श्रेणी, जो राजनीति से विलग नहीं है, के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देता हैः क्या आधुनिकता और नगरीकरण का अर्थ कलंक का सार्वभौमीकरण है? ■

सभी पत्राचार को शिरीन मिर्जा को <shireen@iiitd.ac.in> पर प्रेषित करें।

> डाटा अंतराल

स्त्री–हत्या स्त्रैण हिंसा की पहचान और रोकथाम में बाधा डालता है

मिर्ना डावसन, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एंड लीगल रिस्पॉन्स टू वायलेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ गुएलफ, कनाडा, कैनेडियन फेमिसाइड ऑब्जर्वेटरी फॉर जस्टिस एंड एकाउंटेबिलिटी, और आईएसए थिमैटिक ग्रुप ऑन हिंसा और समाज (टीजी 11) और विचलन और सामाजिक नियंत्रण (आरसी 29) तथा महिला, लिंग और समाज (आरसी 32) पर अनुसंधान समितियों के सदस्य द्वारा

स्त्रैण–हत्या की घटना कोई नई नहीं है; हालाँकि इस पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में नाटकीय वृद्धि अभूतपूर्व है, विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के दौरान। इस ध्यान के समानांतर वैश्विक चर्चाएँ हैं कि क्या समस्या का नाम रखने के लिए ''स्त्रैण हत्या'' शब्द का उपयोग किया जाए, स्त्रैण–हत्या को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए, यह अन्य हत्याओं से क्या व कैसे अलग है और कैसे इन अंतरों को संचालित किया जा सकता है। चर्चाओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम व्यवस्थित रूप से यह प्रलेखित करना है कि महिलाओं की हत्याएं पुरुषों की हत्याओं से कैसे भिन्न होती हैं –स्त्री–हत्या के लिए विशिष्ट लिंग!लिंग–संबंधी प्रेरकों !संकेतकों (SGRMIs) की पहचान करना। SGRMI इस बात की पहचान करते हैं कि महिलाओं के बारे में कथित मानदंडों का पालन करने वाले अपराधियों के स्त्री द्वेषी व्यवहार से हिंसा कैसे उपज सकती है, जिसमें पुरुषों की संपत्ति या पुरुषों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु के रूप में उनकी अधीनता और इस तरह के व्यवहार के साथ संबंधित भेदभाव, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह शामिल हैं।

> स्त्री–हत्या को परिभाषित करना और उसकी पहचान करना

स्त्री–हत्या को परिभाषित करने के दो दृष्टिकोण हैं ''सभी महिलाओं और लड़कियों की हत्याएं'' या ''अंतरंग साथी स्त्री–हत्या'' जो वर्तमानध्पूर्व पुरुष साथियों द्वारा हत्या की गयीं महिलाओं को समेटती हैं। ये दृष्टिकोण आसान पहचान की अनुमति देते हैं लेकिन एक जटिल घटना को समझने के लिए केवल सेक्स/लिंग और या पीड़ित–अपराधी संबंधों पर विचार करने की अति सरलता होने के लिए इनकी आलोचना की जाती है। महिला और पुरुष हत्या में अंतर करने वाले अतिरिक्त कारकों की पहचान करने के लिए, हमने पुरुष अपराधी/महिला पीड़ित नर–हत्या की तुलना की, जो कि स्त्री–हत्या के साथ सबसे अधिक किसी भी अन्य सेक्स/लिंग संयोजनों से निकटता से मेल खाती है।

हमने पाया कि अन्य हत्याओं की तुलना में पुरुष–द्वारा–महिला हत्याओं में SGRMI अधिक आम थे, जिसका अर्थ है कि कम से कम कनाडा के संदर्भ में, स्त्री–हत्याएं अलग हैं, और ये सेक्स/लिंग या सम्बन्ध से परे हैं। अधिक सामान्य पूर्व–घटना विशेषताओं में पूर्व–पुलिस संपर्क, लंबित/वास्तविक अलगाव, पीड़ितों के खिलाफ पूर्व धमकियां, अंतरंग/पारिवारिक संबंध और पूर्वचिन्तन शामिल थे। अधिक सामान्य घटना कारकों में स्त्री–हत्या के उद्देश्य (जैसे, ईर्ष्या), यौन हिंसा, अंग–भंग, अत्यधिक बल, और पीड़ितों को नग्न/आंशिक रूप से नग्न छोड़ देना सम्मिलित हैं। पुरुष–द्वारा –महिला हत्याओं में SGRMI की औसत संख्या औसतन काफी अधिक थी।

> महत्वपूर्ण डाटा अंतराल

प्रमुख चरों के लिए डाटा अक्सर गायब था, जिसने अधिक ठोस निष्कर्षों को रोका है और रोकथाम के लिए अनुसंधान की क्षमता को कम किया। जहाँ कुछ मामलों के लिए जानकारी उपलब्ध थी, कुल नमूने और सेक्स/लिंग संयोजन के लिए संगतता कमजोर थी। पुरुष–द्वारा–महिला हत्याओं के लिए, नामौजूद डाटा पीड़ित की उम्र के लिए कम से कम 3% से लेकर बाल शोषण के अपराध ी इतिहास के लिए 96% के उच्च स्तर तक था। कुछ चरों के लिए न्यूनतम सूचना की उम्मीद की गई थी, लेकिन स्त्री–हत्या के लिए उनकी प्रासंगिकता को देखते हुए एसजीआरएमआई के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, अलगाव के एक अच्छी तरह से प्रलेखित जोखिम कारक होने के बावजूद, 66 प्रतिशत मामलों में सूचना गायब थी। इसके अलावा, अन्य संयोजनों की तुलना में पुरुष–द्वारा–महिला हत्याओं में यौन हिंसा में गहन संभावना के बावजूद, अधिक गायब थी। पूर्व–घटना संकेतकों की तुलना में घटना संकेतकों के लिए अनुपलब्ध डाटा कम था।

हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महिलाओं और लड़कियों के सेक्स/लिंग–संबंधी हत्याओं का नाम और भेद करने के लिए ''स्त्री हत्या'' का उपयोग करना महत्वपूर्ण है –यही कारण है कि हम अपने शोध, शिक्षा और जागरूकता प्रयासों में *#CallItFemicide* का उपयोग करते हैं। हम एक सामाजिक समस्या का समाधान तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी पहचान नहीं करते हैं कि वह क्या है और उसका नाम क्या है; हालांकि, हम यह भी तर्क देते हैं कि हमें सेक्स/लिंग–आधारित तत्वों की पहचान करने और उन्हें लगातार मापने की आवश्यकता है। विश्वसनीय डाटा की कमी के कारण कुछ अनुभवजन्य अध्ययन इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। हमारा शोध अपने मूलभूत और नारी–हत्या पर चल रहे फोकस और कई आधिकारिक/अनौपचारिक डाटा स्रोतों से जानकारी के त्रिकोणासन के लिए अनूठा था। इस प्रकार, पहचाने गए डाटा अंतराल के व्यापक निहितार्थ और भी अधिक चिंताजनक हैं: डाटा जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को लक्षित करने वाली सूचित रोकथाम पहल के विकास को बढ़ा सकते हैं, वे राज्यों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा नियमित रूप से एकत्र नहीं किए जा रहे हैं। ये डाटा पूर्वाग्रह महिलाओं और लड़कियों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, केवल प्रशासनिक जरूरतों के बजाय रोकथाम की डाटा संग्रह प्राथमिकता की तत्काल प्राथमिकता को अधोरेखांकित करते हैं। रोकथाम उपकरण के रूप में डाटा संग्रह को फिर से परिभाषित करना पुलिस जांच के बिंदु पर शुरू होना चाहिए जो बेहतर समग्र–स्तरीय डाटा में फीड होगा, लेकिन इसके लिए

>>

''जांच का ध्यान महिलाओं की हत्या को समझने के लिए महत्वपूर्ण संबंधों के संदर्भों और आसपास की परिस्थितियों के बजाय घटनाओं पर रहता है''

अनुसंधान, समुदायों और सरकार में मजबूत और स्थायी सहयोग की आवश्यकता है।

कानून और शासित निकाय अनुसंधान करने के व्यवसाय में नहीं हैं; हालांकि, वे उन लोगों से सीख सकते हैं जो, साक्ष्य–आधारित डाटा की सुविधा प्रदान करते हैं (1) अधिक उपयुक्त सूचना एकत्र करकेय और (2) उन शोधकर्ताओं के लिए डाटा को सुलभ बनाकर जो हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रयासों के बावजूद, स्थानीय और विश्व स्तर पर, विशेष रूप से दुनिया के कुछ क्षेत्रों (जैसे, दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका) और महिलाओं और लड़कियों के कुछ समूहों (जैसे, स्वदेशी, अप्रवासी और शरणार्थी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, विकलांग महिलाएं) की डाटा तक पहुंच मुश्किल है। कई देशों के लिए, बुनियादी डाटा संग्रह सबसे अच्छी स्थिति है। ऐसा क्यों है कि, जब आम तौर पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ स्त्री–हत्या और पुरुष हिंसा को रोकने के लिए डाटा महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें व्यवस्थित और नियमित रूप से एकत्र नहीं किया जाता है?

> ''सार्वजनिक पितृसत्ता'' और डाटा संग्रह

हम तर्क देते हैं कि एक प्रमुख योगदानकर्ता पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं का ऐतिहासिक और चल रहा प्रभाव है, जिसमें ऐतिहासिक और समकालीन निर्णय निर्माताओं की भूमिका शामिल है, जिनके लिए इन आंकड़ों का संग्रह किया जाता था और इसे प्रथमिकता के रूप में नहीं देखा जाता था। ये निर्णय लेने वाले, यह तय करते हुए कि डेटा का उपयोग कौन और कैसे करेगा, इन आंकड़ों के द्वारपाल के रूप में कार्य करना जारी रखे हैं। उदाहरण के लिए, आपराधिक न्याय प्रणाली एक पितृसत्तात्मक, पारंपरिक रूप से मर्दानी संस्था है; पुलिस जांच और अभियोजन के लिए डाटा की रिकॉर्डिंग इस तथ्य को दर्शाती है। नारीवादी अनुसंधान द्वारा स्त्री हत्या में पीड़ितों और अपराधियों के बीच संबंधों को समझने के महत्व को प्रदर्शित करने के बावजूद, हमारे अध्ययन से पता चला है कि खोजी फोकस – जैसा कि उपलब्ध आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है– स्त्री–हत्या को समझने के लिए महत्वपूर्ण, संबंधों के संदर्भों और आसपास की परिस्थितियों के बजाय घटनाओं पर रहता है।

इस ''सार्वजनिक पितृसत्ता'' और संबंधित निर्णयों के चल रहे प्रभाव, सेक्सधलिंग डेटा पूर्वाग्रह उत्पन्न करते हैं, चाहे इच्छित अथवा नहीं, वे महिलाओं और लड़कियों को जोखिम में डालते हैं, क्योंकि डाटा मुख्य रूप से पुरुषों पर आधारित या उनके द्वारा उत्पन्न किया गया है। पुरुष–पुरुष हत्या के मामलों को पकड़ने के लिए शुरू में डिजाइन किए गए डाटा संग्रह उपकरण महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ पुरुष हिंसा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण डाटा के संग्रह को रोकते हैं। यदि हम स्त्री–हत्या का विश्वसनीय दस्तावेजीकरण नहीं कर सकते हैं, तो महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध पुरुष हिंसा के अन्य रूपों का दस्तावेजीकरण करने की क्या आशा है? हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि राज्य और सार्वजनिक रूप से नारी हत्या को जांच के योग्य घटना के रूप में मान्यता न दी जाए। इसके लिए ''योग्य विषयों'' के मजबूत पदानुक्रम को चुनौती देने की आवश्यकता है, जो अक्सर महिलाओं और लड़कियों के अत्याचार को अदृश्य और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के कुछ समूहों को छोड़ देता है। ■

सभी पत्राचार मयर्ना डॉसन को <mdawson@uoguelph.ca> पर प्रेषित करें।

इस विषय पर लेखक द्वारा एक लम्बा आलेख अंग्रेजी में यहाँ और फ्रेंच में यहाँ उपलब्ध है।

> अमेरिकी राजनीति में नस्लवाद और पर्यावरण–विरोधीवाद

इयान कैरिलो, ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका, और अर्थव्यवस्था और समाज पर आईएसए अनुसंधान समिति के सदस्य (आरसी 02) द्वारा

वेस्ट वर्जीनिया के पोका में जॉन ई. अमोस कोल पावर प्लांट की छाया में कंपनी का शहर।
श्रेयः विगवाम जोन्स, CC BY-NC-ND 2.0.

संयुक्त राज्य अमेरिका में, नस्लवाद और श्वेत वर्चस्व सामूहिक कार्यवाही की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रीय बाधाएं बने हुए हैं, साथ ही पर्यावरण अन्याय और जलवायु परिवर्तन समाज की भलाई के लिए सबसे अधिक दबाव वाले संकट हैं। *करंट सोशियोलॉजी* में हाल ही में प्रकाशित मेरे आलेख ''द रेशियल फिक्स एंड एनवायर्नमेंटल स्टेट फॉर्मेशन'' में, मैंने अमेरिकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में नस्लवाद और पर्यावरण–विरोधीवाद के मध्य संबंधों पर विस्तार से चर्चा की है। मेरा तर्क है कि नस्लीय राजनीति उस राजनीतिक अर्थव्यवस्था का केंद्र है जिसमें पर्यावरण नीति बनाई जाती है।

इस राजनीतिक अर्थव्यवस्था में नस्लवाद और पर्यावरण–विरोधीवाद को एक साथ बांधना, जिसे मैं ''नस्लीय सुधार'' कहती हूं, इस विचार को संदर्भित करता है कि जाति और नस्लवाद उन ताकतों को रोकने के लिए तंत्र हैं जो पारिस्थितिक विनाश को धीमा या उलट सकते हैं। विशेष रूप से, उद्योग और सरकार में अभिजात वर्ग नस्लवाद का उपयोग सामाजिक विभाजन को बोने के लिए और किसी भी सामूहिक लामबंदी जो उनकी शक्ति और लाभ के लक्ष्य को खतरा है, को कमजोर करने के लिए करता है।

> नस्लीय सुधार के स्थानिक आयाम

अमेरिका में, नस्लीय सुधार तीन प्रमुख तरीकों से संचालित होता है। पहला स्थानिक है, नस्ल और स्थान के मध्य संबंधों में यह निर्धारित करना कि पर्यावरणीय बोझ उठाने के लिए कौन सी आबादी को लक्षित किया जाना है। अमरीका में नस्ल किस प्रकार इस बात को प्रभावित करती है कि कौन इसे आबाद करेगा और अमेरिका में लोग कहां रहते हैं, ये प्रश्न मौलिक हैं। आप्रवास नीतियों ने ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय आबादी का पक्ष लिया और जानबूझकर अमेरिका में स्थायी श्वेत बहुमत हासिल करने का प्रयास किया। नगरीय, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक और समकालीन नस्लीय पृथक्करण का मतलब है कि आवासीय पैटर्न नस्लीय हैं और ये जारी रहेंगे।

आवासीय पृथकवाद और अप्रवास को आकार देने वाले नस्लवाद का पर्यावरणीय न्याय पर प्रभाव पड़ता है। रंग के आधार पर पृथक समुदाय अवांछित अपशिष्ट भंडारण और अन्य खतरनाक गतिविधियों के लिए स्थान बन जाते हैं, क्योंकि श्वेत–बहुसंख्यक आबादी स्वच्छ पर्यावरणीय सुविधाओं का आनंद लेती है। इस बीच,

> >

श्वेत बहुसंख्यकवाद रंग के समुदायों को पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए लोकतांत्रिक साधनों का उपयोग करने से रोकता है।

> राजनीतिक के रूप में नस्लीय सुधार

नस्लीय सुधार की दूसरी विशेषता राजनीतिक है। अमेरिका में, लोकतांत्रिक संस्थाएं श्वेत आबादी को लाभ और रंग की आबादी को नुकसान पहुंचाती हैं। यह अमेरिकी राजनीतिक विकास में नस्लवाद के लंबे समय तक उलझे रहने और अमेरिकी राजनीति में समकालीन बदलाव के कारण है। उदाहरण के लिए, इलेक्टोरल कॉलेज –जिसके सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं – की स्थापना दास बनाने वाले और दास उद्योग के हितों को संरक्षित और लोकप्रिय लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रतिबंधित करने के लिए की गई थी। 1965 में ही अमेरिका नस्लीय रूप से समावेशी लोकतंत्र बना, लेकिन तब से नस्लवादी राजनेताओं ने रंग के लोगों के राजनीतिक अधिकारों को सीमित करने के लगातार प्रयास किये है। ये राजनेता बड़े पैमाने पर बंदीकरण की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं जो रंग के लोगों को कैद और बेदखल करती हैं, और साथ ही इस जातिवादी मिथक के आधार पर मतदाता दमन कानून भी पारित करते हैं कि रंग के लोग और अप्रवासी मतदाता धोखाधड़ी में संलग्न होते हैं। संरचनात्मक स्तर पर, राजनीतिक संस्थानों में अभी भी श्वेत–समर्थक पूर्वाग्रह है। श्वेत (विशेषकर ग्रामीण) मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताएं प्रतिनिधि सभा, सीनेट, इलेक्टोरल कॉलेज और सुप्रीम कोर्ट में अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं –जिनके न्यायाधीश सीनेटरों और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन श्वेत संरचनात्मक लाभों के परिणाम सुस्पष्ट हैं: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम को खारिज कर दिया है, कांग्रेसी जिले रूढ़िवादी श्वेत मतदाताओं के पक्ष में झुकाने के लिए अधिकाधिक कार्य करते हैं, और राज्य विधानसभाओं में लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस जूझ रही है।

नस्लीय सुधार का राजनीतिक पहलू पर्यावरण नीति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश जातिवादी राजनेता पर्यावरण विरोधी विचार भी रखते हैं। इस संयुक्त दृष्टिकोण में, नस्लवाद सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण को रोकने का एक उपकरण है जैसे एक न्यायोचित और स्थिर वातावरण। यह ''डॉग–विस्सल'' राजनीति के समरूप है, जहां राजनेता रंग के लोगों को डराने और सरकारी कार्यक्रमों को अवैध बनाने के लिए नस्लीय कोडित भाषा का उपयोग करते हैं। जहाँ डॉग–विस्सल की राजनीति, शुरू में कल्याणकारी नीतियों पर केंद्रित थी, इस तरह के नस्लीय निर्धारण को अंततः पर्यावरण नीति निर्माण के क्षेत्र में विस्तारित किया गया था। इस तरह पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नस्लीय नाराजगी और शत्रुता रूढ़िवादी राजनेताओं और न्यायाधीशों, जिनके विचारों का संरचनात्मक रूप से अमेरिकी राजनीती में अधिक प्रतिधिनित्व है, के दृष्टिकोणों से अतिच्छादित थी।

> नस्लीय पहचान की राजनीति और व्यक्तिगत मनोविज्ञान

नस्लीय सुधार की तीसरी विशेषता में नस्लीय पहचान की राजनीति और व्यक्तिगत मनोविज्ञान के मध्य संबंध शामिल हैं। यह संबंध पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के लिए सरकारी कार्यक्रमों की सार्वजनिक धारणाओं को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले दो दशकों में कई प्रवृत्तियों ने श्वेत पहचान की राजनीति और पर्यावरण विरोधी दृष्टिकोण के मध्य संबंध को मजबूत किया है। सबसे पहले, बराक ओबामा के 2008 के चुनाव के बाद, रूढ़िवादी नेताओं और राजनेताओं ने ओबामा को जातीय–नस्लीय, धार्मिक और विदेशी ''अन्य'' के रूप में ब्रांड करके उनकी नीतियों को अवैध बनाने का काम किया। इन प्रयासों ने नस्लीय रूप से श्वेत मतदाताओं को न केवल वहनीय स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, बल्कि पेरिस जलवायु समझौते और अधिक व्यापक रूप से पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, रूढ़िवादी नेताओं ने बदलती जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों, जिनमें श्वेतों को अब आबादी का बहुमत नहीं होने का अनुमान बताया गया था, को स्थानांतरित करने से संबंधित श्वेत नस्लीय चिंता और बढ़ावा दिया। इस नस्लीय खतरे ने श्वेत पहचान की राजनीति और पर्यावरण विरोधी दृष्टिकोण के बीच संबंधों को और मजबूत किया। उदाहरण के लिए, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे प्रमुख पर्यावरण–विरोधी राजनेताओं ने स्वदेशवाद, नस्लवाद और ''श्वेत प्रतिस्थापन'' की आशंकाओं की लपटों को भड़काकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त की। ये नस्लवादी प्रयास भय और समूह के खतरे के इर्द–गिर्द मूल भावनाओं को गहराई से अपील करते हैं, इस प्रकार व्यक्तिगत मनोविज्ञान को एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं जो पर्यावरण और जलवायु समस्याओं को हल नहीं करने के लिए उन्मुख है।

इस राजनीतिक अर्थव्यवस्था के केंद्र में उद्योग और सरकार में कुलीन वर्ग हैं जो पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को जन्म देने की क्षमता वाली किसी भी सामूहिक कार्रवाई को रोकने के लिए नस्ल और नस्लवाद का उपयोग करते हैं। इस संभ्रांत रणनीति का अमेरिका में एक लंबा इतिहास रहा है। उदाहरण के लिए, बेकन के विद्रोह– 1676 में बहु–नस्लीय श्रमिक विद्रोह–के बाद अभिजात वर्ग ने श्वेत और अश्वेत श्रमिकों को विभाजित करने वाले नस्लीय कानून बनाए, जिससे भविष्य में क्रॉस–नस्लीय श्रमिक एकजुटता के लिए बाधाएं पैदा उत्पन्न हों। दुर्भाग्य से पर्यावरण और जलवायु अन्याय को कायम रखने के लिए अभिजात वर्ग आज भी इस विभाजित करो और जीतो प्लेबुक का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं को नष्ट करने वाली पिछली कुलीन परियोजनाओं की तरह, इन प्रयासों ने रंग के लोगों को सबसे पहले और गहरी चोट पहुंचे है, लेकिन अंततः ये श्वेत लोगों के जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरणीय अन्याय और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली पृथ्वी की अस्थिरता इस बात का उदाहरण है कि श्वेत वर्चस्व अपनी भौतिक परिस्थितियों को कैसे कमजोर करता है और अपने ही समर्थकों के लिए नरभक्षी बन जाता है। भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थिर पर्यावरण और जलवायु को संरक्षित करने के लिए, नस्लीय सुधार को बेअसर करना, घायल रंग के समुदायों को ठीक करना और पुनर्स्थापित करना और नस्लीय एवं वर्ग न्याय पर आधारित मजबूत जलवायु और पर्यावरण कार्यक्रमों को स्थापित करना आवश्यक है। ■

सभी पत्राचार इयान कैरिलो को <icarrillo@ou.edu> पर प्रेषित करें।